

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
दिसंबर 2015
(अंक बारह)



वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक बारह



भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2015

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में <http://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

कृपया इसके संबंध में प्रतिक्रिया fsu@rbi.org.in को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, गिरगांव मार्ग, मुरलीधर मंदिर कम्पाउन्ड,
ठाकुरद्वार पोस्ट-ऑफिस के पास, मुंबई 400 002 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

प्रस्तावना

वैश्विक वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से 2015 अत्यधिक घटनापूर्ण वर्ष रहा है और संपूर्ण अटलांटिकक्षेत्र में नीतिगत बदलावों के लिए मंच तैयार हो चुका है। हाल ही में, फेडरल रिजर्व द्वारा निधि दरों में वृद्धि और चीन में हुई गतिविधियों के कारण वैश्विक विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए घरेलू नीतियों का नपे-तुले तरीके से निर्धारण करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। वैसे भी, संपूर्ण विश्व में वित्तीय स्थिरता के निगहबानों के लिए अनिश्चितता भरे 'उतार-चढ़ाव' का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती है। प्रमुख उन्नत और उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर वृद्धि की संभावनाओं से जुड़े हुए जोखिमों के साथ ही वित्तीय बाजारों की कठिन स्थितियों तथा पण्यों के कमजोर मूल्य के कारण कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवेकपूर्ण नीतिगत उपायों तथा पण्य मूल्यों के कमजोर होने के संयुक्त प्रभावों के कारण उभरते हुए बाजारों वाली अपनी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर प्रतीत होती है, किंतु उभरते जोखिमों से निपटने की तैयारी के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके संबंध में हमें ध्यान देने की जरूरत है।

प्रथम मुद्दा, कारपोरेट क्षेत्र की असुरक्षितता और उनके कमजोर तुलन-पत्र का वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का है जिसकी गहनता पूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है।

द्वितीय, सायबर सुरक्षा प्रमुख चुनौती होगी, यह मात्र परिचालनगत चिंता से कहीं अधिक रणनीतिक मुद्दा है, जिसके लिए बोर्ड स्तर पर खतरों को समझने और समाधान निकालने की जरूरत होगी।

तृतीय, घरेलू मुद्रास्फीति में काफी कमी आने के बावजूद हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जलवायु की परिस्थितियों में अधिक अनियमित तथा अप्रत्याशित होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसका असर मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव और शायद इसके स्तर पर भी पड़ेगा।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली में मौजूद सुदृढ़ता और समुत्थान-शक्ति का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए वित्तीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालती है तथा वास्तविक क्षेत्र को अधिक प्रभावी ढंग से सहारा प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रणाली के आगे बढ़ने की दिशा का संकेत भी देती है।

रघुराम जी. राजन
गवर्नर

23 दिसंबर, 2015



विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	
संक्षेपाक्षरों की सूची	i-iii
विहगावलोकन	1
अध्याय I: समष्टि वित्तीय जोखिम	3-15
वैश्विक पृष्ठभूमि	3
स्वदेशी समष्टि आर्थिक चुनौतियाँ	7
कॉरपोरेट क्षेत्र	10
अध्याय II: वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और लचीलापन	16-40
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	16
निष्पादन	16
लचीलापन - दबाव परीक्षण	21
जोखिम	32
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	33
निष्पादन	33
लचीलापन - दबाव परीक्षण	33
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों	34
निष्पादन	34
लचीलापन - दबाव परीक्षण	35
परस्पर संबद्धता	35
अध्याय III: वित्तीय क्षेत्र विनियमन	41-62
अंतरराष्ट्रीय विनियामक सुधार की कार्यसूची	41
घरेलू वित्तीय प्रणाली	43
बैंकिंग क्षेत्र	43
वित्तीय समावेशन	51
प्रतिभूति बाजार	52
बीमा क्षेत्र	56
पेंशन क्षेत्र	57
वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था: जमाराशि बीमा	59
वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर	60
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	62
अनुबंध-1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	63
अनुबंध 2: कार्यप्रणालियां	67

बॉक्सों की सूची

1.1	प्राचीन ज्ञान की तलाश में	4
2.1	इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों पर आधारित प्रणालीगत जोखिम की माप	40
3.1	‘परिवर्तनकारिता’ (डिसरप्टिव प्रभाव) - ‘ब्लॉक श्रृंखला’ प्रौद्योगिकी	42
3.2	आस्ति-गुणवत्ता के संबंध में हाल में की गई विनियामकीय पहल	44
3.3	भारतीय बैंकों द्वारा इंड ए एस 109 के कार्यान्वयन से पड़ने वाले कतिपय प्रमुख प्रभाव	46
3.4	भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक	52
3.5	स्टार्ट-अप्स द्वारा निधि जुटाने के लिए सेबी का ढांचा	55

चार्ट की सूची

1.1	आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना	5
1.2	विश्व भुगतानों में विभिन्न मुद्राओं का अंश	5
1.3	व्यापारिक हानि और स्फीतिकारी दबावों की स्थितियाँ	5
1.4	वैश्विक जीडीपी संवृद्धि और ईएमडीई-ईई संवृद्धि में अंतराल	6
1.5	उभरते बाजारों में कॉरपोरेट अर्जन और विश्व व्यापार की मात्रा में संवृद्धि	6
1.6	चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतक	7
1.7	ईएम मुद्राओं में मूल्यहास - टेपर टेन्ट्रम बनाम - मई-नवंबर, 2015	7
1.8	पूंजी खाता और बेहतर राजकोषीय दायरे में योजनागत व्यय	7
1.9	उपभोग में गिरावट	8
1.10	कृषि निर्यात और वैश्विक पण्यों के मूल्य	8
1.11	निर्यात और आयात की प्रवृत्तियाँ	8
1.12	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर और 3 माह का गतिमान औसत	9
1.13	चालू खाता, पूंजी खाता और निजी अंतरण	9
1.14	अल्पावधि बाह्य ऋण स्टॉक और परिवर्तनशील पूंजी प्रवाह	9
1.15	विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधि बाह्य ऋण का अनुपात - भिन्न देशों के बीच तुलना	10
1.16	विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में परिवर्तनशील पूंजी प्रवाह का अनुपात - भिन्न देशों के बीच तुलना	10
1.17	सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन	10
1.18	सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियाँ: कमजोर कंपनियाँ - वर्तमान प्रवृत्ति (2013-14 से 2015-16)	12
1.19	चुनिंदा उद्योगों के जोखिम प्रोफाइल	12
1.20	कॉरपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक: आकार के अनुसार वर्गीकरण	13
1.21	कमजोर एनजीएनएफ कंपनियाँ	14
2.1	ऋण और जमाराशि में वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष आधार पर	16
2.2	कुल ऋण में ऋण का क्षेत्रगत हिस्सा	17
2.3	पूंजी पर्याप्तता	17

	पृष्ठ सं.
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लीवरेज अनुपात	17
2.5 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	18
2.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनएनपीए	18
2.7 दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात आधारित एससीबी का वितरण	18
2.8 व्यापक क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम	18
2.9 दबावग्रस्त क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम	19
2.10 बड़े उधारकर्ताओं के जीएनपीए अनुपात	19
2.11 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) आधारित एससीबी का वितरण (वार्षिकीकृत)	20
2.12 प्रणालीगत स्तर पर एससीबी के जीएनपीए तथा सीआरएआर का अनुमान	21
2.13 बैंक-समूह वार जीएनपीए अनुपात एवं सीआरएआर के अनुमान	22
2.14 विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए	22
2.15 संभावित हानियां : बैंक समूह-वार	23
2.16 अप्रत्याशित हानि और प्रत्याशित कमियां : बैंक-समूह वार	23
2.17 प्रत्याशित हानियां तथा अप्रत्याशित हानियां : बैंक-वार	24
2.18 सीआरएआर के अनुसार बैंकों का वितरण	25
2.19 ऋण सकेन्द्रण जोखिम - वैयक्तिक उधारकर्ता	26
2.20 एससीबी की तुलन-पत्र से इतर आस्तियों का हिस्सा (ऋण समतुल्य)	31
2.21 कुल व्युत्पन्नियों के एमटीएम	32
2.22 दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी संविभागों पर आघातों का असर	32
2.23 बैंकिंग स्थिरता सूचक	33
2.24 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	33
2.25 एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता	34
2.26 एनबीएफसी क्षेत्र का सीआरएआर	35
2.27 अंतरबैंक बाजार का आकार	35
2.28 अंतरबैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा	36
2.29 अंतरबैंक बाजार में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित लेनदेन	36
2.30 अल्पावधि एवं दीर्घावधि अंतरबैंक बाजार (निधि आधारित)	36
2.31 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना	37
2.32 भारतीय वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट	38
3.1 कॉरपोरेट ऋण और कमर्शियल पेपर के बकाया निर्गम	43
3.2 बैंक-समूहवार निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) की प्रवृत्ति	45
3.3 कुल आस्तियों और एआरसी की स्वाधिकृत निधि की प्रवृत्ति	45
3.4 एआरसी द्वारा अभिग्रहीत आस्तियों की प्रवृत्ति	46
3.5 भारतीय कंपनियों के कर्ज, पूंजी व्यय और आमदनी	47

	पृष्ठ सं.
3.6 एचएचआई 1 सिस्टम स्तर पर (समस्त एससीबी)	48
3.7 एनपीए एवं ऋणों के बीच एचएचआई के अंतर का बैंक-वार वितरण	48
3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सरकार को प्राप्त लाभांश और उनके द्वारा बैंकों में पूंजी डालना	50
3.9 बीएसबीडी खातों में रुझान	51
3.10 बीसी-आईसीटी लेनदेनों और कीमत संबंधी रुझान	51
3.11 डीआईआई और एफपीआई द्वारा इक्विटी में निवल निवेश	53
3.12 एफपीआई और डीआईआई की खरीदारी/बिकवाली रुझानों का दिन-वार ब्रेक-अप	53
3.13 पूंजी बाजारों में बीमा कंपनियों के निवेश की तुलनात्मक स्थिति	57
3.14 राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ग्राहकी और प्रबंधनाधीन आस्तियों में रुझान	58
3.15 2015 के दौरान रिपोर्ट की गई 'घटनाओं' की संख्या में रुझान	62

सारणियों की सूची

1.1 सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के कार्य-निष्पादन के चुनिंदा वित्तीय अनुपात (2014-15 और 2015-16)	11
1.2 सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियां: कॉरपोरेट लीवरेज में सामान्यतर जोखिम	11
1.3 बैंक ऋण के संबंध में एनजीएनएफ कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता में कमजोरी का प्रभाव	15
2.1 एससीबी का बड़े उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर	20
2.2 एससीबी की लाभप्रदता	20
2.3 समष्टि आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत मान्यताएं	21
2.4 ऋण जोखिम - आघात और असर	25
2.5 ऋण संकेद्रण जोखिम: समूह उधारकर्ता	26
2.6 क्षेत्रगत ऋण जोखिम : उद्योग - आघात एवं असर	27
2.7 क्षेत्रगत ऋण जोखिम : आधारभूत संरचना - आघात एवं असर	28
2.8 क्षेत्रगत ऋण जोखिम : चुनिंदा उद्योग	29
2.9 ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात एवं असर	30
2.10 चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर (सीएलआर एवं एसएलआर निधियों का प्रयोग करते हुए)	30
2.11 चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर (एसएलआर निधियों का प्रयोग करते हुए)	31
2.12 एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन-पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	34
2.13 एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन	34
2.14 बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता सांख्यिकी	37
2.15 विभिन्न समूहों की अंतर-क्षेत्र आस्तियां और देयताएं	38
2.16 बैंकों में बीमा कंपनियों के एक्सपोजर का पैटर्न	38
2.17 एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों का एक्सपोजर	39
2.18 निवल उधारकर्ता बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई संक्रामकता	39
2.19 निवल उधारदाता बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई संक्रामकता	39
3.1 कॉरपोरेट बॉण्डों में म्यूच्युअल फंडों का एक्सपोजर	54

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीआरआर	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात
एएमसी	आस्ति प्रबंध कंपनी	सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण	डीबीआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस
एपीवाई	अटल पेंशन योजना	डीसीसीओ	वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ की तिथि
एआरसी	आस्ति पुनर्चना कंपनी	डीईआर	इक्विटी अनुपात की तुलना में ऋण
एएसईएएन	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ	डीएफआई	घरेलू वित्तीय संस्थान
एएसटीआरओआईडी	रुपये ओटीसी ब्याज दर व्युत्पन्नी व्यापार के लिए नाम रहित प्रणाली	डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	डीआईआई	घरेलू वित्तीय निवेशक
बीसी/डीआर	कारोबार निरंतरता/आपदा उद्धार	डीपीएस	विभेदक प्रीमियम प्रणाली
बीसी-आईसीटी	कारोबार प्रतिनिधि- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	डीआर	आपदा उद्धार
बीसीपी	कारोबार निरंतरता योजना	ईबीआईटी	ब्याज, कर से पूर्व आमदनी
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यहास तथा परिशोधन से पूर्व आमदनी
बीओजे	बैंक ऑफ जापान	ईबीपीटी	प्रावधान और कर के पूर्व आमदनी
बीपीएस	आधार अंक	ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
बीएसबीडीए	साधारण बचत बैंक जमा खाता	ईसीएल	प्रत्याशित ऋण हानि
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर
सीएडी	चालू खाता घाटा	ईएल	अपेक्षित हानि
सीएपी	सुधारात्मक कार्रवाई योजना	ईएम	उभरते बाजार
सीबीएस	कोर बैंकिंग सुविधा	ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	ईपीएस	प्रति शेयर अर्जन
सीडीओ	संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्व	ईएस	अपेक्षित कमी
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफएएलएलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी करार	एएफएटीसीए	विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम
सीईआरटी-इन	कंप्यूटर आपातकालीन सहायता दल-भारत	एफबी	विदेशी बैंक
सीएफटीसी	पण्य वायदा व्यापार आयोग	एफडीआईसी	फेडरल जमा बीमा निगम
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर	एफईडी	अमरीकी फेडरल रिजर्व
सीओएफईआर	आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार का करेंसी संगठन	एफईआर	विदेशी मुद्रा भंडार
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
सीपीएमआई	भुगतान और बाजार बुनियादी संरचना समिति	एफआई	वित्तीय संस्थान
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	एफएमसी	वायदा बाजार आयोग
		एफएमआई	वित्तीय बाजार मूलभूत व्यवस्थाएं
		एफपीआई	विदेशी संविभाग निवेश

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड	केपीआई	मूल कार्यनिष्पादन सूचकांक
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	एलईआई	विधिक संस्था पहचानकर्ता
एफवीओसीआई	कतिपय वित्तीय लिखतों पर उचित मूल्य परिवर्तन	एलईआईएल	भारतीय विधिक संस्था निर्धारक लिमिटेड
एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एफवाई	वित्तीय वर्ष	एलओयू	स्थानीय परिचालक यूनित
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद	एमसीए	कंपनी कार्य मंत्रालय
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एमसीसीआईएल	भारतीय महानगरीय समाशोधन निगम
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम	एमएफ	पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)
जीएसटी	माल और सेवा कर	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
जीवीए	योजित सकल मूल्य	एमएमएमएफ	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित	एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एचएचइडेक्स	हर्फिन्डाल-हर्शमैन सूचकांक	एमआरसी	न्यूनतम अपेक्षित निधि
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां	एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
आईएडीआई	जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	एमयूडीआरए	सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी
आईबी-सीएआरटी	जोखिम और खतरे का विश्लेषण करने के लिए भारतीय बैंकों का केंद्र	एमएक्सईएफ	एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक
आईसीसीएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आईसीआर	ब्याज कवरेज अनुपात	एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
आईडीएफ	बुनियादी ढांचा कर्ज निधि	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान	एनबीएफसी-डी	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	एनबीएफसी-एनडी	जमाराशि स्वीकार न करनेवाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
आईएफएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार न करनेवाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
आईएनडीएस	भारतीय लेखा मानक	एनजीएनएफ	गैर-सरकारी गैर- वित्तीय
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईआरडीआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एनआईआई	गैर संस्थागत निवेशक
आईआरएस	ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)	एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एनएनपीए	निवल अनर्जक अग्रिम
आईटीपी	संस्थागत व्यापार प्लेटफार्म	एनपीए	अनर्जक अग्रिम
जेएलएफ	संयुक्त उधारदाता मंच	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
जेएलएफ-ईजी	संयुक्त उधारदाता मंच - सशक्त समूह	एनआरआई	अनिवासी भारतीय

एनएससीसीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड	आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आरओसी	विनियामक निगरानी समिति
ओआरएम	परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन	आरओई	इक्विटी पर प्रतिफल
ओटीसी	काउंटर पर	आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
पी/ई	मूल्य अर्जित अनुपात	एसएएफई	विदेशी विनियमन का राज्य प्रशासन
पीएटी	कर पश्चात लाभ	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीबीटी	कर पूर्व लाभ	एसडी	मानक विचलन
पीडी	चूक की संभाव्यता	एसडीआर	कार्यनीतिक ऋण पुनर्चना
पीएफ	भविष्य निधि	एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
पीएफसीई	निजी अंतिम खपत व्यय	एसईबीआई (सेबी)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
पीएफएमआई	वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा के सिद्धांत	एसएफबी	लघु वित्त बैंक
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	एसआइडीबीआइ (सिडबी)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पीएमजेडीवाई	प्रधान मंत्री जन धन योजना	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
पीओपी	उपस्थिति स्थल/बिंदु	एसएसजी	वरिष्ठ पर्यवेक्षक समूह
पीपीआई	पूर्वदत्त भुगतान लिखत	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट)	विश्वव्यापी अंतर - बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
पीवीपी	भुगतान बनाम भुगतान	यूडीएवाई	उज्वल डिस्कॉम एश्यूरेंस योजना
क्यूई	मात्रात्मक सहजता	यूएल	अप्रत्याशित हानि
क्यूआईबी	अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता	वीएपीटी	असुरक्षितता मूल्यांकन और अर्तव्यापन परीक्षण
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक	वाई-ओ-वाई	वर्ष-दर-वर्ष
आरबीपी	जोखिम आधारित प्रीमियम		



विहगावलोकन

समष्टिगत-वित्तीय जोखिम

विश्व अर्थव्यवस्था और बाज़ार

जहां, वर्ष 2006 के बाद पहली बार फेडरल रिजर्व द्वारा नीति दर में वृद्धि करने का प्रभाव बाजारों द्वारा समाहित कर लिया जाना प्रतीत होता है, वहीं नीति दर में आगे की जाने वाली वृद्धि की गति बाजार के व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ-साथ चीन में हुई गतिविधियां और वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि, आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करेगी।

घरेलू समष्टिगत-आर्थिक चुनौतियां

समष्टि स्तर पर आर्थिक मौलिक सिद्धांतों में सुधार के बावजूद घरेलू मांग एवं निजी निवेश में धीमापन बने रहने से यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी निवेश को बढ़ाया जाए, वह भी ऐसे समय में जब सरकार राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध है। बाह्य मांग की कमजोरियों ने निर्यात को बुरी तरह से प्रभावित किया है, यद्यपि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा एक सहज स्तर पर बना हुआ है। जहां अल्पकालिक कर्ज का अनुपात तथा विदेशी मुद्रा भंडार में अस्थिर पूंजी के प्रवाह में एक संतुलन पैदा होने लगा है, वहीं ऐसी स्थिति में चालू खाता घाटे को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से पूंजी के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधार करने, स्पष्ट नीतिगत रुझान अपनाने खासतौर से कर संबंधी मामलों में तथा कारोबार करने में आसानी पैदा करने पर जोर देने की आवश्यकता है। कारपोरेट क्षेत्र में घटता हुआ लाभ, उच्च लीवरेज तथा कर्ज चुकाने की कम क्षमता क्षेत्र के सहवर्तियों सहित चिंता का विषय बनी रही है और इसका वित्तीय क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बावजूद इसके कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में मामूली सुधार पाया गया था।

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति

अनुसूचित वाणिज्य बैंक - निष्पादन और जोखिम

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कारोबार मंद पड़ गए हैं जो उनकी जमाशियों एवं ऋण-वृद्धि में गिरावट से स्पष्ट दिखाई देता है। मार्च और सितंबर, 2015 के बीच सकल अनर्जक अग्रिमों का

अनुपात(जीएनपीए) बढ़ गया था, जबकि पुनः वर्गीकृत मानक अग्रिमों का अनुपात घट गया था। जून 2015 तक के खंडवार आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उद्योग में दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात लगभग 19.5 प्रतिशत पर काफी ऊंचा बना हुआ है एवं उसके बाद सेवा-क्षेत्र में यह अनुपात 7 प्रतिशत है।

वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी की तुलना में जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक समूह में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर अभी तक सबसे कम रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता स्थिति और भी खराब हो गई है।

अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच स्थिति को देखें तो वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) दोनों की आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आई है।

बैंकिंग स्थिरता संकेतकों से पता चलता है कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन से लेकर अब तक बैंकिंग क्षेत्र के प्रति जोखिम और बढ़े हैं, जिसका मुख्य कारण आस्तियों की घटती हुई गुणवत्ता, सुदृढ़ता में कमी तथा लाभ में धीमापन रहा है।

अंतरसंबद्धता और जोखिम संक्रामकता

नेटवर्क विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अंतर-वित्तीय संस्था बाजार में म्यूचुअल फंड के बाद बीमा कंपनियां निधि उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं, जबकि निधि प्राप्त करने वाली संस्थाओं में एनबीएफसी के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंक सबसे अधिक निधि प्राप्त करते हैं। संक्रामकता विश्लेषण से पता चलता है कि यदि शीर्ष के वास्तविक उधारकर्ता बैंक फेल हो जाते हैं तो संयुक्त शोधन-क्षमता चलनिधि संक्रामकता के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली में 33.3 प्रतिशत की टियर-1 पूंजी का नुकसान हो सकता है, जबकि यदि शीर्ष के वास्तविक उधारदाता बैंक फेल हो जाते हैं तो उससे 35.1 प्रतिशत की टियर-1 पूंजी का नुकसान हो सकता है।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन

जहां विश्व स्तर पर रेगुलेटरी सुधार की कार्यसूची धीरे-धीरे लागू की जा रही है, वहीं विभिन्न संरचना वाली अर्थव्यवस्थाओं एवं विविध राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त क्षेत्रों

में इन सुधारों को लागू करने में लागत-लाभ मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। नई और अधिक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के आ जाने से जोखिम के मुख्य संचालक ऐसे क्षेत्रों में चले गए हैं जो रेगुलेटर्स के विवेक को निरंतर चुनौती देते रहेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र

जहां भारत में कारपोरेट ऋण बाजार को विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों के कुछ परिणाम दिखाई देने लगे हैं, वहीं बैंक से वित्त प्राप्त करने की निर्भरता बनी हुई है, भले ही बैंक खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंक आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता एवं पूंजी के स्तर को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हों। 'इंद्रधनुष' जैसी पहल के माध्यम से गवर्नेंस प्रक्रियाओं में सुधार लाने के अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने कारोबारी मॉडल की समीक्षा करने, तथा रणनीतिगत निर्णयों जैसे पूंजी की संरचना तथा लाभांश नीति का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

प्रतिभूति बाजार

भारतीय पूंजी बाजार विनियमन बदलते कारोबारी वातावरण की अपेक्षाओं के साथ कदम मिलाकर चला है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है ताकि कारोबार शुरू करने वाली कंपनियां आसानी से पूंजी बाजार तक पहुंच सकें। घरेलू संस्थागत निवेशक, खासतौर से म्यूचुअल फंड, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाहों की संभावित अस्थिरता के प्रति स्थिरता पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं। अक्टूबर, 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ फारवर्ड मार्केट कमीशन के विलय के फलस्वरूप व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि भारत में समस्त नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में जोखिम प्रबंधन ढांचे को समरूप बनाया जा सके तथा व्यवस्थित किया जा सके।

बीमा क्षेत्र

इन्श्योरेंस बिजनेस मॉडल के अंतर्गत बीमाकर्ता तथा पुनः बीमाकर्ता दोनों आते हैं जिसमें कुछ खास विशेषताएं हैं जो उसे बैंकिंग प्रणाली से अलग करती हैं और वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता का स्रोत बनती हैं।

पेंशन क्षेत्र

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, और अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में लोगों द्वारा इस संबंध में उठाई जा रही परेशानियों को दूर करना है।

वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी सुविधाएं

देश में वित्तीय बाजार से संबंधित बुनियादी सुविधाएं आमतौर पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। इक्विटी बाजार हेतु समाशोधन निगमों तथा अन्य प्रमुख वित्तीय बाजारों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष को सुदृढ़ एवं समुत्थानशील बनाने हेतु महत्वपूर्ण रेगुलेटरी उपाय किए गए हैं।

प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2015 में किए गए हालिया प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अनुबंध 1) के परिणामों से ज्ञात होता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए 'वैश्विक जोखिम' अभी भी प्रमुख रूप से 'उच्च' जोखिम बना हुआ है, जबकि घरेलू स्तर पर मैक्रो-इकानामिक जोखिम 'मध्यम' जोखिम की श्रेणी में आ गया है।

मूल्यांकन

भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है और अपेक्षाकृत इसके सुदृढ़ मैक्रो-इकानामिक सिद्धांतों ने अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों में व्याप्त अनिश्चितताओं एवं उभरते जोखिमों के प्रति उसे समुत्थानशील बनाया हुआ है। लेकिन, नीति-निर्माताओं और हितधारकों के लिए आवश्यक है कि वे विश्व में तेल एवं वस्तुओं की कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि, वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता तथा विश्व के व्यापार में हो रही और भी मंदी के साथ-साथ विश्व स्तर पर होने वाली संभावित प्रगति के अत्यधिक प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सावधान रहें।

घरेलू स्तर पर, अन्य कारणों सहित अनियमित मौसम की स्थितियों, सीमित नीतिगत प्रभाव-क्षेत्र, कारपोरेट निष्पादन, वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता तथा निवेश में धीमी वृद्धि से उत्पन्न जोखिम, चुनौती पैदा कर सकते हैं।

अध्याय I समष्टिगत-वित्तीय जोखिम

वैश्विक स्तर पर नाजुक बहाली के बीच चीन के वित्तीय बाजार में दबाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत संशयों ने विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है। विश्वव्यापी वित्तीय बाजार क्रियाकलापों में अमरीकी डालर का महत्व ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता लग रहा है, जबकि उदीयमान बाजारों की मुद्राओं की कमजोरी विश्वव्यापी व्यापार और संवृद्धि दोनों के साथ-साथ कॉर्पोरेट कार्य-निष्पादन को भी नुकसान पहुँचा रही है।

हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों में संरचनागत विस्थापनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाजारों में नवोत्पादों की मांग को संतुलित करने की जरूरत स्पष्टतया बाजार में चलनिधि को बढ़ाने के लिए है जिसका प्रभाव बाजार की बाधाओं और वित्तीय स्थिरता पर पड़ेगा।

स्वदेशी मोर्चे पर देखें तो धीमी हो रही वैश्विक संवृद्धि और व्यापार के बीच आउटपुट संवृद्धि में सुधार क्रमिक रूप से होना संभावित है, क्योंकि निजी अंतिम उपभोग-व्यय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं और क्षमता के कम उपभोग के कारण नए निवेश भी प्रभावित हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में लाभप्रदता का स्तर, लीवरेज और ऋण-चुकौती क्षमता लगातार चिंता का विषय बनी रही और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पर इनके प्रतिकूल प्रभाव भी रहे इसके बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान कॉर्पोरेट कार्य-निष्पादन में थोड़ा सुधार भी देखा गया।

वैश्विक पृष्ठभूमि

1.1 चीन की गतिविधियाँ, अपनी मौद्रिक नीति के प्रति रवैये में बदलाव के बारे में अमरीकी फेडरल रिजर्व के सामने दुविधाएं और वैश्विक व्यापार में धीमी संवृद्धि ऐसी बड़ी चिंताएँ हैं जिनसे समस्त संसार के नीति निर्माता तभी से जूझ रहे थे जब जून 2015 में रिजर्व बैंक ने अपनी विगत वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। इसके अलावा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरो ब्लाक में नाजुक रिकवरी और जापान में डगमगाती हुई एबेनोमिक्स को देखते हुए अपनी मात्रात्मक मुक्ति कार्यक्रम¹ को आगे बढ़ाने का वचन दिया है तो बैंक ऑफ जापान से भी इसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत हो रही है, जिससे लगता है कि जी-20 में हुए समझौतों के बावजूद गैर-इरादतन करेसी-युद्ध आरंभ हो सकता है। हालांकि अभी हाल ही में हुई समीक्षा में ईसीबी ने अपने क्यूई कार्यक्रम को मार्च 2017 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, इसमें मात्रात्मक विस्तार नहीं किया गया है और डिपॉजिट सुविधाओं पर ब्याज की दरों को एक अन्य ऐतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है। इसी बीच बैंक ऑफ जापान ने संकुचित श्रम बाजार को देखते हुए क्यूई तत्काल ही आगे बढ़ने का कदम नहीं उठाया। फेड द्वारा 2006 के बाद पहली बार दर में की गई वृद्धि, जो वस्तुतः 16

दिसंबर 2015 के मध्य से प्रभावी की गई है, से वित्तीय बाजारों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, इससे पड़ने वाले प्रभाव को वास्तविक अर्थव्यवस्था में होने वाली प्रगति एवं बाजारों की उसके प्रति प्रतिक्रिया के आलोक में देखा जाना चाहिए, और आगे चलकर इससे खासतौर से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नीतिगत रुझानों में किस प्रकार की तब्दीलियाँ उत्पन्न होंगी। हालात जो भी हों, वैश्विक बाजारों में उभरते डायनामिक्स इस बात की माँग करते हैं कि “जोखिम” और “अनिश्चितता” के बीच विभेद पर पैनी नजर रखी जाए (बॉक्स 1.1)।

1.2 इस बीच, इस तथ्य के बावजूद कि रेन मिन्बी के मोर्चे पर चीन की गतिविधियाँ समूचे विश्व के बाजार परिचालन में काफी प्रभावी रही हैं, यूएस मौद्रिक नीति का रवैया और अमरीकी डालर का महत्व विश्वव्यापी वित्तीय बाजार क्रियाकलापों में अधिक सुरक्षित होता जा रहा है (चार्ट 1.1 और 1.2)। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) बास्केट में रेनमिन्बी को शामिल किए जाने से, आगे चलकर कुछ आरक्षित निधि का आबंटन शुरू करना पड़ सकता है।

1.3 फेड से अक्टूबर 2015 में दरों में बढ़ोतरी का आसन्न संकेत उस समय आया जब नीति निर्माताओं की विचारधारा और

¹ ईसीबी को भी वापसी-खरीद के लिए अर्हताप्राप्त पेपर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में कठिनाई हुई किंतु कहा जाता है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) की आरक्षित निधि का प्रबंध करने वाली शाखा, दि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज (एसएएफई) ने सहजीवी कदम के रूप में बंडों की बिक्री की।

बाक्स 1.1 : प्राचीन ज्ञान की तलाश में

जब मौजूदा समस्याओं के लिए वर्तमान ज्ञान कोई समाधान नहीं दे पाए तो कई बार प्राचीन ज्ञान मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्वव्यापी वित्तीय संकट ने हमें मजबूर किया कि मिन्सकी द्वारा बताई गई वित्तीय स्थिरता की अवधारणा पर ध्यान दें जिसमें यह माना गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋण का संचय करना आर्थिक संकट की कुंजी है। अपने अध्ययन में मिन्सकी ने उधार लेने वालों के तीन प्रकारों का उल्लेख किया था - यथा “सतर्क उधारकर्ता” (ऐसे उधारकर्ता जो अपने देनदारी दायित्वों- मूलधन और ब्याज दोनों को निवेश के वर्तमान नकदी प्रवाह से चुकता कर सकते थे), “कल्पनाशील उधारकर्ता” (ऐसे उधारकर्ता जो देनदारियों को चुका सकते थे - ये वर्तमान निवेश से आने वाले नकदी प्रवाह के माध्यम से केवल ब्याज का भुगतान करते थे और मूलधन का आवधिक रूप से भुगतान स्थगन कर देते थे); और “पॉन्जी उधारकर्ता (जिनका वर्तमान नकदी प्रवाह देनदारी के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था, लेकिन इस भरोसे पर उधार लेते थे कि उसकी आस्तियों के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी से इन देनदारियों को चुकता किया जा सकेगा)। जब आस्तियों की कीमत बढ़ना बन्द हो जाए तो पॉन्जी उधारकर्ताओं का बाहुल्य वित्तीय प्रणाली में तब व्यवधान पैदा कर देता है।

संकट पश्चात के दृश्य को देखें तो मौद्रिक नीतियाँ अत्यधिक सहज रहीं और विकसित राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा आस्तियों की भारी खरीद हुई, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली में स्थायित्व प्रतीत हो रहा था, लेकिन कमजोर संवृद्धि और कम स्फीति दर चिन्ता का विषय रही। क्या प्राचीन ज्ञान इसके लिए उत्तर दे सकता है? लारेन्स समर्स ने एल्विन हेनसेन के “सेक्युलर स्टेगनेशन” की अवधारणा को फिर से प्रस्तुत किया और इस तर्क के माध्यम से स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास किया कि सामान्य न्यूनतम ब्याज दरों की सीमा जीरो और अत्यधिक बचत के साथ अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक पूर्ण रोजगार की स्थिति में लाना कठिन होगा। बरनान्के ने इस तर्क का खंडन किया कि अंतरराष्ट्रीय आयाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी खुली अर्थव्यवस्था में सेक्युलर स्टेगनेशन के कायम रहने की संभावना नहीं होती है। दूसरी ओर, रोगेफ ने “ऋण-सुपर सायकल” में तर्क दिया है कि लाभ उठाने और उधार लेने की विपरीत स्थितियों के एक बार शांत होते ही संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ उच्चतर सिद्ध हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सेक्युलर स्टेगनेशन की तरह ऋण-सुपर-सायकल हमेशा के लिए नहीं होता है।

स्विस नेशनल बैंक द्वारा इस साल के आरंभ में करेंसी पेग को छोड़ने के निर्णय ने मार्केट को चकित कर दिया था और अब चीन में घटनाओं में आए मोड़, खासकर मार्केट को बंद करने के निर्णय के बीच समरूपता लाते हुए उदीयमान देशों के नीति निर्माताओं का फोकस संभवतया एक अन्य प्राचीन ज्ञान की ओर चला जाता है, अर्थात् जोखिम और अनिश्चितता के बीच फ्रैन्क नाइट द्वारा किया गया विभेद - इस अर्थ में कि जोखिम की कीमत लगाई जा सकती है इससे सुरक्षा की जा सकती है, जबकि अनिश्चितता के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। नाइट ने “रिस्क अनसर्टिनिटी एंड प्रॉफिट” में संभाव्यता के तीन विभिन्न प्रकारों के बीच विभेद किया है यथा- “अनुमानित संभाव्यता” (पांसे फेंकने पर कोई भी संख्या आने की संभावना), “सांख्यिकीय संभाव्यता” (जो कि अनुभवजन्य मूल्यांकन पर आश्रित होती है) और “अनुमान” (जहाँ विद्यमान आंकड़े स्वयं ही किसी सांख्यिकीय विश्लेषण की तरफ नहीं ले जाते)।

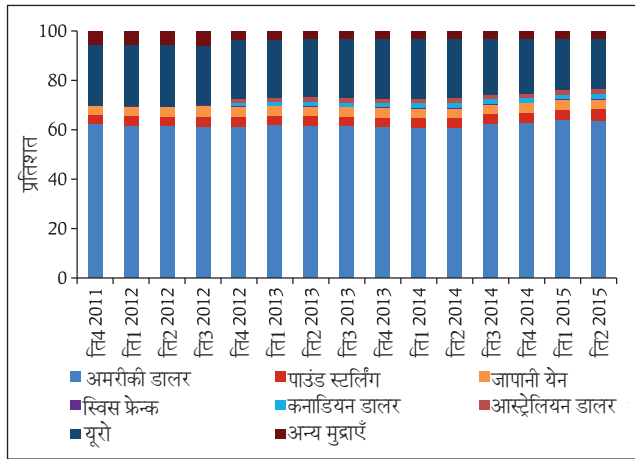
संदर्भ

- मिन्सकी, एच (1992), "दी फाइनेन्शियल इन्स्टेबिलिटी हायपोथिसिस", वर्किंग पेपर सं.74, लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, मई हेन्सेन, एल्विन (1939), "इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डिक्लाइनिंग पॉप्यूलेशन ग्रोथ", दी अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, वाल्यूम नं. 29, सं.1, पृष्ठ 1-15, मार्च
- समर्स, लारेन्स (2014), "यू.एस. इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स : सेक्युलर स्टेगनेशन, हिस्टेरिसिस, एंड दी जिरो लोअर बाउन्ड" बिजनेस इकोनॉमिक्स, वाल्यूम 49, सं.2, नैशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्रैल
- बरनान्के, बेन (2015), "वाइ आर इन्टरेस्ट रेट्स सो लो, पार्ट-2 : सेक्युलर स्टेगनेशन" बेन बरनान्केस ब्लॉग, ब्रुकिंग्स, मार्च 31 (<http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/03-31-why-interest-rates-low-secular-stagnation> पर उपलब्ध है)।
- रोगॉफ, केनेथ (2015), "डेब्ट सुपरसाइकल, नॉट सिक््युलर स्टेगनेशन", सीईपीआर पॉलिसी पोर्टल, अप्रैल 22 (<http://www.voxeu.org/article/debt-supercycle-not-secular-stagnation> पर उपलब्ध है)।

बाजारों की सोच के बीच बढ़ते हुए विभेद वित्तीय बाजारों में संभावित अस्थिरता में बढ़ोतरी कर रहे थे। समस्त संसार में वित्तीय स्थिरता के प्रावधानकर्ता इस बारे में संशयवादी नहीं हो सकते हैं कि समस्त संसार में उदार मौद्रिक नीतियों के साथ बाजार में चलनिधि की

बढ़ोतरी भी रही, और दोनों ने मिलकर, खासतौर पर बाजारों के लिए, आसन्न बाधक चक्र के साथ आने वाले संभावित चलनिधि जोखिम को भी बढ़ाया। दूसरी तरफ ऐसे संकेत तब भी मदद करेंगे जब "सेक्युलर स्टेगनेशन" की अवधारणा बाजार की मनोवृत्ति के

चार्ट 1.1 : आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना



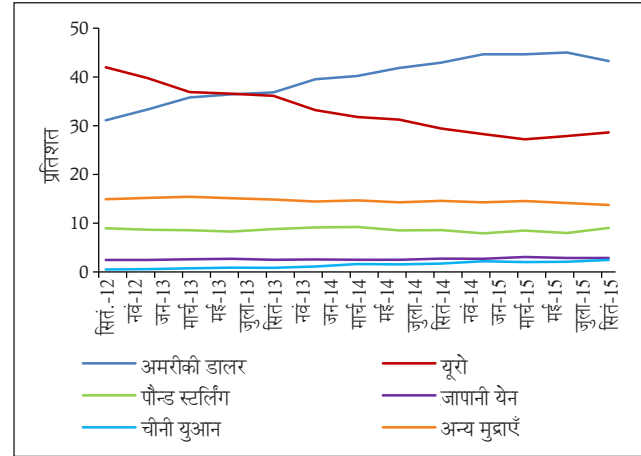
टिप्पणी : आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार आबटित भंडार को दर्शाते हैं (देशों के भंडार जो आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना (सीओएफईआर) डेटाबेस में दर्ज होते हैं)।
स्रोत : अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष - सीओएफईआर

साथ मजबूत होती जा रही हो, जो आस्ति कीमतों में अचानक उछाल को बल प्रदान कर सकती है, खासकर आस्ति श्रेणियों² के बीच बढ़े हुए सकारात्मक सहसम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में यदि अतिसवेदनशीलता हुई तो इससे बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे हालात जिनमें अमरीकी महंगाई 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे है, तो फेड के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मतलब यह भी रहा होगा कि महंगाई के अनुमानों को भी घटाया जाए। बाजारों में अनिश्चितता को संयमित करने के लिए 'भावी मार्गदर्शन' अब सारे संसार के केंद्रीय बैंकों के लिए चुनौती भरा काम होने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) का मानना है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य वास्तविक अर्थव्यवस्था में साम्यावस्था नहीं है, बल्कि वित्तीय क्षेत्र³ में साम्यावस्था लाना है, यह वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों के बीच प्रकट हो रहे डायनामिक्स की स्वीकारोक्ति है।

धीमा वैश्विक व्यापार

1.4 वैश्विक व्यापार में धीमेपन की प्रवृत्ति विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनागत परिवर्तनों के कारण भी हो सकती है, भले ही फोकस स्वदेशी की तरफ बढ़ रहा हो। इसी बीच कुछ शोध यह भी बता रहे हैं कि उदीयमान बाजारों की मुद्राओं में कमजोरी, चाहे

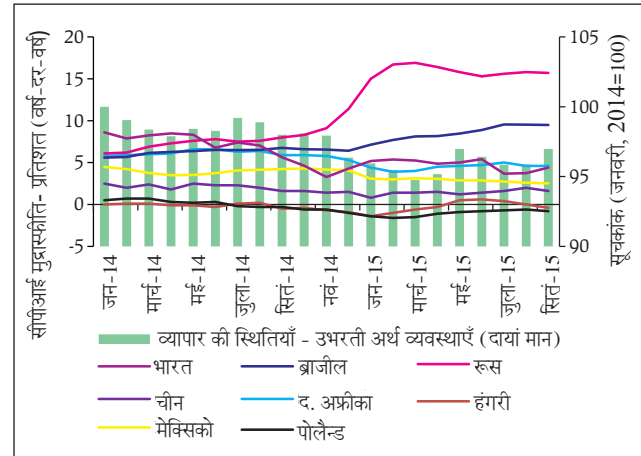
चार्ट 1.2 : विश्व भुगतानों में विभिन्न मुद्राओं के अंश



टिप्पणी : यह अंश ग्राहक द्वारा आरंभ और संस्थागत भुगतानों के कुल मूल्य पर आधारित हैं, जो स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त हुए और भेजे गए।
स्रोत : विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट)

यह मुद्रा-युद्ध के कारण हो या नहीं, विश्वव्यापी व्यापार को नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि उनके आयात तो घट रहे हैं लेकिन उनके निर्यातों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिल रहा। इसके बजाय उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं⁴ के लिए मुद्रा अवमूल्यन ने व्यापार में हानियों को व्यापक रूप से बढ़ाया है, (चार्ट 1.3) और कुछ देशों में महंगाई के दबाव को बढ़ाया है।

चार्ट 1.3: व्यापारिक हानि और स्फीतिकारी दबावों की स्थितियाँ



स्रोत : ब्लूमबर्ग और केन्द्रीय आयोजना ब्यूरो (सीपीबी) नीदरलैंड डेटाबेस।

² जीएसएफआर अप्रैल 2015 के अनुसार कम चलनिधि, कम मार्केट मेकिंग और अधिक बेन्च-मार्किंग के कारण यह संभावना बनती है कि आस्ति कीमतें सामान्य आघातों से ज्यादा संचालित होंगी, खासकर उच्चतर बारंबारता के साथ, और ऐसे में उनकी स्वभाविक वृत्ति के मूल-सिद्धान्त पीछे रह जाते हैं।

³ फाइनेशियल टाइम्स, सितंबर 8, 2015 में प्रकाशित मार्टिन वुल्फके लेख 'दि केस फॉर कीपिंग यूएस इंटररेस्ट रेट्स लो' में प्रकाशित बीआईएस की जून 2015 में प्रकाशित 85 वीं वार्षिक रिपोर्ट (2014-15) के संदर्भ में।

⁴ कैपिटल मार्केट मॉनिटर-आईआईएफ सितंबर 2015।

उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर हो रही संवृद्धि

1.5 विश्वव्यापी वित्तीय संकट-काल से लेकर इस समय तक भले ही ईएमडीई-ईई संवृद्धि अंतराल अपने न्यूनतम बिंदु पर है, किंतु फिलहाल यह संभावना अधिक है कि वैश्विक संवृद्धि दरों के वर्तमान अनुमानों को और भी नीचे लाया जाएगा (चार्ट 1.4)। इसके अलावा, विश्व व्यापार में संवृद्धि और कारपोरेट अर्जनों के बीच इस संबंध को देखते हुए धीमी व्यापार संवृद्धि का प्रभाव उदीयमान बाजारों के कारपोरेट अर्जनों पर पड़ना संभावित है (चार्ट 1.5)।

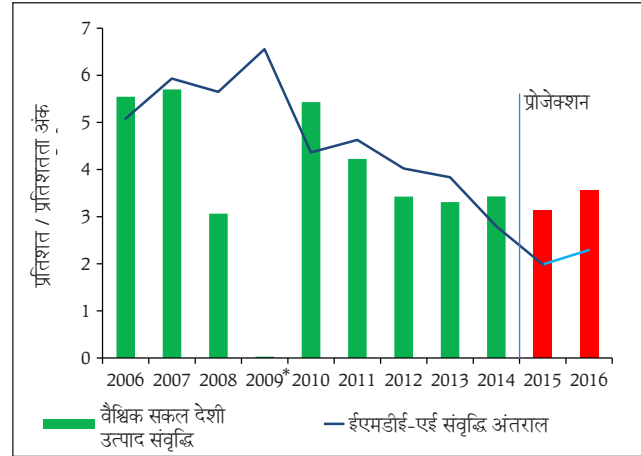
तेल-कीमतों के लिए नरम दृष्टिकोण की निरन्तरता

1.6 कमोडिटी सुपर-सायकल का समापन व्यय की शक्ति को उपभोग की उच्चतर सीमांत प्रवृत्ति वाली अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ा सकता है। इस बीच अमरीकी शेल उद्योग वित्तीय दबाव का अनुभव कर रहा है। परिणामस्वरूप, अब अमरीकी फर्मों को अनुमति दी गई है कि वे अपने कुछ तेल की अदला-बदली मैक्सिको के साथ करें जो कि स्वेदश में उत्पादित तेल की कीमत को विश्वव्यापी बाजार की कीमतों की तुलना में अंतर को प्रभावित करेगी। ईरान का परमाणु समझौता तेल की प्रचुरता में और भी बढ़ोतरी कर देगा। हालांकि तेल के लिए इस नरम दृष्टिकोण में उन देशों के लिए आत्म संतोष का जोखिम भी है जो कच्चा तेल काफी बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्योंकि इन देशों में असंतुलित राजकोषीय प्राथमिकताएँ और तेल की सकल मांग की बढ़ती हुई तेजी दोहरे घाटे की तरफ ले जाएंगी, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों से भी सिद्ध है।

वित्तीय बाजारों में संरचनागत परिवर्तनों से अनिश्चितता को बढ़ावा

1.7 अनिश्चितता इस तथ्य से प्रकट होती है कि वित्तीय बाजारों ने विगत कुछ वर्षों में संरचनागत परिवर्तन किए हैं। यद्यपि सामान्यतया इसमें कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन 'बाजार में चलनिधि बढ़ाने' के नाम से झोंक दिए गए वित्तीय बाजार के नव उत्पादों के लिए माँग और बाजार में खलबली और वित्तीय स्थिरता पर इन नव-उत्पादों के प्रभाव के बीच संतुलन स्थापित करने में विनियामकों के समक्ष चुनौती निरंतर बनी रहेगी। बाजारों में टकराव की झलक के हालिया प्रसंगों से संकेत मिलते हैं कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी और स्वचालित कम्प्यूटर प्रोग्राम या

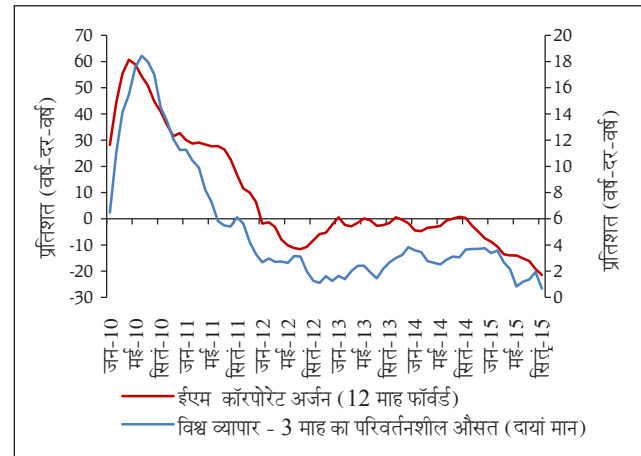
चार्ट 1.4: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि और ईएमडीई-ईई संवृद्धि में अंतराल



*: 2009 के लिए वैश्विक सकल देशी उत्पाद संवृद्धि 0.03 प्रतिशत था।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

चार्ट 1.5: उभरते बाजारों में कारपोरेट अर्जन और विश्व व्यापार की मात्रा में संवृद्धि



टिप्पणी : ईएम कॉर्पोरेट अर्जन (12 माह फॉर्वर्ड) का सम्बन्ध एमएससीआय उभरते बाजार सूचकांक (एमएक्सईएफ) के प्रति शेयर 12 माह फॉर्वर्ड अर्जन से है (ईपीएस)

स्रोत : ब्लूमबर्ग और सीपीबी डाटाबेस।

* कुछ लोगों का मानना है कि "जोखिम समता निधियों" - जो कि परिवर्तनशीलता की प्रतिक्रिया में आवधिक रूप से आबंटनों को बदलने के लिए 'एल्गोरिथ्म' का प्रयोग करती हैं - ने स्टॉक मार्केट में हाल ही में हुई खलबली को बढ़ावा दिया।

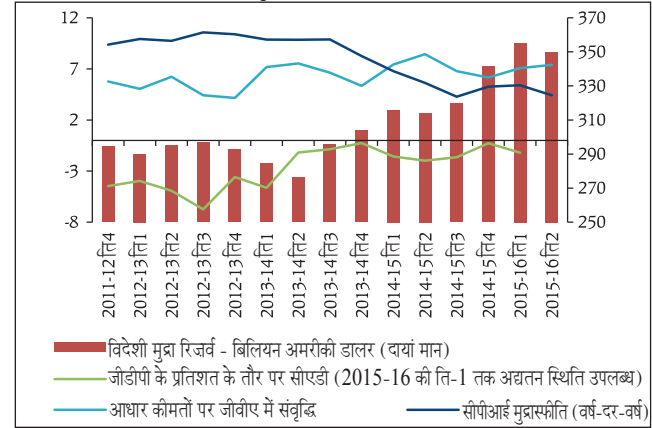
उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग⁶ ने बाजार के कार्य-चालन को बदल कर असमानता पैदा कर दी है, क्योंकि खुदरा निवेशक तो आधुनिक बाजारों में भारी तादाद में लगातार हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। अमरीका के प्रमुख विनियामकों की एक संयुक्त रिपोर्ट⁶ में उल्लिखित अमरीकी ट्रेजरियों में तेजी से हुई अचानक गिरावट ऐसी ही है जो डीलर वर्चस्व वाले बाजार को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म वाले बाजार में बदलने से परिवर्तनशीलता गंभीर हालात पैदा कर सकती है जो चलनिधि पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं। इसी बीच दि.कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी), जो कि अमरीकी वित्तीय नियंत्रक है, ने बताया है कि यह संभवतया आर्डर सीमाओं और 'किल स्विच'⁷ के माध्यम से हाईस्पीड ट्रेडिंग के जोखिमों पर ध्यान देगा।

घरेलू समष्टि-आर्थिक चुनौतियाँ

बेहतर मूल सिद्धांतों का सामना स्वदेशी सुधारों की चुनौतियों से

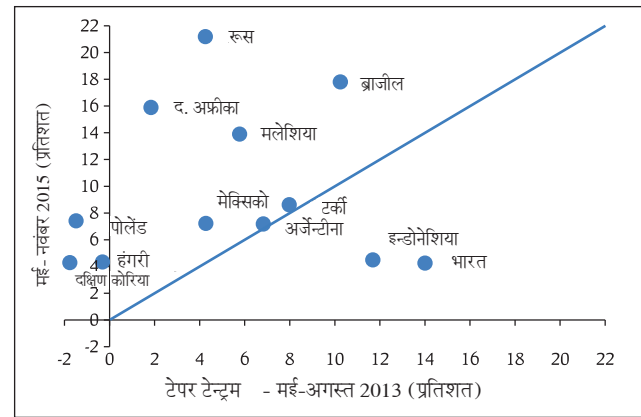
1.8 समुन्नत समष्टि-आर्थिक मूल सिद्धान्तों (चार्ट 1.6) और इसके समस्तों की तुलना में समुत्थानशीलता (चार्ट 1.7) के बावजूद - एक तरफ तो रुपये को बाहरी स्पर्धा में बने रहने की चुनौती है और दूसरी ओर स्फीतिकारी दबावों और अपेक्षित पूंजी प्रवाह का प्रबंधन भी करना है - स्वदेशी माँग और निजी निवेश में धीमेपन की स्थिति में अधिकाधिक सरकारी निवेश की जरूरत होती है, वह भी ऐसे समय में जब सरकार राजकोषीय समेकन के लिए वचनबद्ध है। यद्यपि कर और कर से इतर राजस्व के उच्चतर संग्रहण के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में (अब तक) गैर-ऋणगत पूंजी प्राप्तियों के (चार्ट 1.8) साथ पूँजीगत व्यय का अधिक ट्रैक्शन मिल रहा है, तथापि राजस्व व्यय पर बढ़ती हुई माँग और सरकारी क्षेत्र के विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में अक्षमता को देखते हुए राजकोषीय युक्तियों के समक्ष भी सीमाएं आ जाती हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, बाजार की प्रत्याशाओं के अनुसार महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभकारी होगा। भारत को अपनी क्षमता के अनुरूप वृद्धि दर से आगे बढ़ने के लिए माल एवं सेवा

चार्ट 1.6: चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतक



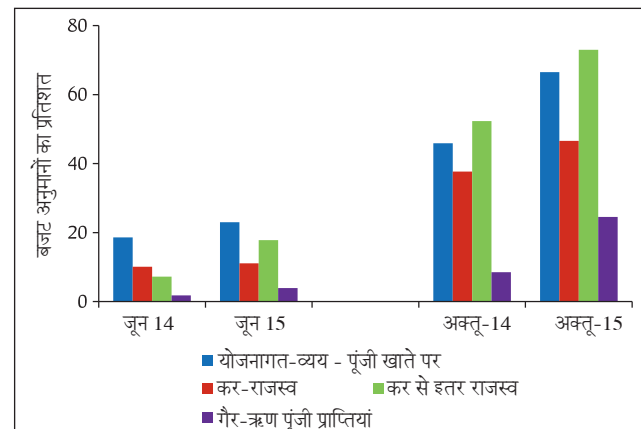
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.7: ईएम मुद्राओं का मूल्य-हास- टेपर टेन्टम बनाम - मई-नवंबर 2015



स्रोत - ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.8 : पूंजी खाता और बेहतर राजकोषीय दायरे में योजनागत-व्यय



स्रोत : नियंत्रक महा-लेखाकार - भारत सरकार

⁶ ज्वाइंट स्टाफ रिपोर्ट: 15 अक्टूबर 2014 को अमरीकी ट्रेजरी मार्केट-यह अमरीकी ट्रेजरी विभाग के स्टाफ, फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नरों के बोर्ड, दि. फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क, दि. यू.एस. सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, और यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, की रिपोर्ट है जो 13 जुलाई 2015 को प्रकाशित हुई <http://www.treasury.gov/press-center/pressreleases/Documents/joint-Staff-Report-Treasury-10-15-2015.pdf>

⁷ प्रक्रिया समापन करने की व्यवस्था इस मामले में 'रनअवे अल्गोरिथ्म' को रोकने की प्रक्रिया।

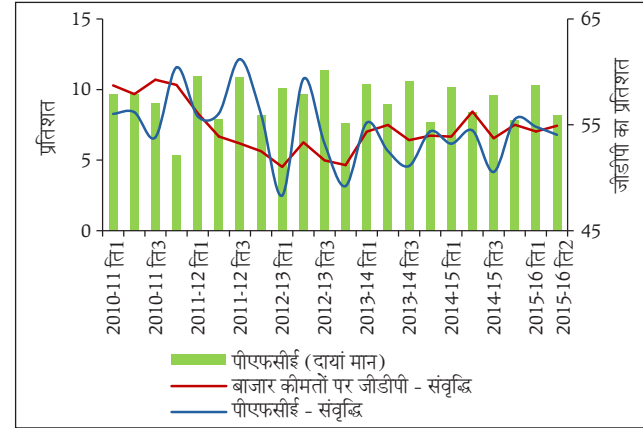
कर (जीएसटी) को लागू करना एक तत्काल अनिवार्यता है। विश्वव्यापी विपरीत स्थितियों और उनके साथ जुड़े जोखिम भारत के लिए चिन्ता बने रहेंगे और इसलिए उचित उपाय आरंभ करने की जरूरत होगी जो परिवर्तनशील वित्तीय बाजारों और बाजार की नाजुक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए देश-विशेष से जुड़े विशिष्ट स्वभाव वाले जोखिमों को नियंत्रित कर सकें।

1.9 उत्पाद संवृद्धि मुख्यतया रोक लिए गए निजी अंतिम उपभोग व्यय⁸ (पीएफसीई) में धीमी बढ़ोत्तरी के कारण बाधित रही, जो कि अन्य घटकों में से एक है, इसके अलावा कृषि की जीवीए संवृद्धि में भी कमजोरी रही (चार्ट 1.9)। यहाँ तक कि कमोडिटी कीमतों में कमी का असर कृषि निर्यातों पर पड़ रहा है (चार्ट 1.10)।

1.10 बाह्य मांग में कमजोरी ने निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, हालांकि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में चालू खाते का घाटा सहज स्तर पर बना हुआ है। तथापि, ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप⁹ तथा रेंमिन्बी के मूल्यहास जैसी विश्वव्यापी गतिविधियों के बीच निर्यातों में गिरावट चिन्ताजनक हो सकती है। खास तौर पर यह कि निर्यात की मात्रा में संवृद्धि हाल ही के वर्षों में कमजोर रही है और हाल ही के महीनों में तो ऋणात्मक भी हो गई, भले ही एशियन सदस्यों के साथ 2010 से ही मुक्त व्यापार समझौता¹⁰ लागू है, इससे एशियाई ईएमडीई के बीच मुद्रा की प्रतिस्पर्धा की भूमिका प्रकट होती है (चार्ट 1.11)। आयात के मोर्चे पर देखें तो कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और स्वर्ण आयात में कमी के कारण काफी लाभ हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं¹¹ के आयात में सुस्थिर बढ़ोतरी यह बताती है कि स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

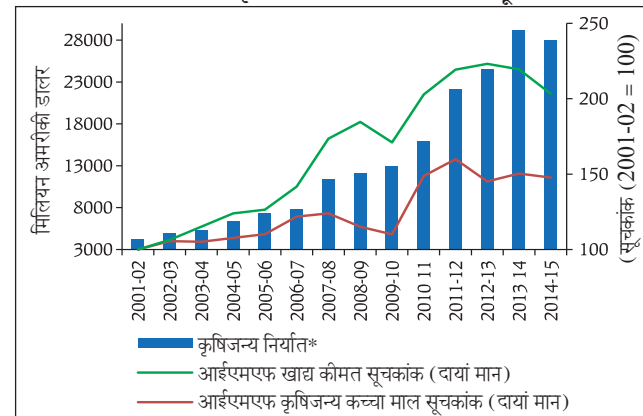
1.11 घरेलू और बाहरी मांग में कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि कमजोर रही है, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में सूचित किया गया है। हालांकि, हाल ही में, अक्टूबर 2015 में 9.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) होने (पांच वर्षों में सबसे अधिक), जिसमें आंशिकरूप से आधार प्रभाव का असर पड़ा, से बहाली के संकेत मिलते हैं (चार्ट 1.12)।

चार्ट 1.9 : उपभोग में गिरावट



स्रोत : एमओएसपीआई-भारत सरकार।

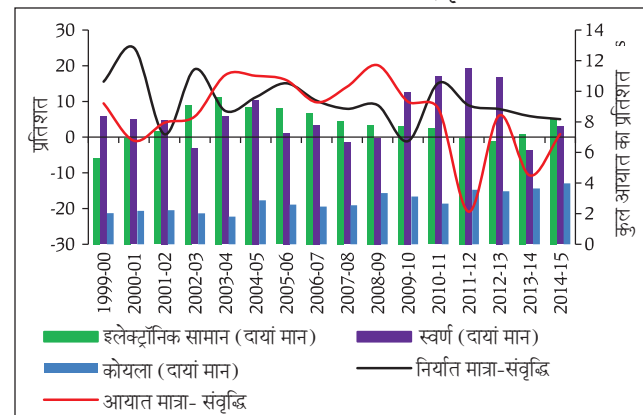
चार्ट 1.10 : कृषि निर्यात और वैश्विक पण्यों के मूल्य



टिप्पणी : * कृषिजन्य निर्यातों में शामिल है - चाय, कॉफी, चावल, तम्बाकू, काजू, मसाले, खली, फल और सब्जियाँ, मैरीन-उत्पाद और मांस तथा मांसाहार।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

चार्ट 1.11: निर्यात और आयात की प्रवृत्तियाँ



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

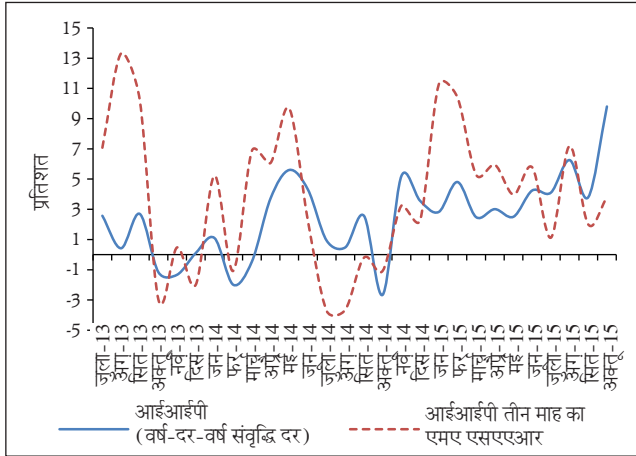
⁸ 2015-16 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी (बाजार कीमतों पर) घटकर 7.4 प्रतिशत हुई जब कि विगत वर्ष इसी समयावधि में यह 8.4 प्रतिशत थी। यह गिरावट मुख्यतया निजी अंतिम उपभोग व्यय में बढ़ोतरी के कारण हुई।

⁹ ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर पेसिफिक की परिधि पर स्थित प्रमुख देशों (इस समय इनमें चीन और द. कोरिया शामिल नहीं हैं) के बीच वर्तमान चर्चा चल रही है।

¹⁰ भारत ने जापान और कोरिया के साथ भी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) किया है।

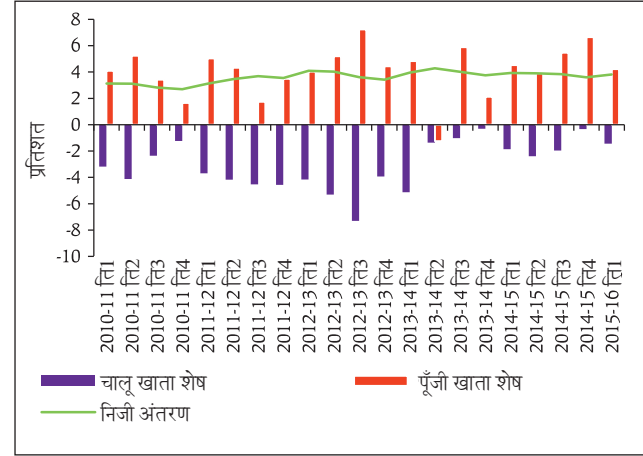
¹¹ रुपये में देखें तो, हाल के अतीत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात मूल्य स्वर्ण आयात के मूल्य से आगे निकल गया।

चार्ट 1.12: औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर और 3 माह का गतिमान औसत



टिप्पणी: एमए एसएएआर का तात्पर्य मौसमी घटकों के कारण समायोजित वार्षिक दर का गतिमान औसत
स्रोत: सीएसओ-भारत सरकार

चार्ट 1.13: चालू खाता, पूँजी खाता तथा निजी अंतरण
(जोड़ोपी के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

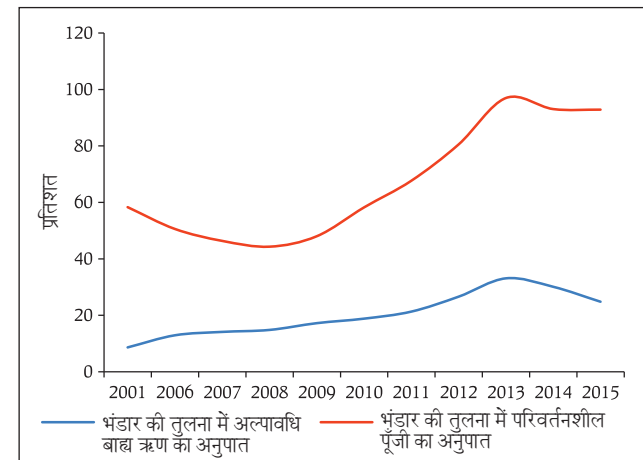
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 2011-12 से क्षमता प्रयोग में व्यापक रूप से गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

1.12 धीमी स्वदेशी और बाह्य मांग के बीच अत्याधिक क्षमता (कतिपय उद्योगों में) अपने आप में अनिवार्यतः मांग में कमजोरी का संकेत नहीं है। भारतीय विद्युत क्षेत्र का एक मामला हम देख सकते हैं कि उत्पादित विद्युत का भुगतान करने में डिस्कॉमस¹² की अक्षमता ने अत्यधिक क्षमता की पैरा-डॉक्सिकल स्थिति पैदा कर दी है जिससे विद्युत उत्पादकों और उनके वित्तपोषकों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। डिस्कॉमस के ऋणों की पुनर्संरचना के लिए हाल ही में तैयार पैकेज उज्ज्वल डिस्कॉम एन्शोरेन्स योजना (उदय) का अभी हाल ही में अनुमोदन हुआ है, यह अनिवार्यतया वित्तीय संस्थानों पर पड़ रहे दबाव को राज्य सरकारों पर शिफ्ट कर देगी, यह उप अधिशासकीय स्तर पर वित्तीय अनुशासन, खासकर प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली को सुनिश्चित करेगा।

चालू तथा पूँजी खाता शेष

1.13 चालू खाता घाटा को कम करने में प्रेरक धनप्रेषण (निजी अंतरण) ने कच्चे तेल की कम कीमतों ने अनुपूर्ति की है और कम लेकिन महत्वपूर्ण पूँजी प्रवाह ने पूँजी खाते में भी पर्याप्त अधिशेष बनाया है (चार्ट 1.13)। यद्यपि अल्पावधि बाह्य ऋण और परिवर्तनशील पूँजी प्रवाह (एक साथ) तथा फोरेक्स रिजर्व का अनुपात संयत ही बना रहा (चार्ट 1.14), तथापि कतिपय अन्य

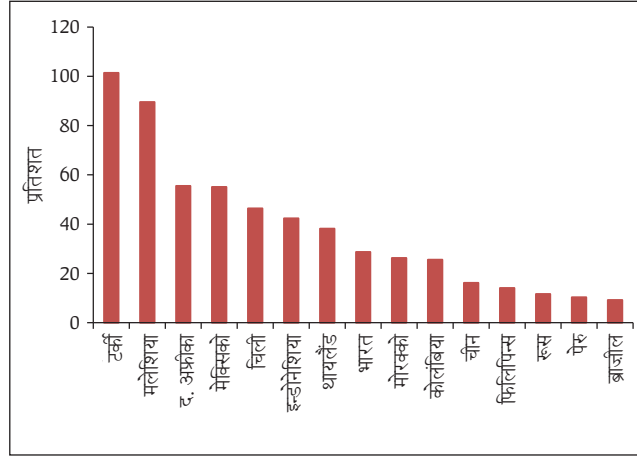
चार्ट 1.14: अल्पावधि बाह्य ऋण स्टॉक और परिवर्तनशील पूँजी प्रवाह
(विदेशी मुद्रा भंडार का प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

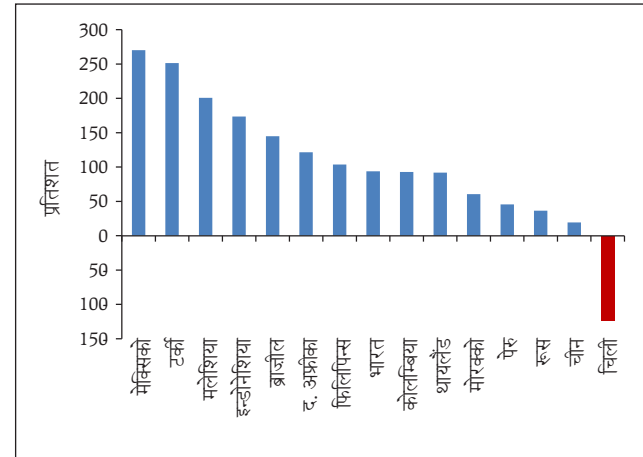
¹² डिस्कॉमस भारतीय विद्युत वितरण कंपनियाँ हैं।

चार्ट 1.15: विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधि बाह्य ऋण का अनुपात - भिन्न देशों के बीच तुलना



टिप्पणी: नवीनतम उपलब्ध डाटा (वर्ष 2014 या वर्ष 2013 हेतु) का प्रयोग किया गया।
स्रोत: इंटरनेशनल फ़ाइनेन्शियल स्टेटिस्टिक्स (आईएफएस) ईयरबुक 2015 (आईएमएफ) और इंटरनेशनल डेट स्टेटिस्टिक्स 2015 (विश्व बैंक)

चार्ट 1.16: विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में परिवर्तनशील पूँजी प्रवाह का अनुपात



टिप्पणी: परिवर्तनशील पूँजी प्रवाह की परिभाषा इस प्रकार है- पोर्टफोलियो निवेश (देयताएँ) इनमें से घटाएँ पोर्टफोलियो निवेश (आस्तियाँ) और इनमें अल्पावधि ऋण जोड़ें, यहाँ पोर्टफोलियो निवेशों को इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट पोजिशन (आईएफएस- ईयरबुक 2015) से लिया गया है।
स्रोत: आईएमएफ।

बाह्य सुभेद्यता उपायों (चार्ट 1.15 और 1.16) की दृष्टि से भारत को औसत स्थिति मिल जाती है। हालांकि चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने वाले पूँजी प्रवाह के प्रकार के लिए संरचनागत सुधारों, सुस्पष्ट नीतिगत रवैये, खासकर टैक्स मामलों और कारोबार करने में सहजता के लिए लगातार जोर देने की अपेक्षा है।

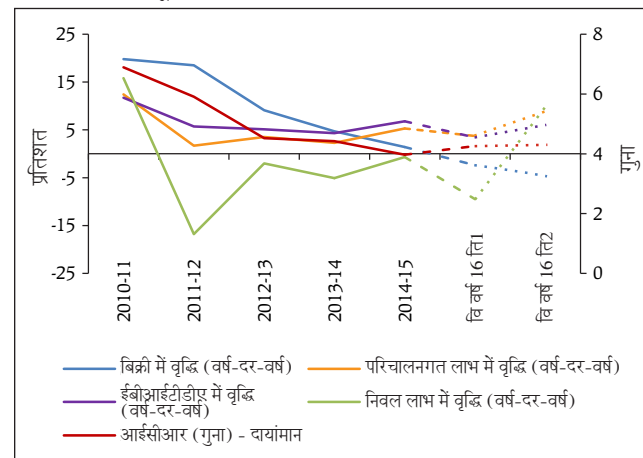
कॉर्पोरेट क्षेत्र

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

1.14 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए सूचीबद्ध चुनिंदा गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ)¹³ कंपनियों का प्रयोग करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि परिचालनगत लाभ, ईबीआईटीडीए¹⁴, निवल लाभ तथा ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर)¹⁵ जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों में 2015-16 की पहली तिमाही में गिरावट आने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में सुधार देखा गया (चार्ट 1.17)।

1.15 सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों¹⁶ की लाभप्रदता में 2014-15 के उत्तरार्द्ध में कमी आई किंतु 2015-16 के पूर्वार्द्ध में

चार्ट 1.17: सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों का कॉर्पोरेट कार्य निष्पादन



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियाँ)

¹³ सूचीबद्ध 2,711 एनजीएनएफ कंपनियाँ।

¹⁴ ईबीआईटीडीए ब्याज, करों, मूल्यहास तथा ऋण-परिशोधन के पहले की कमाई है, जिसकी गणना इस प्रकार की जाती है - ईबीआईटीडीए=ईबीआईटी + मूल्यहास एवं ऋण-परिशोधन। ईबीआईटी ब्याज एवं करों के पहले की कमाई है।

¹⁵ आईसीआर को ब्याज पर व्यय अनुपात की तुलना में ईबीआईटीडीए के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹⁶ पिछली तीन छमाहियों अर्थात् सितंबर 2014 को समाप्त छमाही, मार्च 2015 तथा सितंबर 2015 को समाप्त छमाही के दौरान सूचीबद्ध 2,368 एनजीएनएफ कंपनियों की छमाही विवरणियों पर आधारित।

इसमें सुधार हुआ जब कि ऋण-शोधन क्षमता अनुपात¹⁷ में काफी सुधार होने के संकेत मिले। आईसीआर के माध्यम से मापी गई कर्ज चुकौती क्षमता में भी 2015-16 के पूर्वार्द्ध में सुधार हुआ। इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात (डीईआर)¹⁸ के माध्यम से मापे गए कॉरपोरेट लीवरेज लगभग उसी स्तर पर बना रहा जहां पर यह सितंबर 2014 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान था (सारणी 1.1)।

कॉरपोरेट लीवरेज

प्रवृत्ति

1.16 पिछली तीन छमाहियों के दौरान ऋणात्मक निवल मालियत या डीईआर ≥ 2 (जिन्हें 'लीवरेज युक्त' कंपनी कहा गया) वाली कंपनियों का अनुपात सितंबर 2014 के 18.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2015 में 19.4 प्रतिशत हो गया जबकि नमूने की सभी कंपनियों के कुल कर्ज में उनका हिस्सा मार्च 2015 के 33.8 प्रतिशत की तुलना में थोड़ासा घटकर 30.5 प्रतिशत हो गया था (सारणी 1.2)।

1.17 इसी प्रकार से, डीईआर ≥ 3 (जिन्हें 'अत्यधिक लीवरेज युक्त' कंपनी कहा गया) वाली लीवरेज युक्त कंपनियों के बीच कंपनियों का अनुपात सितंबर 2014 के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2015 में 15.3 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल कर्ज में इन कंपनियों के कर्ज का हिस्सा 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 1.2)।

ऋण चुकौती क्षमता

1.18 चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों¹⁹ के नमूने का प्रयोग करते हुए कर्ज चुकौती क्षमता एवं कमजोर कंपनियों के लीवरेज की वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, 'कमजोर' कंपनियों के रूप में उन कंपनियों को परिभाषित किया गया जिनका आईसीआर 1 से कम था। जिन कंपनियों का डीईआर 2 के बराबर या उससे अधिक था उनको 'लीवरेज युक्त'²⁰ कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कमजोर कंपनियों में उन कंपनियों को 'लीवरेज उक्त कमजोर' माना गया है जिनका डीईआर 2 के बराबर या उससे अधिक है या ऋणात्मक निवल मालियत की हैं।

सारणी 1.1: सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के कार्य निष्पादन के चुनिंदा वित्तीय अनुपात (2014-15 एवं 2015-16)

	सितंबर 2014 को समाप्त छमाही	मार्च 2015 को समाप्त छमाही	सितंबर 2015 को समाप्त छमाही
औसत* कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	2.6	1.9	2.6
ऋण-शोधन क्षमता अनुपात (प्रतिशत)	13.8	12.1	14.5
इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात	0.38	0.39	0.38
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	5.8	4.9	5.4
औसत* उधारियों की तुलना में ब्याज भुगतान ** (प्रतिशत)	10.1	10.1	10.3

टिप्पणी: * औसत छमाही से संबंधित बकाया प्रारंभिक एवं अंत की स्थिति पर आधारित है।
** वार्षिकीकृत ब्याज भुगतान का प्रयोग किया गया।

स्रोत: भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

सारणी 1.2: सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियां : कॉरपोरेट लीवरेज में सामान्यतर जोखिम

(प्रतिशत)

लीवरेज	कंपनियों की संख्या (कुल कंपनियों के प्रतिशत के रूप में)			कुल कर्ज की तुलना में कर्ज का हिस्सा		
	सितं'14	मार्च'15	सितं'15	सितं'14	मार्च'15	सितं'15
ऋणात्मक निवल मालियत या डीईआर ≥ 2	18.4	19.0	19.4	31.8	33.8	30.5
ऋणात्मक निवल मालियत या डीईआर ≥ 3	13.6	14.2	15.3	22.9	23.0	24.9

स्रोत: भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

1.19 विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार चुनिंदा प्रतिदर्शों में से 15.8 प्रतिशत कंपनियां कमजोर थीं। 2014-15 के उत्तरार्द्ध में इन कमजोर कंपनियों का

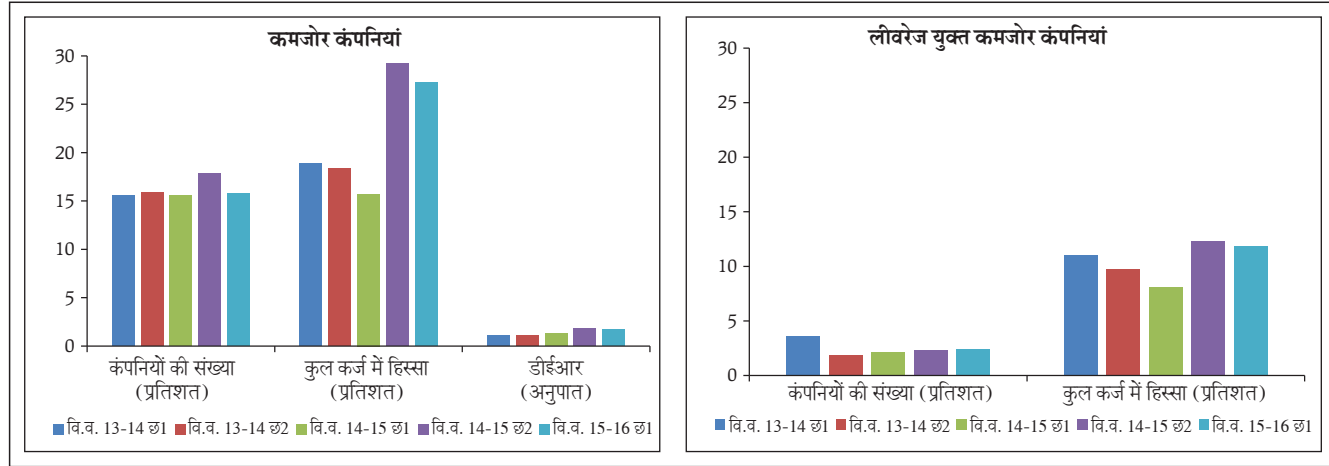
¹⁷ ऋण-शोधन क्षमता को कर पश्चात लाभ (पीएटी) तथा कुल कर्ज की तुलना में मूल्यहास के रूप में परिभाषित किया गया।

¹⁸ कर्ज को दीर्घावधि उधारियां माना गया है तथा इक्विटी निवल मालियत है।

¹⁹ पिछले पांच छमाहियों अर्थात सितंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014, मार्च 2015 एवं सितंबर 2015 को समाप्त छमाहियों के दौरान सूचीबद्ध 2,368 एनजीएनएफ कंपनियों की छमाही विवरणियों, पर आधारित।

²⁰ लीवरेज युक्त कंपनियों में ऋणात्मक निवल मालियत वाली कंपनियों को शामिल किया गया है क्योंकि इन कंपनियों के ऋण-शोधन क्षमता के मुद्दे भी होंगे।

चार्ट 1.18 : सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों : कमजोर कंपनियों - वर्तमान प्रवृत्ति (2013-14 से 2015-16)



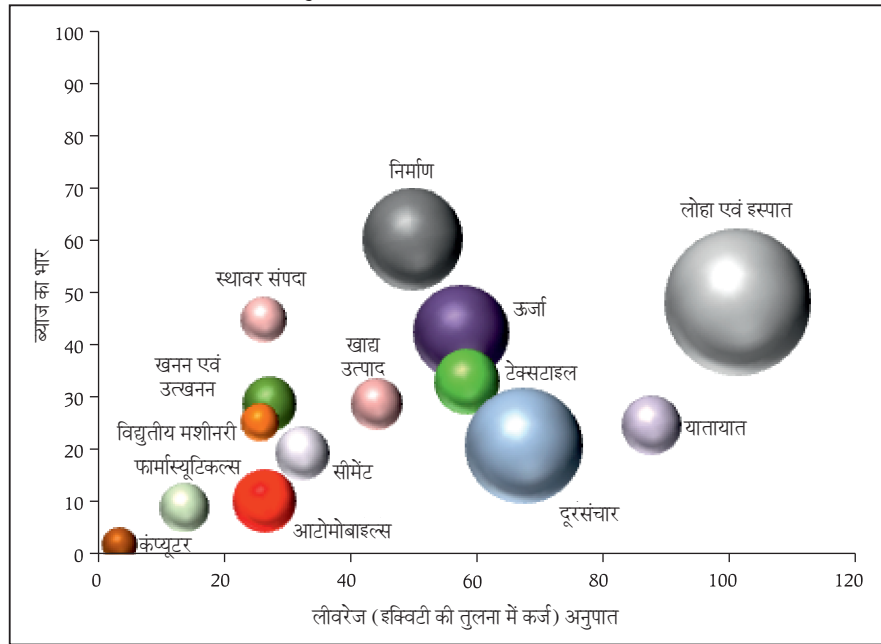
स्रोत : भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

डीईआर बढ़कर 1.8 हो गया किंतु 2015-16 की पहली छमाही में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 1.7 रह गया। कुल कर्ज में इन कमजोर कंपनियों के कर्ज²¹ का हिस्सा 27.3 प्रतिशत रहा। प्रतिदर्श में लीवरेज युक्त कमजोर कंपनियों 2.4 प्रतिशत थीं और कुल कर्ज में उनका हिस्सा 11.8 प्रतिशत था। 2014-15 में कमजोर के साथ ही साथ लीवरेज युक्त कमजोर -दोनों तरह की कंपनियों के कुल

कर्ज में हिस्सा बढ़ा, किंतु 2015-16 की पहली छमाही में इसमें थोड़ी गिरावट आई (चार्ट 1.18)।

1.20 सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार चुनिंदा उद्योगों के जोखिम प्रोफाइल से ज्ञात हुआ कि लोहा एवं इस्पात, कंस्ट्रक्शन तथा ऊर्जा उद्योग अपेक्षाकृत अधिक लीवरेज युक्त होने के साथ ही साथ उन पर ब्याज भार²² भी अधिक रहा (चार्ट 1.19)।

चार्ट 1.19 : चुनिंदा उद्योगों का जोखिम प्रोफाइल (सितंबर 2015)



टिप्पणी : बुलबुला का आकार प्रतिदर्श कंपनियों से व्युत्पन्न सभी उद्योगों के कुल कर्ज में उद्योग के कर्ज के तुलनात्मक हिस्से पर आधारित है।

स्रोत : भारिबैं (चुनिंदा सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों के छमाही विवरण)।

²¹ बैंक उधारियां कुल उधारियों का एक हिस्सा निर्मित करती हैं, जिसमें अल्पावधि के साथ ही साथ दीर्घावधि उधारियां -दोनों ही शामिल हैं।

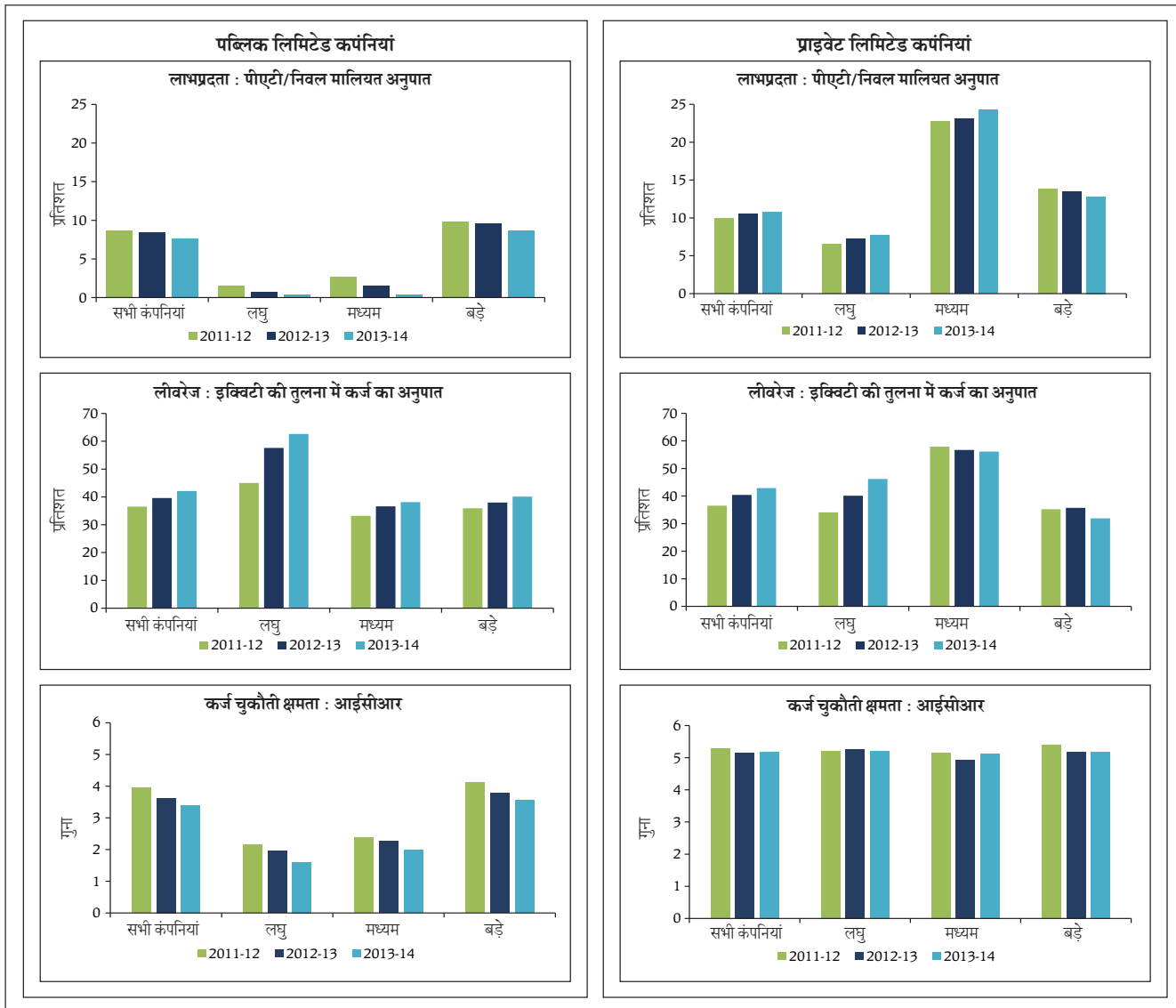
²² ब्याज भार को ईबीआईटीडीए के प्रतिशत के रूप में ब्याज पर व्यय के रूप में परिभाषित किया गया।

वित्तीय सेहत : विशाल डेटाबेस पर आधारित

1.21 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान बड़े नमूने²³ का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के व्यापक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि इस अवधि की शुरुआत में देखा गया दबाव निरंतर चिंता का विषय बना रहा।²⁴ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में गिरावट की

प्रवृत्ति देखी गई, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की लाभप्रदता में मामूली सुधार देखा गया, यद्यपि बड़ी²⁵ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की लाभप्रदता में गिरावट दर्ज की गई है। सामान्यतः लीवरेज अनुपात, विशेष रूप से, छोटी कंपनियों के लीवरेज अनुपात में वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई, जबकि मध्यम और बड़ी कंपनियों के मामले में इस अनुपात में गिरावट देखी गई (चार्ट 1.20)।

चार्ट 1.20: कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संकेतक : आकार के अनुसार वर्गीकरण



स्रोत: एमसीए डाटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियाँ)

²³ कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का अध्ययन कंपनी मामले मंत्रालय के बड़े डाटाबेस के भाग का उपयोग करके किया गया था, जिसमें 19,478 एनजीएनएफ पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ और 255,426 एनजीएनएफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ शामिल थीं।

²⁴ लाभप्रदता के लिए इस्तेमाल किया गया संकेतक निवल मालियत अनुपात की तुलना में कर पश्चात लाभ है (पीएटी/एनडब्ल्यू)। लीवरेज के लिए, संकेतक इक्विटी (निवल मालियत को लिया गया है) की तुलना में दीर्घावधि उधारी अनुपात है, जबकि कर्ज चुकौती क्षमता की माप ब्याज पर किए गए व्यय की तुलना में ईबीआईटीडीए के रूप में ब्याज कवरेज अनुपात द्वारा की गई है।

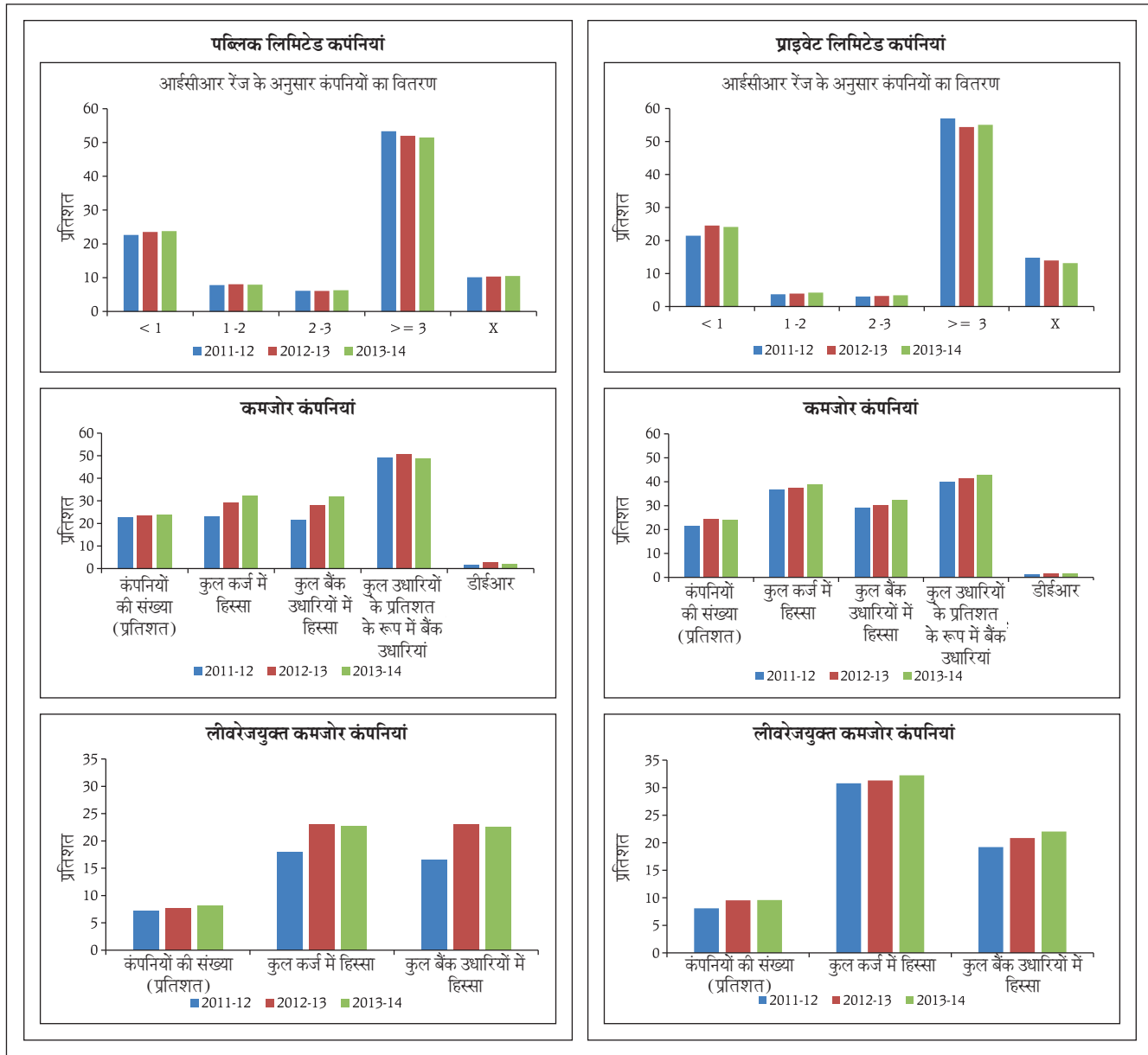
²⁵ कंपनियों का वर्गीकरण उनके बिक्री-आकार के अनुसार किया गया है। ₹250 मिलियन से कम बिक्री (वार्षिक) वाली कंपनियों को छोटी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है; ₹250 मिलियन से ₹1 बिलियन के बीच बिक्री वाली कंपनियों को मध्यम कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया और ₹1 बिलियन और उससे अधिक की बिक्री वाली कंपनियों को बड़ी कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.22 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए आईसीआर के संदर्भ में मापी गई कर्ज चुकौती क्षमता में गिरावट देखी गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में मध्यम आकार वाली कंपनियों के आईसीआर में वृद्धि देखी गई, यद्यपि, छोटी कंपनियों के मामले में मामूली गिरावट आयी, प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनियों के मामले में आईसीआर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है (चार्ट 1.20)।

कर्ज चुकौती क्षमता और लीवरेज

1.23 एमसीए डाटा का उपयोग करते हुए एक विश्लेषण किया गया था ताकि कमजोर और लीवरेजयुक्त कमजोर कंपनियों का तथा कुल कर्ज एवं बैंक उधारियों में उनके हिस्से का निर्धारण किया जा सके (चार्ट 1.21)।

चार्ट 1.21: एनजीएनएफ कमजोर कंपनियां



टिप्पणी: X उन कंपनियों को दर्शाती है जिनकी उधारियाँ शून्य हैं।
 स्रोत: एमसीए डेटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)।

1.24 विश्लेषण से पता चलता है कि 4,635 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां (23.8 प्रतिशत) और 61,557 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (24.1 प्रतिशत) 2013-14 में चुनिंदा नमूने के अनुसार 'कमजोर' थीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए डीईआर 2012-13 के 3.0 से घटकर 2013-14 में 2.2 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए डीईआर 1.5 से घटकर 1.4 हो गया था। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए कुल उधारियों में बैंक उधारियों का हिस्सा लगभग 49 प्रतिशत और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए 43 प्रतिशत था। इस समूह की कुल बैंक उधारियों में कमजोर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का हिस्सा 32.1 प्रतिशत रहा। उसी प्रकार, 2013-14 में सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की कुल बैंक उधारियों में से कमजोर प्राइवेट लिमिटेड का बैंक उधारियों में हिस्सा 32.5 प्रतिशत रहा। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में, कुल बैंक उधारियों में लीवरेजयुक्त कमजोर कंपनियों की बैंक उधारियों का हिस्सा 22.6 प्रतिशत था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए लीवरेजयुक्त कमजोर कंपनियों के मामले में बैंक उधारियों का हिस्सा 22.8 प्रतिशत था (चार्ट 1.21)।

बैंक ऋण पर प्रभाव

1.25 लीवरेजयुक्त कंपनियों की निम्न कर्ज चुकौती क्षमता एवं उच्च लीवरेज, प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंक ऋणों की पहले से ही खराब आस्ति गुणवत्ता पर दबाव डाल सकते हैं। सभी एनजीएनएफ कंपनियों को अधिसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का ऋण, मार्च 2014 के अंत में कुल बैंक ऋण का लगभग 32.4 प्रतिशत था। इसलिए, कमजोर एनजीएनएफ कंपनियों की कल्पित चूक के कारण समग्र प्रभाव²⁶ एससीबी के कुल बैंक ऋण का लगभग 10.4 प्रतिशत हो सकता है। यह प्रभाव ऋण-भारित कमजोर एनजीएनएफ कंपनियों की कल्पित चूक के मामले में 7.3 प्रतिशत हो सकता है (सारणी 1.3)। फिर भी, इन कंपनियों को बैंक ऋण का एक भाग बैंकों के मौजूदा दबावग्रस्त अग्रिमों (अनर्जक अग्रिम या पुनर्चित मानक अग्रिम) का पहले से ही हिस्सा हो सकता है।

1.26 इस संदर्भ में, इस पर ध्यान देना उचित है कि यह स्थिति 2013-14 के एमसीए आंकड़ों पर आधारित है और 2014-15 के छोटे से नमूने एवं 2015-16 की पहली और दूसरी तिमाही (चयनित एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां) हेतु नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 'परिचालन लाभ', 'ईबीआईटीडीए' के साथ ही 'निवल लाभ' के संदर्भ में मापी गई लाभप्रदता में थोड़ा सा सुधार हुआ, जैसा अध्याय में पहले चर्चा की गई है (पैरा 1.14)।

सारणी 1.3: बैंक ऋण के संबंध में एनजीएनएफ कंपनियों की कर्ज चुकौती क्षमता में कमजोरी का प्रभाव

(अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बैंक ऋण में बैंक ऋण का हिस्सा)

(प्रतिशत)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14
सभी एनजीएनएफ कंपनियां	31.9	31.5	32.4
कमजोर कंपनियां	7.4	9.0	10.4
ऋण-भारित कमजोर कंपनियां	5.5	7.1	7.3

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मूल सांख्यिकीय विवरणियां (बीएसआर) और एमसीए डाटाबेस (चुनिंदा एनजीएनएफ कंपनियां)

²⁶ ब्योरे अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और लचीलापन

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के कारोबार की वृद्धि मंद हुई, जैसा कि जमा राशि और ऋण-दोनों की वृद्धि में और गिरावट से भी पता चलता है। मार्च 2015 और सितंबर 2015 के बीच सकल अनजर्क अग्रिम अनुपात (जीएनपीए) में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पुनर्चित मानक अग्रिम अनुपात में गिरावट आई। 2015-16 के पूर्वार्द्ध के दौरान एससीबी के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात में थोड़ी गिरावट आई। बैंक समूहों के अंतर्गत सरकारी बैंकों का सीआरएआर न्यूनतम बना रहा। एससीबी की लाभप्रदता में आगे और गिरावट आई। 2015-16 के पूर्वार्द्ध के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) -दोनों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई।

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र से पता चलता है कि सितंबर 2015 को समाप्त छमाही के दौरान आस्ति गुणवत्ता में कमी आने, अपेक्षाकृत कम सुदृढ़ता और लाभप्रदता में गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़ गया है। दबाव परीक्षण लचीलेपन को दर्शाता है किंतु समष्टिगत आर्थिक स्थितियां तेजी से बिगड़ने पर बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो सकती है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक¹

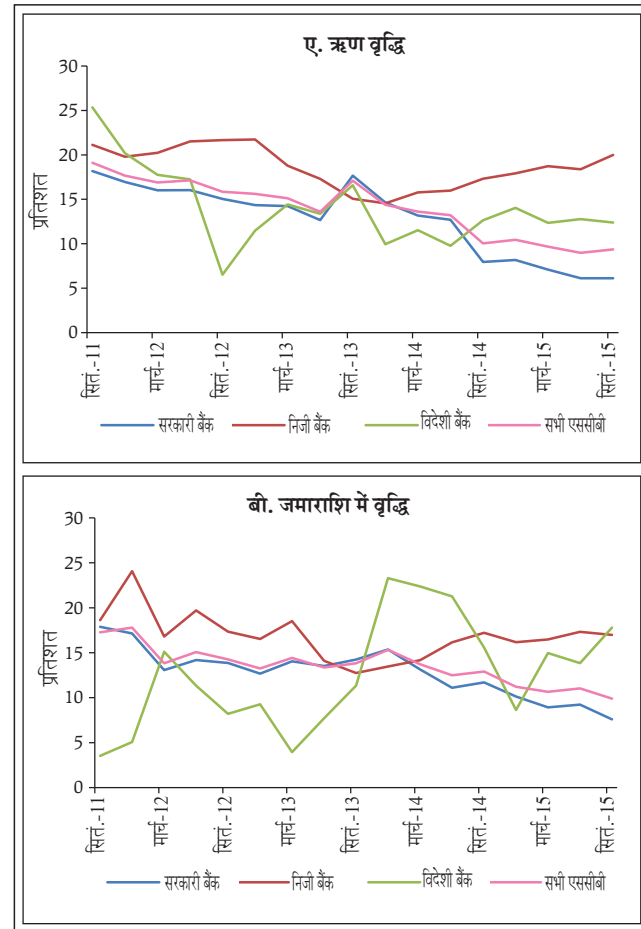
2.1 इस भाग में, दो व्यापक उप शीर्षों : विभिन्न व्यावहारिक पक्षों के संबंध में बैंकों का कार्यनिष्पादन तथा उनके लचीलेपन के अंतर्गत परिदृश्यों और एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण के जरिए समष्टिगत दबाव परीक्षणों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों² (एससीबी) की सुदृढ़ता और लचीलेपन पर चर्चा की गई है।

कार्यनिष्पादन

ऋण और जमा राशि में वृद्धि

2.2 जहां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण वृद्धि 9.7 प्रतिशत से घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई, वहीं मार्च 2015 और सितंबर 2015 के बीच जमा राशि में वृद्धि 10.7 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत रह गई। बैंक-समूहों में, जहां सरकारी क्षेत्र के बैंक में जमा राशि और ऋण वृद्धि के निष्पादन में मंदी जारी रही, वहीं निजी बैंकों और विदेशी बैंकों ने इसी अवधि के दौरान में काफी वृद्धि दर्ज की है (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: ऋण और जमा राशि में वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष आधार पर



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

¹ अध्याय के अंतर्गत किया गया विश्लेषण नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

² विश्लेषण पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित है, जिनमें सिर्फ घरेलू परिचालन शामिल हैं।

2.3 व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत, 'उद्योगों' को दिए गए ऋण में गिरावट आई, इसका मुख्य कारण मध्यम और बड़े उद्योगों को दिए गए ऋण के हिस्से में गिरावट आना रहा। कुल ऋण के अंतर्गत खुदरा वर्ग के हिस्से में वृद्धि दर्ज की गई है (चार्ट 2.2)।

सुदृढ़ता

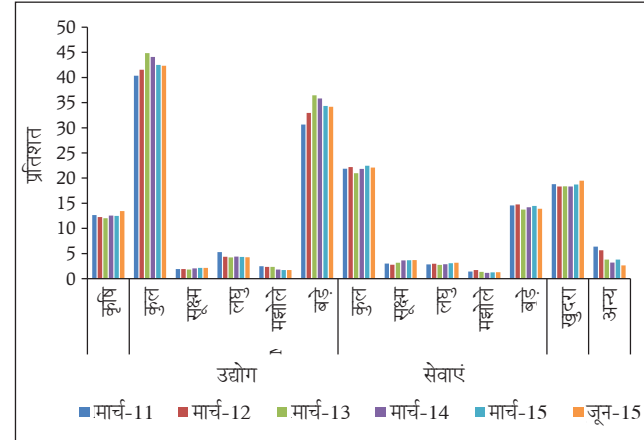
पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज

2.4 मार्च और सितंबर 2015 के बीच प्रणालीगत स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 13.0 प्रतिशत से घटकर 12.7 प्रतिशत रह गया, जबकि इसी अवधि के दौरान टियर 1 लीवरेज अनुपात³ 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.3 और 2.4)।

आस्ति गुणवत्ता

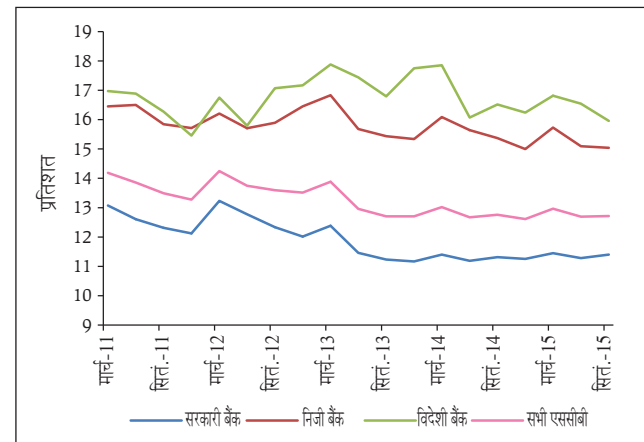
2.5 सकल अग्रिम के प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम⁴ (जीएनपीए) मार्च और सितंबर 2015 के बीच 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गया। सकल अग्रिम के प्रतिशत की तुलना में पुनर्चित मानक अग्रिम 6.4 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि के दौरान दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया। सबसे अधिक 14.1 प्रतिशत की दबावग्रस्त आस्तियां⁵ सरकारी क्षेत्र के बैंकों की रही जबकि उसके बाद 4.6 प्रतिशत के साथ निजी बैंकों का क्रम आता है और फिर 3.4 प्रतिशत के साथ विदेशी बैंकों का क्रम आता है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए कुल निवल अग्रिम के प्रतिशत की तुलना में निवल अनर्जक अग्रिम (एनएनपीए) इसी अवधि के दौरान 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया। बैंक समूह स्तर पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एनएनपीए अनुपात 3.2 प्रतिशत

चार्ट 2.2: कुल ऋण में क्षेत्रगत ऋण का हिस्सा



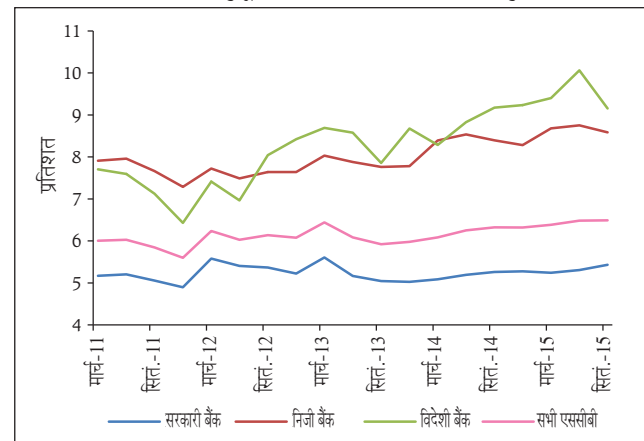
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.3: पूंजी पर्याप्तता



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लीवरेज अनुपात



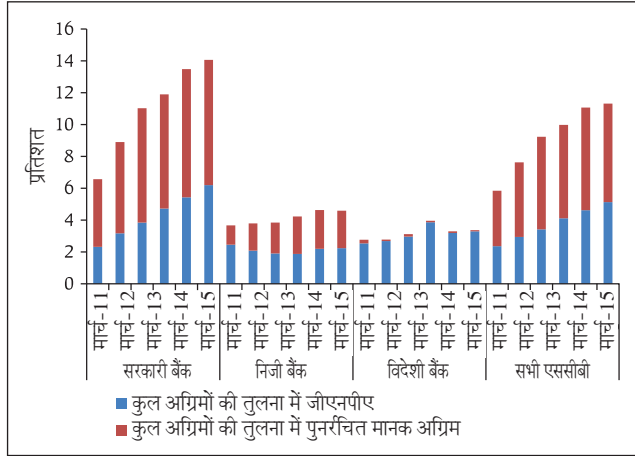
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

³ टियर 1 लीवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में टियर 1 पूंजी अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल आस्तियों में तुलनपत्र से इतर मर्दों के तुल्य ऋण शामिल हैं।

⁴ यहां पर अग्रिम और ऋण शब्दों को आपस में प्रतिस्थापित किए जाने योग्य किया गया है।

⁵ आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए दबावग्रस्त अग्रिमों को जीएनपीए और पुनर्चित मानक अग्रिमों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट 2.5 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया जबकि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित यह अनुपात क्रमशः 0.9 और 0.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा (चार्ट 2.5 और 2.6)।

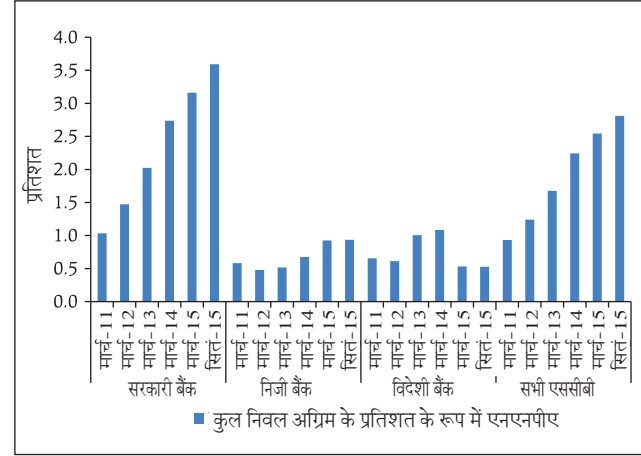
2.6 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, अग्रिम में 12 प्रतिशत हिस्से के साथ 34 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में बहुत कम अर्थात् 2 प्रतिशत से कम दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात दर्ज किया गया, जबकि अग्रिम में 27 प्रतिशत हिस्से के साथ 16 बैंकों ने बहुत अधिक अर्थात् 16 प्रतिशत से अधिक दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात दर्ज किया (चार्ट 2.7)।

2.7 जून 2015 के क्षेत्रगत आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग लगभग 19.5 प्रतिशत के दबावग्रस्त अग्रिमों के साथ पहले पायदान रहा है, उसके बाद 7 प्रतिशत के साथ सेवा क्षेत्र रहा है। खुदरा क्षेत्र में सबसे कम अर्थात् 2 प्रतिशत का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात दर्ज किया गया। आकार की दृष्टि से, मध्यम और बड़े उद्योग -दोनों में 21 प्रतिशत के दबावग्रस्त अग्रिम दर्ज किए गए, जबकि सूक्ष्म आकार वाले उद्योगों के संबंध में अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक रहा (चार्ट 2.8)।

2.8 पांच उप क्षेत्रों अर्थात् खनन, लोहा और इस्पात, वस्त्र, आधारभूत संरचना और विमानन जिनका जून 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिम में 24.2 प्रतिशत का हिस्सा है, ने कुल दबावग्रस्त अग्रिम में 53.0 प्रतिशत की भागीदारी की है। विमानन क्षेत्र⁶ में दबावग्रस्त अग्रिम मार्च के 58.9 प्रतिशत से बढ़कर जून 2015 में 61.0 प्रतिशत हो गया, और इसी

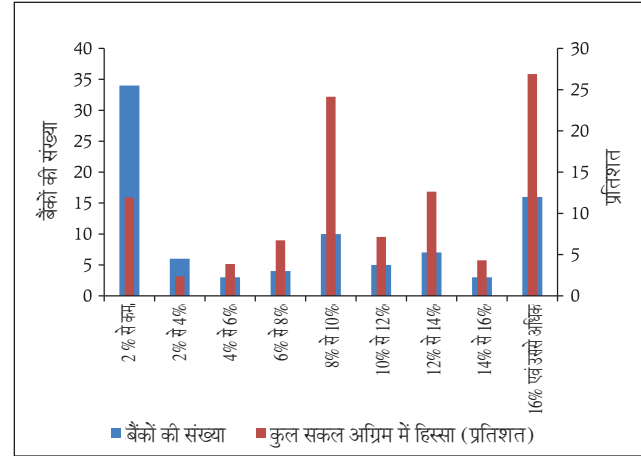
⁶ विमानन उद्योग में विश्वव्यापी बहाली होने के बावजूद भारत के संदर्भ कुछ प्रतिभागी कंपनियों के कारण दबाव जारी है।

चार्ट 2.6 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनएनपीए



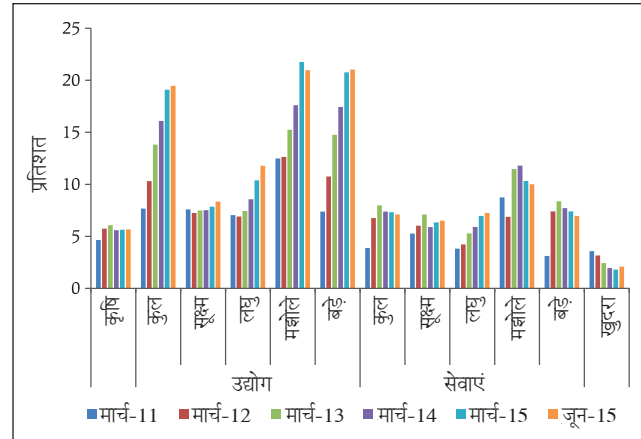
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.7: दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात आधारित एससीबी का वितरण (सितंबर 2015)



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.8: व्यापक क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

अवधि के दौरान आधारभूत संरचना क्षेत्र के दबावग्रस्त अग्रिम 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 24.0 प्रतिशत हो गए। इन क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन और बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में इनका प्रभाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है (चार्ट 2.9)।

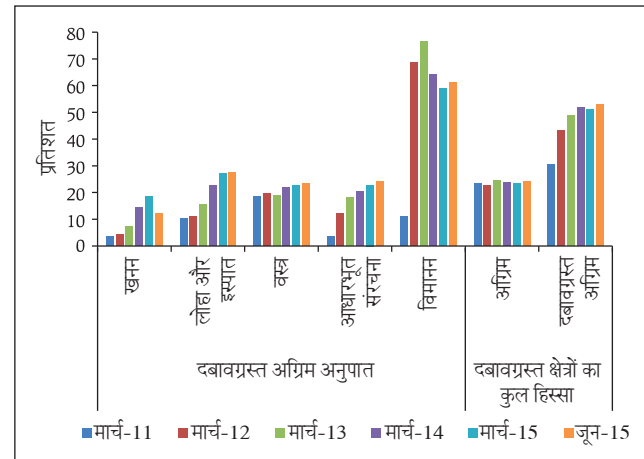
बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता⁷

2.9 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को नियंत्रित करने की प्रणाली को सक्रिय और समन्वित करने के अधिदेश के साथ और बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की समस्या का समाधान करने के अपने लगातार और स्थायी प्रयास में जनवरी 2014 में ‘अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने संबंधी ढांचे’⁸ की शुरुआत की है ताकि सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के लिए पारदर्शी ऋण सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इस पहल के रूप में, रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने, स्टोर करने और ऋणदाताओं में प्रसारित करने के लिए बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) की स्थापना की है। सीआरआईएलसी के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं - (i) सूचना असममिति को कम करके आस्ति गुणवत्ता की समस्याओं की समय रहते पहचान करना, और (ii) सुविज्ञ ऋण निर्णय लेने के लिए बैंकों की मदद करना। बैंकों को कुल ₹50 मिलियन और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर रखने वाले अपनी सभी उधारकर्ताओं के बारे में सीआरआईएलसी को ऋण संबंधी सूचना देनी होगी।

2.10 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए अनुपात मार्च 2015 के 6.1 प्रतिशत से काफी बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली का जीएनपीए अनुपात बढ़ गया। तथापि, विदेशी बैंकों के जीएनपीए अनुपात में इसी अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 2.10)।

2.11 बड़े उधारकर्ताओं की मानक आस्तियां मार्च 2015 के कुल सकल अग्रिम का 86.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2015 को 84.5 प्रतिशत रह गईं। शीर्ष 100 उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण कुल बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में 27.6 प्रतिशत रहा और सभी एससीबी के ऋण का 17.8 प्रतिशत था। सभी एससीबी के कुल जीएनपीए में इन उधारकर्ताओं का जीएनपीए का

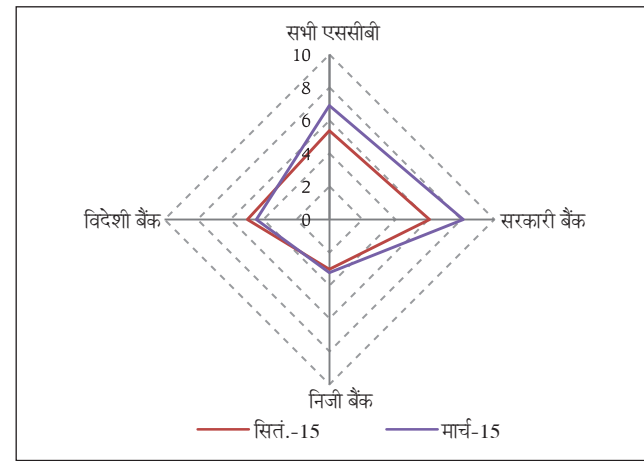
चार्ट 2.9: दबावग्रस्त क्षेत्रों में दबावग्रस्त अग्रिम



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.10: बड़े उधारकर्ताओं के जीएनपीए अनुपात

(सकल अग्रिम का प्रतिशत)



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

⁷ 50 मिलियन और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर रखने वाले उधारकर्ता को बड़े उधारकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है।

⁸ <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NPA300114RFF.pdf>.

हिस्सा मार्च 2015 के 0.7 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.1)।

2.12 कुल जीएनपीए की तुलना में बड़े उधारकर्ताओं के जीएनपीए के हिस्से में मार्च 2015 के 78.2 प्रतिशत से सितंबर 2015 में तेजी से बढ़कर 87.4 प्रतिशत होना ऋण देने वाली संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है (सारणी 2.1)।

लाभप्रदता

2.13 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) -दोनों में मार्च 2015 के 0.8 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत से सितंबर 2015 में क्रमशः घटकर 0.7 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत रह गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के दौरान एससीबी के कर पश्चात लाभ में 4.4 प्रतिशत का गिरावट आई, इसका मुख्य कारण प्रावधान और कर-पूर्व अर्जन में कम वृद्धि तथा प्रावधान और राइट-ऑफ में उच्च वृद्धि का होना रहा (सारणी 2.2)। बैंक समूहों के बीच, सरकारी बैंकों से संबंधित पीएटी में 22.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि समान अवधि के दौरान इसमें निजी बैंकों के मामले में 11.5 प्रतिशत की तथा विदेशी बैंकों के मामले में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

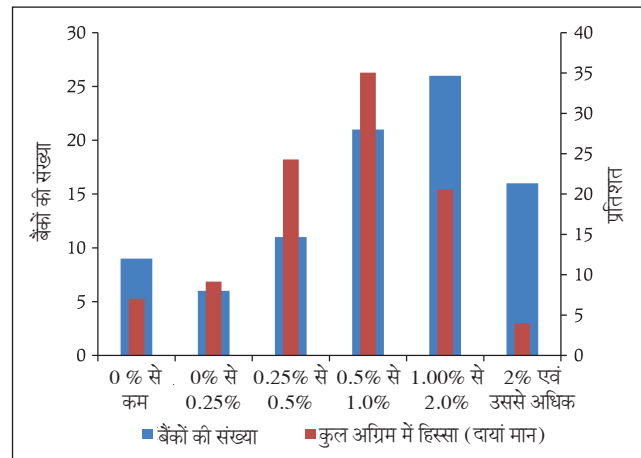
2.14 आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत) के बैंक-वार वितरण से पता चलता है कि कुल आस्तियों में 7 प्रतिशत हिस्से के साथ 9 एससीबी ने 2015-16 की पहली छमाही के दौरान ऋणात्मक आरओए दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुल आस्तियों में 9 प्रतिशत के हिस्से के साथ 6 बैंकों ने शून्य प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत के बीच आरओए दर्ज किया गया (चार्ट 2.11)।

सारणी 2.1: एससीबी का बड़े उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर

	मार्च-15	सित-15*
i. कुल सकल अग्रिमों की तुलना में बकाया निधिक राशि	65.4	64.5
ii. कुल जीएनपीए की तुलना में बकाया निधिक राशि में जीएनपीए	78.2	87.4
बड़े उधारकर्ताओं की बकाया कुल निधिक राशि की संरचना		
i. मानक	86.2	84.5
ii. पुनर्रचित मानक	8.4	8.6
ii. अवमानक	1.7	1.9
iv. संदिग्ध	3.0	4.2
v. हानि	0.7	0.8
शीर्ष 100 उधारकर्ता		
i. कुल निधि आधारित एक्सपोजर की तुलना में बड़े उधारकर्ताओं का निधि आधारित एक्सपोजर	28.1	27.6
ii. कुल सकल अग्रिम की तुलना में निधि आधारित एक्सपोजर	18.3	17.8
iii. कुल निधि आधारित एक्सपोजर की तुलना में बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए	0.8	3.5
iv. एससीबी के कुल जीएनपीए की तुलना में निधि आधारित एक्सपोजर में जीएनपीए	0.7	3.1

* अर्न्तम आंकड़े
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.11: आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) आधारित एससीबी का वितरण (वार्षिकीकृत) (सितंबर 2015)



टिप्पणी: सितंबर 2015 को आस्तियों पर माध्यिका प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत) 0.94 प्रतिशत था।
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 2.2: एससीबी की लाभप्रदता

	आस्तियों पर प्रतिलाभ	इक्विटी पर प्रतिलाभ	पीएटी की वृद्धि	प्रावधानीकरण एवं कर वृद्धि पूर्व अर्जन	निवल ब्याज आय में वृद्धि	अन्य परिचालगत आय में वृद्धि	जोखिम प्रावधान में वृद्धि	बढ़ा खातों में वृद्धि
मार्च-11	1.1	13.6	23.6	21.7	34.6	0.5	38.6	-50.6
मार्च-12	1.1	13.4	14.6	15.3	15.8	7.4	35.6	-13.1
मार्च-13	1.0	12.9	12.9	9.9	10.8	14.4	10.2	-8.5
मार्च-14	0.8	9.5	-14.1	9.5	11.7	16.6	41.9	80.3
मार्च-15	0.8	9.3	10.1	11.4	8.5	17.4	7.0	23.4
सित-11	0.7	8.5	-4.4	8.8	8.6	11.0	22.2	49.2

टिप्पणी: आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ के वार्षिकीकृत आंकड़े हैं जबकि वृद्धियों की गणना वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की गई है।
 स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

समष्टिगत दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम⁹

2.15 समष्टि आर्थिक आघातों की तुलना में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लचीलापन प्रणाली, बैंक-समूह और क्षेत्रगत स्तर पर उधार जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षण की श्रृंखला के अंतर्गत है। इन परीक्षणों में कल्पित जोखिम परिदृश्य शामिल हैं जिसमें मध्यम और अत्यधिक जोखिम को दर्शाने वाली एक आधार रेखा और दो प्रतिकूल समष्टि आर्थिक परिदृश्य शामिल हैं (सारणी 2.3)। प्रतिकूल परिदृश्य का आधार मध्यम जोखिम के लिए एक मानक विचलन (एसडी) तक और अत्यधिक जोखिम के लिए दो मानक विचलन (10 वर्ष के महत्वपूर्ण आंकड़े)¹⁰ तक लिया गया है।

प्रणालीगत स्तरीय ऋण जोखिम

2.16 ऋण जोखिम के समष्टिगत दबाव परीक्षण से पता चलता है कि आधार रेखा परिदृश्य के तहत जीएनपीए अनुपात सितंबर 2015 के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2016 में 5.4 प्रतिशत हो सकता है, किंतु बाद में मार्च 2017 तक इसके सुधार के साथ 5.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। तथापि, यदि समष्टि आर्थिक

सारणी 2.3 : समष्टि आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत मान्यताएं¹¹

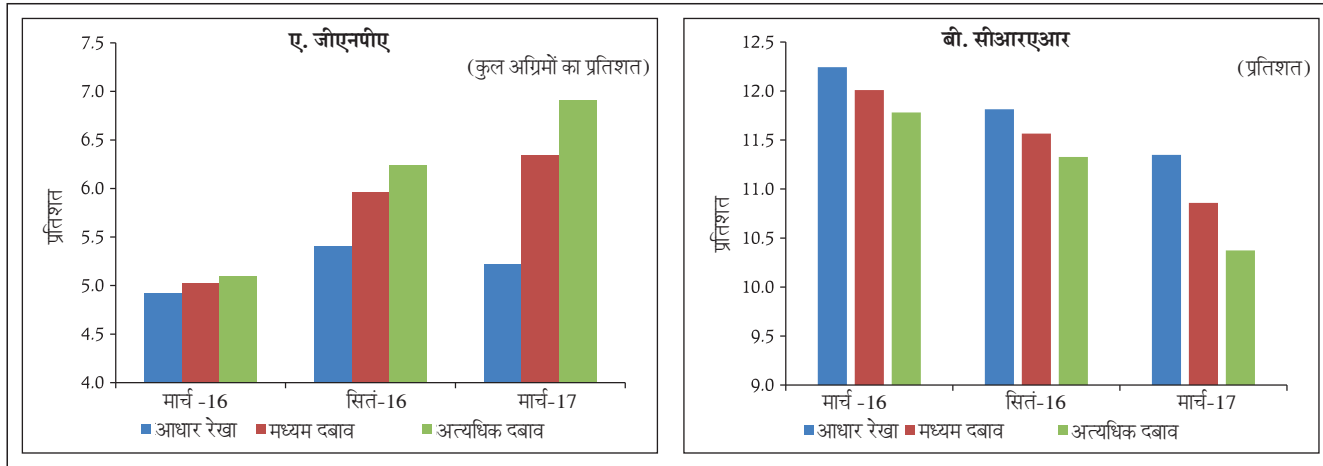
(प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष		आधार रेखा	मध्यम दबाव	अत्यधिक दबाव
2015-16	आधार मूल्य पर जीवीए में वृद्धि	7.3	5.7	3.7
	जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा अनुपात	3.9	4.7	5.7
	सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति	5.7	7.1	8.8
	भारत औसत उधार दर	11.8	12.3	12.8
	जीडीपी की तुलना में पण्य निर्यात अनुपात	14.9	13.8	12.4
	जीडीपी की तुलना में चालू घाटा शेष अनुपात	-1.1	-2.0	-3.9
2016-17	आधार मूल्य पर जीवीए में वृद्धि	7.8	5.2	2.7
	जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा अनुपात	3.5	4.8	6.1
	सीपीआई (संयुक्त मुद्रास्फीति)	5.5	7.8	10.0
	भारत औसत उधार दर	11.8	12.5	13.2
	जीडीपी की तुलना में पण्य निर्यात अनुपात	14.8	13.0	11.3
	जीडीपी की तुलना में चालू घाटा शेष अनुपात	-1.3	-2.7	-5.5

टिप्पणी: जीवीए = योजित सकल मूल्य

स्थितियों में गिरावट आती है, तो जीएनपीए अनुपात में आगे वृद्धि हो सकती है और इसके चलते अत्यधिक दबाव परिदृश्य के तहत मार्च 2017 तक यह बढ़कर लगभग 6.9 प्रतिशत हो सकता है। इस प्रकार के परिदृश्य के तहत एससीबी का प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर सितंबर 2015 के 12.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2017 तक 10.4 प्रतिशत रह सकता है (चार्ट 2.12)।

चार्ट 2.12 : प्रणालीगत स्तर पर एससीबी के जीएनपीए तथा सीआरएआर का अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



टिप्पणी : 1. प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए का अनुमान तीन अलग-अलग, किंतु पूरक अर्थमतिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए, किया गया है : मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, वेक्टर आटोरिग्रेसिव (जिसमें, समष्टि चरों की ऋण गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया के प्रभाव तथा संपर्क प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है) एवं क्वॉटाइल रिग्रेशन (जो टेल/पुच्छ जोखिम का समाना कर सकता है तथा समष्टिआर्थिक आघातों के अरैखिक प्रभावों को ध्यान में रख सकता है)। तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए उपर्युक्त चार्ट में दिया गया है।

2. सीआरएआर का अनुमान परंपरागत पूर्वानुमान के तहत पूंजी रिजर्व में न्यूनतम लाभ अंतरण 25 प्रतिशत की दर पर किया गया है।

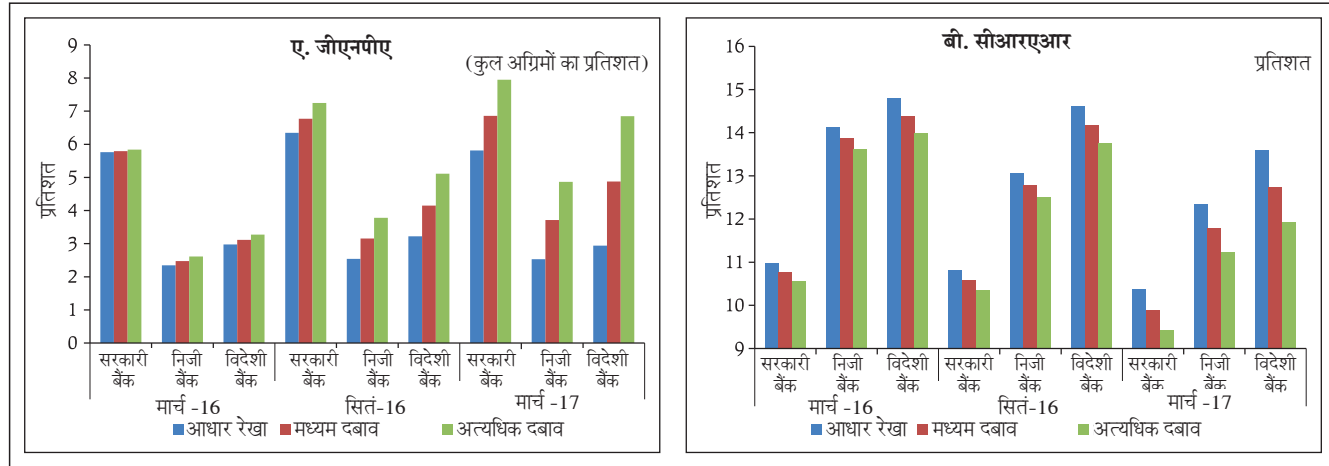
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

⁹ विस्तृत कार्यप्रणाली अनुबंध 2 में दी गई है।

¹⁰ आघातों (मानक विचलन के गुणक के रूप में) का परिमाण समय (तिमाही अवधि) के साथ बढ़ता है।

¹¹ ये दबावग्रस्त परिदृश्य कठोर और रूढ़िवादी मूल्यांकनपरक हैं जो कि कल्पित हैं। यहां संदर्भ में शामिल अनेक प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों की व्याख्या पूर्वानुमान अथवा प्रत्याशित परिणामों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

चार्ट 2.13: बैंक समूह-वार जीएनपीए अनुपात एवं सीआरएआर के अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



टिप्पणी : 1. बैंक समूह-वार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग, किंतु पूरक अर्थमिक्तिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए किया गया है, : मल्टीवेरिफाई रिग्रेसन तथा वेक्टर आटोरिग्रेसिव। दोनों मॉडलों का औसत जीएनपीए उपर्युक्त चार्ट में दिया गया है।
2. सीआरएआर का अनुमान परंपरागत पूर्वानुमान के तहत पूंजी रिजर्व में न्यूनतम लाभ अंतरण 25 प्रतिशत की दर पर किया गया है। इसमें हित धारकों द्वारा किया गया किसी प्रकार का पूंजी अंतर्वेशन शामिल नहीं है।
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

बैंक समूह स्तर पर ऋण जोखिम

2.17 बैंक-समूहों में, सरकारी बैंकों का जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक बना रह सकता है। आधार रेखा परिदृश्य के तहत उनका जीएनपीए अनुपात सितंबर 2015 के 6.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2016 को 6.3 प्रतिशत हो सकता है और उसके बाद यह मार्च 2017 में सुधार के साथ 5.8 प्रतिशत हो सकता है। तथापि, अत्यधिक दबाव परिदृश्य के तहत यह मार्च 2017 तक बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो सकता है। आधार रेखा परिदृश्य के तहत निजी बैंकों का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2015 के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 तक 2.5 प्रतिशत हो सकता है, किंतु अत्यधिक दबाव परिदृश्य के तहत यह बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.13)।

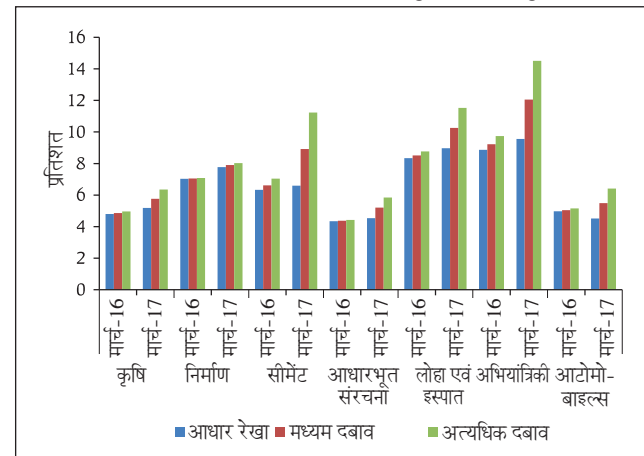
2.18 अत्यधिक दबाव परिदृश्य के तहत सरकारी बैंक सितंबर 2015 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 तक लगभग 9.4 प्रतिशत का सबसे कम सीआरएआर दर्ज कर सकते हैं (चार्ट 2.13)।

क्षेत्रगत उधार जोखिम

2.19 क्षेत्रगत ऋण जोखिम के लिए किए गए समष्टिगत दबाव परीक्षण से पता चलता है कि अत्यधिक दबावग्रस्त परिदृश्य में, चुनिंदा सात क्षेत्रों में अभियांत्रिकी, जिसका सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार 8.5 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक जीएनपीए अनुपात

था, मार्च 2017 तक बढ़कर जीएनपीए अनुपात 14.5 प्रतिशत तक हो सकता है, उसके बाद लोहा और इस्पात (8.4 प्रतिशत से बढ़कर 11.5 प्रतिशत) और सीमेंट (6.4 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत) का क्रम आता है (चार्ट 2.14)।

चार्ट 2.14: विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए (कुल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत)



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

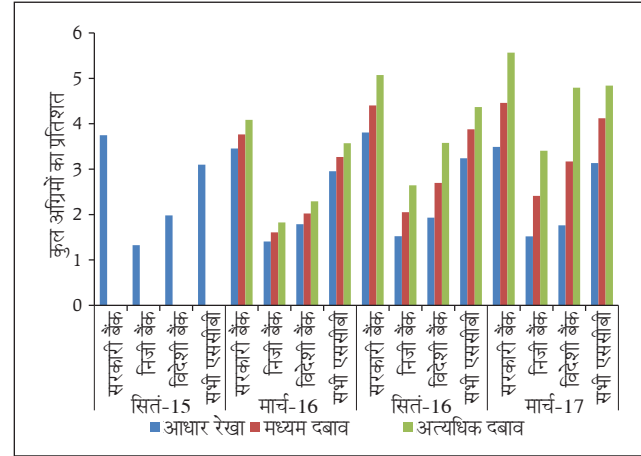
ऋण जोखिम के लिए हानियों² का अनुमान : प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता

2.20 कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में अनेक बैंक समूहों का प्रावधानीकरण¹³ स्तर सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार सरकारी बैंकों के लिए 3.8 प्रतिशत, निजी बैंकों के लिए 2.0 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 3.6 प्रतिशत था जो कि आधार रेखा परिदृश्य में उनके अनमानित प्रत्याशित हानि (ईएल) से अधिक है। कुल अग्रिम की तुलना में सरकारी बैंकों का ईएल सबसे अधिक रहा और अत्यधिक दबाव परिदृश्य के तहत मौजूदा प्रावधानीकरण स्तर सामान्यतः ईएल को प्राप्त करने में कम प्रतीत होता है¹⁴ (चार्ट 2.15)।

2.21 अत्यधिक समष्टिगत आर्थिक दबावपूर्ण परिस्थितियों के तहत उधार जोखिम के चलते अनेक बैंक समूहों की अनमानित अप्रत्याशित हानियां (यूएल) और प्रत्याशित कमियां (ईएल) कुल पूंजी (टियर I + टियर II) के अपने मौजूदा स्तर से काफी कम रहने की संभावना है। कुल अग्रिम¹⁵ के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का स्तर मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सरकारी बैंकों के लिए 13.1 प्रतिशत, निजी बैंकों के लिए 20.6 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 33.3 प्रतिशत रहा (चार्ट 2.16)।

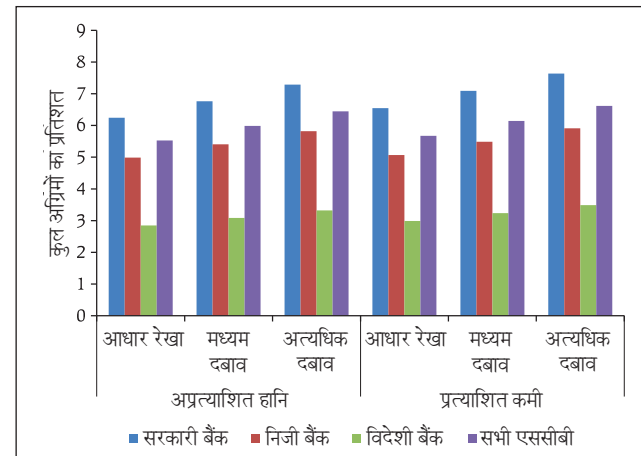
2.22 ईएल और यूएल के बैंक-वार¹⁶ अनुमानों (चुनिंदा 60 बैंक) से पता चलता है कि 19 बैंक (एफएसआर जून 2015 में दर्ज 16 बैंकों की तुलना में), जिनका कुल अग्रिमों में 36.2 हिस्सा था, अपने मौजूदा प्रावधानों के साथ अपनी प्रत्याशित हानियों की भरपाई करने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर, पांच ऐसे बैंक (चुनिंदा बैंकों के कुल अग्रिम में 2.4 प्रतिशत हिस्से के साथ) थे, जिनमें उनकी कुल पूंजी की

चार्ट 2.15: संभावित हानियां : बैंक समूह-वार



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 2.16: अप्रत्याशित हानि और प्रत्याशित कमियां : बैंक समूह-वार (सितंबर 2015)



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

¹² हानियों का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण अनुबंध 2 में दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह सिफारिश की गई है कि अनुमानित हानियों (ईएल+यूएल) के दृष्टिकोण को एक वर्ष आगे की अवधि के लिए प्रावधान करने और पूंजी जुटाने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए, चूक संभाव्यता (पीडी) की गणना वार्षिक स्लीपेज के आधार पर की गई। चूंकि इस अध्ययन का उद्देश्य एससीबी द्वारा किए जा रहे प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता स्तर की जांच करना है, न कि अगले वर्ष के लिए रखे जाने वाले प्रावधानों और पूंजी के अपेक्षित स्तर का अनुमान लगाना। यहां पर पीडी का प्रयोग जीएनपीए पर आधारित है।

¹³ प्रावधानों में ऋण हानियों के लिए प्रावधान, मानक अग्रिमों के लिए जोखिम प्रावधान और पुनर्रचित मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

¹⁴ दबाव परिदृश्यों को समष्टि-दबाव परीक्षण के तहत सारणी 2.3 में परिभाषित किया गया है।

¹⁵ तुलना करने के लिए यूएल और ईएल तथा कुल पूंजी को कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में दिया गया है। सभी बैंक-समूहों में कुल अग्रिम अनुपात की तुलना में कुल पूंजी तुलनीय नहीं है क्योंकि निवेश और तुलनपत्र में शामिल नहीं की गई मदों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

¹⁶ ईएल और यूएल का बैंक-वार अनुमान 60 एससीबी के लिए किया गया था जिसमें एससीबी की कुल आस्तियों का 99 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अप्रत्याशित हानियां होने की संभावना थी (चार्ट 2.17)।

संवेदनशीलता विश्लेषण : बैंक स्तर¹⁷

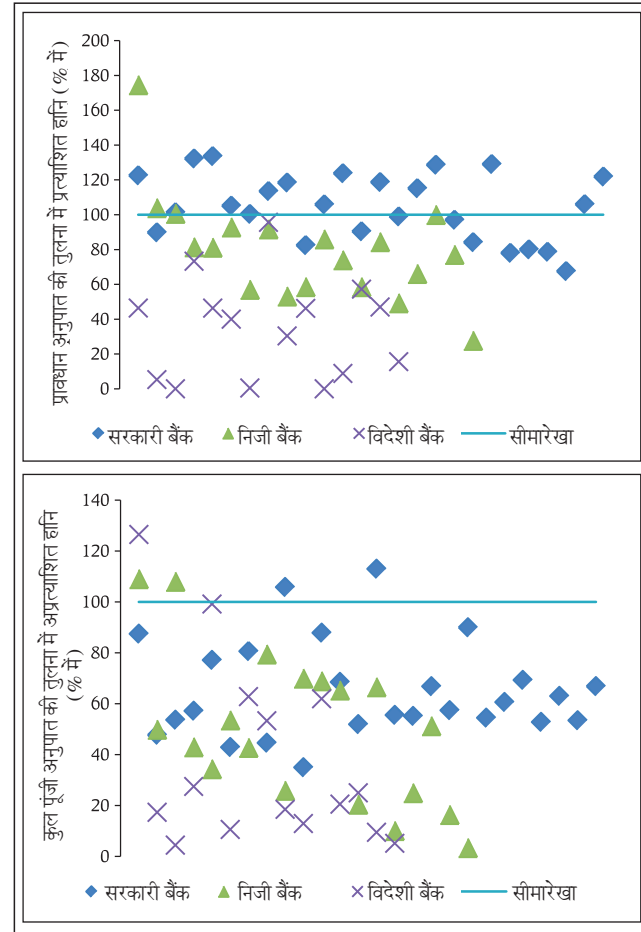
2.23 सितंबर 2015 के आंकड़ों के आधार पर अनेक एकल कारक संवेदनशीलता दबाव परीक्षण¹⁸ (टॉप-डाउन) चुनिंदा एससीबी (बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का 99 प्रतिशत हिस्सा 60 बैंकों से संबंधित है) में किए गए थे, ताकि विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के संबंध में उनकी अतिसंवेदनशीलता और लचीलेपन का मूल्यांकन किया जा सके¹⁹।

टॉप-डाउन दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

2.24 बैंकों के लिए विभिन्न स्थिर ऋण आघातों के प्रभाव से पता चलता है कि प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर (परिकल्पित दबावग्रस्त परिदृश्य के तहत) अपेक्षित 9 प्रतिशत से अधिक बना रहेगा। उदाहरण के लिए, 3 मानक विचलन (एसडी)²⁰ [अर्थात् यदि जीएनपीए अनुपात 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत होता हो] के बड़े आघात के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर घटकर 9.9 प्रतिशत होगा और प्रणाली स्तर पर टियर 1 सीआरएआर घटकर 7.3 प्रतिशत रह जाएगा। प्रणाली स्तर पर पूंजीगत हानियां लगभग 23.4 प्रतिशत रह सकती हैं। लाभ पर इन आघातों का प्रभाव एससीबी में बहुत अधिक पड़ेगा जिससे यदि 1.5 एसडी के साथ एनपीए बढ़कर 8.3 प्रतिशत होता है तो ये पूरा लाभ गंवा सकते हैं (सारणी 2.4)। सरकारी क्षेत्र के बैंक इन दबाव परीक्षणों, जहां उनका सीआरएआर उनके एनपीए में 3 एसडी बढ़ोतरी के आघात के तहत 9 प्रतिशत से नीचे आ गया, से बहुत प्रभावित हुए हैं। परिकल्पित आघात के अंतर्गत, तीन बैंकों के छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम हो जाएगा। वैयक्तिक बैंक स्तर पर दबाव परीक्षण परिणामों से पता चलता है कि एससीबी की कुल आस्तियों का 50.4 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाले 28 बैंक एनपीए

चार्ट 2.17: प्रत्याशित हानियां तथा अप्रत्याशित हानियां : बैंक-वार (सितंबर 2015)



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

¹⁷ संवेदनशीलता विश्लेषण ऋण जोखिम के लिए समष्टिगत दबाव परीक्षण के लिए अतिरिक्त रूप में किया गया। जहां पूर्व के आघात सीधे आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए) पर आरोपित किए गए थे, वहीं बाद वाले आघात प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक स्थितियों पर आरोपित गए। इसके साथ ही साथ, समष्टिगत दबाव परीक्षण प्रणाली, प्रमुख बैंक समूह और क्षेत्रगत स्तर पर किए गए जहां संवेदनशीलता का विश्लेषण प्रणालीगत और बैंक स्तर पर अलग-अलग किए गए। जहां, समष्टिगत दबाव परीक्षण का ध्यान ऋण जोखिम केंद्रित पर था, वहीं संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम को शामिल किया गया।

¹⁸ दबाव परीक्षण की विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

¹⁹ विभिन्न कल्पित परिदृश्यों के तहत निर्धारित किए गए आघात अत्यधिक हैं किंतु संभव हैं।

²⁰ जीएनपीए अनुपात के मानक विचलन (एसडी) का अनुमान 10 वर्षीय तिमाही आंकड़ों के आधार किया गया है। एक एसडी आघात एनपीए में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बराबर होता है।

सारणी 2.4: ऋण जोखिम - आघात और असर

(प्रतिशत)

	प्रणाली स्तर *					बैंक स्तर			
	सीआरएआर	टियर -1 सीआरएआर	जीएनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियां	वार्षिकीकृत लाभ के प्रतिशत के रूप में हानियां	प्रभावित बैंक (सीआरएआर < 9%)		प्रभावित बैंक (टियर-1 सीआरएआर < 6%)	
आधार रेखा (आघात से पहले)	12.6	10.0	5.2	-	-	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों के प्रतिशत में हिस्सा	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों के प्रतिशत में हिस्सा
आघात 1:	11.7	9.1	7.2	7.8	65.3	4	3.8	3	3.6
आघात 2:	10.8	8.2	9.2	15.6	130.6	19	31.6	17	29.4
आघात 3:	9.9	7.3	11.2	23.4	195.9	28	50.4	24	43.1
आघात 4:	12.3	9.7	6.9	3.1	25.7	2	2.5	0	0.0
आघात 5:	11.3	8.7	6.9	11.4	95.3	13	16.7	11	18.5

आघात 1: जीएनपीए पर 1 एसडी का आघात
 आघात 2: जीएनपीए पर 2 एसडी का आघात
 आघात 3: जीएनपीए पर 3 एसडी का आघात
 आघात 4: पुनर्रचित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत सकल अनर्जक आस्ति बन गए (अवमानक श्रेणी)
 आघात 5: पुनर्रचित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत को बट्टा खाता में डाला गया (हानि श्रेणी) - बट्टे खाते में डाला गया

* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

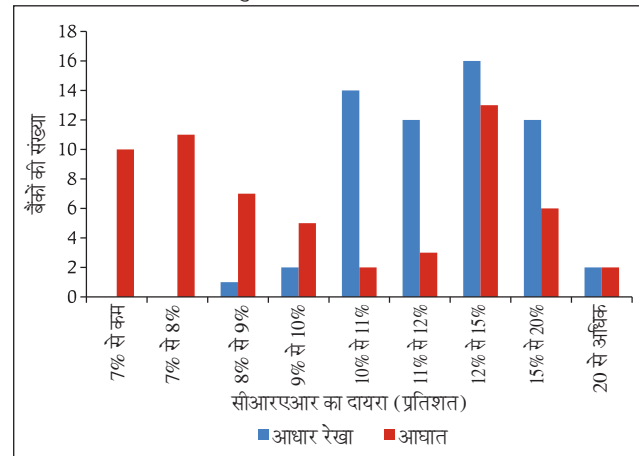
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

में 3 एसडी बड़ेतरी के आघात के तहत अपेक्षित सीआरएआर को बनाए रखने में असफल हो जाएंगे (चार्ट 2.18)।

ऋण संकेद्रण जोखिम

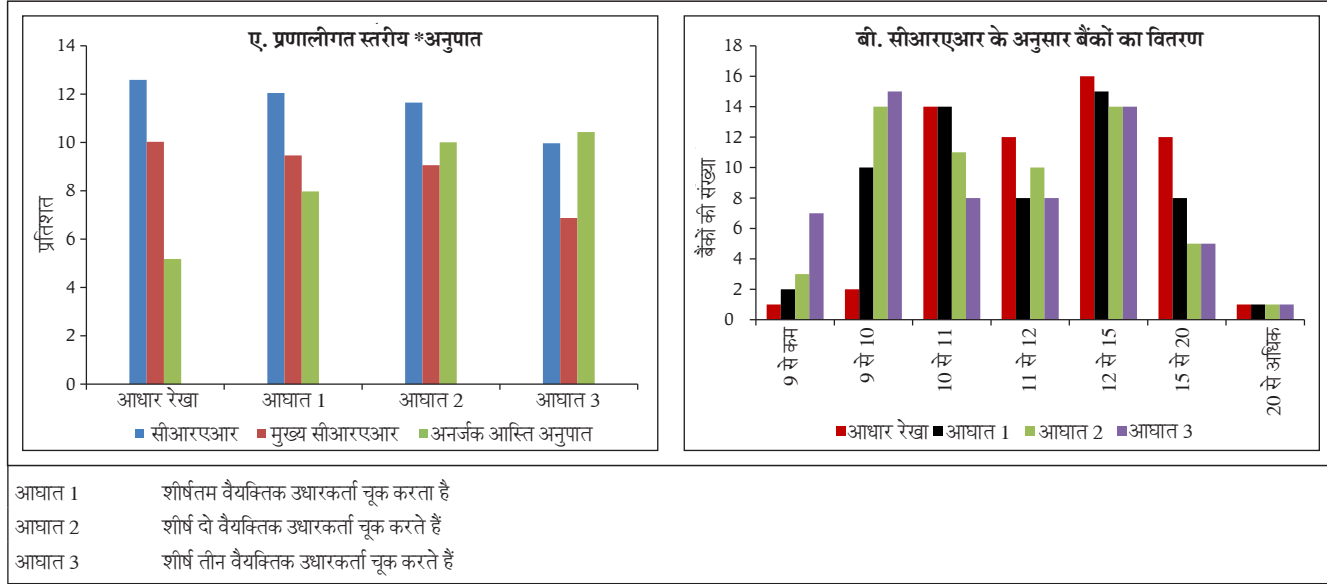
2.25 वैयक्तिक उधारकर्ता पर विचार करते हुए बैंकों के ऋण संकेद्रण जोखिम के दबाव परीक्षण से पता चलता है कि 7 बैंकों पर काफी प्रभाव (तीन भिन्न परिदृश्यों के तहत) था जिसमें आस्तियों का लगभग 6.1 प्रतिशत हिस्सा शामिल है जो कि कम से कम एक परिदृश्य के अंतर्गत 9 प्रतिशत के सीआरएआर को बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। शीर्षतम उधारकर्ता की चूक के परिकल्पित परिदृश्य के तहत पूंजीगत हानियां लगभग 5 प्रतिशत हो सकती हैं। शीर्ष दो उधारकर्ताओं की चूक से 9 प्रतिशत की पूंजीगत हानियां हो सकती हैं जबकि सबसे अधिक तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक के मामले में 13 प्रतिशत की हानियां हो सकती हैं। शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक के लिए लाभ पूर्व कर (पीबीटी) पर प्रभाव 112 प्रतिशत हो सकता है। शीर्षतम वैयक्तिक उधारकर्ता की चूक के परिदृश्य के तहत पीबीटी की 41 प्रतिशत की हानियां हो सकती है और शीर्ष दो वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक के मामले में 71 प्रतिशत की हानियां हो सकती हैं। शीर्ष एक, दो और तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक का परिकल्पित परिदृश्यों के तहत

चार्ट 2.18: सीआरएआर के अनुसार बैंकों का वितरण (जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी के आघात के अंतर्गत)



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 2.19: ऋण संकेद्रण जोखिम - वैयक्तिक उधारकर्ता



* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर पर 54, 94 और 262 आधार अंकों का प्रभाव होगा (चार्ट 2.19)।

2.26 बैंकों के ऋण संकेद्रण जोखिम से संबंधित समूह उधारकर्ताओं की जानकारी पर आधारित 10 भिन्न-भिन्न परिदृश्यों का प्रयोग करते हुए किए गए दबाव परीक्षण से पता चलता है कि यदि अधिक समूह उधारकर्ता चूक करते हैं तो पूंजी पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। हानियां शीर्ष एक समूह उधारकर्ता और शीर्ष दो समूह उधारकर्ताओं के

परिकल्पित परिदृश्यों के तहत प्रणाली स्तर पर लगभग 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की चूक हो सकती हैं। 5 समूह उधारकर्ताओं की चूक के मामले में हानियां 19 प्रतिशत हो सकती हैं और यदि अत्यधिक दबाव की स्थिति में 10 सामूहिक उधारकर्ता चूक करते हैं तो पूंजी के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से की हानि हो सकती है। इस प्रकार की अत्यधिक दबावपूर्ण विषम स्थिति में लगभग 27 बैंक अपने सीआरएआर को 9 प्रतिशत बनाए रखने में असमर्थ होंगे (सारणी 2.5)।

सारणी 2.5: ऋण संकेद्रण जोखिम: समूह उधारकर्ता

आघात	प्रणालीगत स्तर*				बैंक स्तर	
	सीआरएआर	मुख्य सीआरएआर	एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानियां	प्रभावित बैंक (सीआरएआर <9%)	
आधार रेखा (आघात पूर्व)	12.6	10.0	5.2	---	बैंकों की संख्या	बैंकिंग प्रणाली में कुल आस्तियों का हिस्सा (% में)
आधार 1	11.9	9.3	8.6	6	1	0.1
आधार 2	11.4	8.8	11.1	10	5	4.8
आधार 3	11.1	8.4	13.0	14	8	10.4
आधार 4	10.7	8.1	14.7	17	13	16.9
आधार 5	10.4	7.8	16.2	19	15	34.2
आधार 6	10.1	7.5	17.6	22	20	43.3
आधार 7	9.9	7.2	18.9	24	22	46.2
आधार 8	9.6	7.0	20.1	26	26	50.7
आधार 9	9.4	6.7	21.3	28	26	50.7
आधार 10	9.1	6.5	22.4	30	27	52.0

* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.27 कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योगों के लिए एक्जोजर से होने वाले ऋण जोखिम की जांच क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षणों²¹ के जरिए की गई। यह माना गया था कि मौजूदा पुनर्रचित मानक अग्रिमों का एक हिस्सा एनपीए में बदल जाएगा जिससे प्रत्येक क्षेत्र में अन्य मानक अग्रिमों पर एक आघात पड़ेगा। संवेदनशीलता के विश्लेषण के परिणामों से पता चला

कि आघातों से प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए में काफी बढ़ोतरी होगी, जिसमें से एकल क्षेत्र आघात का सबसे अधिक प्रभाव लोहा और इस्पात क्षेत्र पर पड़ेगा (सारणी 2.6)। इसे देखते हुए कि ऋण संविभाग का सिर्फ एक हिस्सा ही आघात के अंतर्गत था, पूंजी अनुपातों पर आघात का प्रभाव सीमित रहा। तथापि, बैंकों की लाभप्रदता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है (कर पूर्व लाभ)।

सारणी 2.6 : क्षेत्रगत ऋण जोखिम : उद्योग - आघात एवं असर

(प्रतिशत)

क्षेत्र		उद्योग	(ए) जिसमें से : एमएसएमई			(बी 1) जिसमें से : टेक्सटाइल			(बी 2) जिसमें से : लोहा एवं इस्पात									
क्षेत्र का प्रोफाइल																		
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		40.78	7.91			3.18			4.67									
पुनर्रचित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		82.42	4.74			6.18			14.01									
कुल एनपीए - समग्र स्तर में क्षेत्र का हिस्सा		54.05	9.32			7.05			6.88									
क्षेत्रगत पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात		13.20	3.92			12.67			19.58									
प्रणाली का पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात		6.53	6.53			6.53			6.53									
आघात	पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर आघात	अन्य मानक अग्रिमों पर आघात	उद्योग			(ए) जिसमें से : एमएसएमई			(बी 1) जिसमें से : टेक्सटाइल			(बी 2) जिसमें से : लोहा एवं इस्पात						
			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *						
				प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि				
आघात पूर्व की स्थिति			6.68	5.04	-	-	5.94	5.04	-	-	11.16	5.04	-	-	7.42	5.04	-	-
आघात-1		-	8.66	5.85	1.56	12.32	6.52	5.09	0.09	0.71	13.06	5.10	0.12	0.92	10.36	5.18	0.26	2.10
आघात-2	15	5	8.99	5.98	2.12	16.83	6.82	5.11	0.19	1.50	13.62	5.12	0.19	1.50	10.73	5.19	0.33	2.65
आघात-3		10	9.33	6.12	2.69	21.33	7.12	5.13	0.29	2.30	14.18	5.14	0.26	2.09	11.10	5.21	0.40	3.20
आघात-4		-	10.64	6.65	3.11	24.65	7.11	5.13	0.18	1.42	14.96	5.16	0.23	1.85	13.30	5.31	0.53	4.19
आघात-5	30	5	10.97	6.79	3.68	29.15	7.41	5.16	0.28	2.21	15.52	5.18	0.31	2.43	13.67	5.33	0.60	4.74
आघात-6		10	11.31	6.93	4.25	33.65	7.70	5.18	0.38	3.01	16.08	5.20	0.38	3.01	14.04	5.35	0.67	5.29
आघात-7		-	8.66	5.85	5.78	45.75	6.52	5.09	0.33	2.63	13.06	5.10	0.43	3.43	10.36	5.18	0.98	7.78
आघात-8	15	5	8.99	5.98	6.35	50.26	6.82	5.11	0.43	3.43	13.62	5.12	0.51	4.01	10.73	5.19	1.05	8.33
आघात-9		10	9.33	6.12	6.91	54.76	7.12	5.13	0.53	4.22	14.18	5.14	0.58	4.59	11.10	5.21	1.12	8.88
आघात-10		-	10.64	6.65	11.55	91.51	7.11	5.13	0.67	5.27	14.96	5.16	0.87	6.86	13.30	5.31	1.96	15.56
आघात-11	30	5	10.97	6.79	12.12	96.01	7.41	5.16	0.77	6.06	15.52	5.18	0.94	7.44	13.67	5.33	2.03	16.11
आघात-12		10	11.31	6.93	12.69	100.51	7.70	5.18	0.87	6.86	16.08	5.20	1.01	8.02	14.04	5.35	2.10	16.66

टिप्पणी: * चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

& नए एनपीए की आस्ति श्रेणी के संबंध में मान्यताएं :

आघात 1-6 : अवमानक श्रेणी की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम

आघात 7-12 : हानि श्रेणी की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम

आघात के अंतर्गत क्षेत्रगत एनपीए में नियत प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मानक अग्रिमों (पुनर्रचित मानक अग्रिमों के अलावा) में से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए के आघात पड़ने की स्थिति में अवमानक हो जाने की परिकल्पना की गई है।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

²¹ आंकड़े जून 2015 की स्थिति के अनुसार हैं।

2.28 क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षण ऊर्जा, यातायात और दूरसंचार के कुछ महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों सहित आधारभूत संरचना खंडों के लिए भी किए गए। परीक्षणों से पता चला कि आधारभूत संरचना खंड पर

पड़ने वाले आघातों से प्रणाली पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। किसी एक क्षेत्र पर पड़ने वाले आघात का सबसे महत्वपूर्ण असर ऊर्जा एवं यातायात क्षेत्रों पर होगा (सारणी 2.7)।

सारणी 2.7: क्षेत्रगत ऋण जोखिम : आधारभूत संरचना - आघात एवं असर

(प्रतिशत)

क्षेत्र		आधारभूत संरचना	(ए 1) जिसमें से : ऊर्जा			(बी 1) जिसमें से : यातायात			(ए 3) जिसमें से : दूरसंचार									
क्षेत्र का प्रोफाइल																		
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		15.49	9.24			3.24			1.54									
पुनर्रचित मानक अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		45.66	29.31			14.64			1.71									
कुल एनपीए - समग्र स्तर में क्षेत्र का हिस्सा		12.69	4.99			3.78			1.76									
क्षेत्रगत पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात		19.25	20.71			29.50			7.24									
प्रणाली का पुनर्रचित मानक अग्रिम अनुपात		6.53	6.53			6.53			6.53									
आघात	पुनर्रचित मानक अग्रिमों* पर आघात	अन्य मानक अग्रिमों* पर आघात	आधारभूत संरचना				(ए 1) जिसमें से : ऊर्जा			(बी 1) जिसमें से : यातायात			(ए 3) जिसमें से : दूरसंचार					
			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि	क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि
आघात पूर्व की स्थिति			4.13	5.04	-	-	2.72	5.04	-	-	5.88	5.04	-	-	5.74	5.04	-	-
आघात-1	15	-	7.02	5.49	0.86	6.83	5.83	5.33	0.55	4.38	10.30	5.18	0.28	2.19	6.83	5.06	0.03	0.26
आघात-2		5	7.22	5.52	0.99	7.84	5.97	5.34	0.60	4.74	10.59	5.19	0.32	2.50	7.11	5.06	0.05	0.43
आघात-3		10	7.43	5.55	1.12	8.85	6.10	5.35	0.64	5.11	10.89	5.20	0.36	2.82	7.40	5.06	0.08	0.60
आघात-4	30	-	9.91	5.93	1.72	13.66	8.94	5.61	1.11	8.77	14.73	5.33	0.55	4.38	7.91	5.07	0.06	0.51
आघात-5		5	10.11	5.97	1.85	14.67	9.07	5.63	1.15	9.13	15.02	5.34	0.59	4.69	8.20	5.08	0.09	0.68
आघात-6		10	10.32	6.00	1.98	15.68	9.21	5.64	1.20	9.49	15.31	5.35	0.63	5.01	8.49	5.08	0.11	0.86
आघात-7	15	-	7.02	5.49	3.20	25.35	5.83	5.33	2.05	16.27	10.30	5.18	1.03	8.13	6.83	5.06	0.12	0.95
आघात-8		5	7.22	5.52	3.33	26.36	5.97	5.34	2.10	16.63	10.59	5.19	1.07	8.44	7.11	5.06	0.14	1.12
आघात-9		10	7.43	5.55	3.46	27.37	6.10	5.35	2.15	16.99	10.89	5.20	1.11	8.76	7.40	5.06	0.16	1.29
आघात-10	30	-	9.91	5.93	6.40	50.70	8.94	5.61	4.11	32.54	14.73	5.33	2.05	16.26	7.91	5.07	0.24	1.90
आघात-11		5	10.11	5.97	6.53	51.71	9.07	5.63	4.15	32.90	15.02	5.34	2.09	16.57	8.20	5.08	0.26	2.07
आघात-12		10	10.32	6.00	6.66	52.72	9.21	5.64	4.20	33.26	15.31	5.35	2.13	16.88	8.49	5.08	0.28	2.24

टिप्पणी - * नए एनपीए की आस्ति श्रेणी के संबंध में मान्यताएं :

आघात 1-6 : अवमानक श्रेणी की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम

आघात 7-12 : हानि श्रेणी की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम

आघात के अंतर्गत क्षेत्रगत एनपीए में नियत प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। मानक अग्रिमों (पुनर्रचित मानक अग्रिमों के अलावा) में से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए के आघात पड़ने की स्थिति में अवमानक हो जाने की परिकल्पना की गई है।

* चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

2.29 क्षेत्रगत ऋण आघातों की तुलना में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के विश्लेषण भी किए गए²²। विश्लेषण में अभियांत्रिकी, आटोमोबाइल्स, भवन निर्माण एवं सीमेंट उद्योगों पर गौर किया गया। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि पड़ने वाले आघात से प्रणालीगत स्तरीय सकल अनर्जक अग्रिमों (जीएनपीए) में काफी वृद्धि होगी। किसी एक उद्योग पर पड़ने वाला इसका सबसे महत्वपूर्ण असर अभियांत्रिकी पर पड़ा (सारणी -2.8)।

ब्याज दर जोखिम

2.30 बैंकों के एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) एवं एचएफटी (व्यापार के लिए धारित) पोर्टफोलियों (प्रत्यक्ष असर) में 2.5 प्रतिशत अंकों की समानांतर वृद्धि (ऊपर की ओर परिवर्तन) से उत्पन्न होने वाला ब्याज दर जोखिम काबू करने योग्य प्रतीत होता है क्योंकि प्रणालीगत स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) लगभग 94 आधारभूत अंक रहेगा। इस आघात के संबंध में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2015²³ में रिपोर्ट किए अनुसार सीआरएआर में 92 आधारभूत अंकों की कमी आई थी। भिन्न-भिन्न स्तरों पर, कुल आस्तियों का 9.2 प्रतिशत धारित

करने वाले आठ बैंकों पर विपरीत असर पड़ा और उनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम हो गया। प्रणालीगत स्तर पर कुल पूंजीगत हानि के लगभग 8.4 प्रतिशत रहने का अनुमान था। बैंकों के एचटीएम पोर्टफोलियों से संबंधित प्राप्त वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों के समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तित होने के परिकल्पित आघात, यदि यह बाजार दरों पर आधारित हो, से सीआरएआर में 233 आधारभूत अंकों की उल्लेखनीय कमी आएगी जिसका विपरीत असर उन 22 बैंकों पर पड़ेगा जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम स्तर पर चला जाएगा (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2015 में किए गए आकलन के अनुसार यह असर 276 आधारभूत अंक रहा)। प्राप्त वक्र में समानांतर नीचे की ओर परिवर्तित होने (2.5 आधारभूत अंक) के परिकल्पित आघात के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंकिंग बहियों²⁴ पर आय का असर उनके लाभ (कर पूर्व) के लगभग 53.7 प्रतिशत हो सकता है।

2.31 कारोबारी बहियों के प्राप्त वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों के समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तित होने के आघात के असर के बैंक समूह स्तरीय विश्लेषण (दबाव परीक्षण करने के लिए सिर्फ चुनिंदा बैंकों का प्रयोग करते हुए) से पता चलता है कि निजी बैंकों (पीवीबी) (55

सारणी 2.8: क्षेत्रगत ऋण जोखिम : चुनिंदा उद्योग
(एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात : एनपीए अनुपात में नियत प्रतिशत अंकों की वृद्धि)

क्षेत्र		अभियांत्रिकी				आटोमोबाइल्स				निर्माण				सीमेंट			
क्षेत्र का प्रोफाइल																	
कुल अग्रिमों में क्षेत्र का हिस्सा		2.59				1.19				1.53				0.85			
कुल एनपीए में क्षेत्र का हिस्सा		4.29				1.19				1.91				1.04			
आघात	वर्तमान क्षेत्रगत जीएनपीए अनुपात पर क्रमागत आघात	अभियांत्रिकी				आटोमोबाइल्स				निर्माण				सीमेंट			
		क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *			क्षेत्र का एनपीए अनुपात	प्रणालीगत स्तर पर असर *		
			प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि		प्रणालीगत स्तर पर एनपीए अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में हानि	लाभ के प्रतिशत के रूप में हानि
आघात पूर्व की स्थिति		8.57	5.18	-	-	5.16	5.18	-	-	6.47	5.18	-	-	6.37	5.18	-	-
आघात-1	2	10.57	5.23	0.22	1.86	7.16	5.20	0.09	0.76	8.47	5.21	0.12	0.98	8.37	5.19	0.07	0.57
आघात-2	5	13.57	5.31	0.55	4.64	10.16	5.24	0.23	1.89	11.47	5.25	0.29	2.44	11.37	5.22	0.17	1.41
आघात-3	10	18.57	5.44	1.11	9.29	15.16	5.30	0.45	3.78	16.47	5.33	0.58	4.88	16.37	5.26	0.34	2.83

टिप्पणी: * चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।

आघात में क्षेत्रगत एनपीए अनुपात (एनपीए अनुपात पर उत्तरोत्तर आघात - वर्तमान एनपीए अनुपात पर अतिरिक्त) में नियत प्रतिशत की वृद्धि मानी गई है। मानक अग्रिमों में से उत्पन्न होने वाले नए एनपीए को आघात पड़ने पर विभिन्न आस्त श्रेणियों (वर्तमान पैटर्न के अनुसार) में वितरित किया गया माना गया है।

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

²² आंकड़े सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार हैं।

²³ आंकड़े मार्च 2015 तिमाही के हैं।

²⁴ बैंकिंग बहियों में आय के प्रभाव की गणना सिर्फ एक वर्ष के लिए की गई है जिसमें दर के प्रति संवेदनशील आस्तियों एवं देयताओं के एक्सपोजर अंतराल पर विचार किया गया है और एएफएस एवं एचएफटी पोर्टफोलियों पर विचार नहीं किया गया है।

आधारभूत अंक) तथा विदेशी बैंकों (एफबी) (144 आधारभूत अंक) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीआरएआर में 106 आधारभूत अंकों (बीपीएस) की गिरावट हो सकती है जिसका मुख्य कारण इन बैंकों की कारोबारी बहियों (मोडिफाइड ड्यूरेशन द्वारा सूचित) में निवेश की संवेदनशीलता की उच्चतर दर होना है (सारणी 2.9)।

चलनिधि जोखिम

2.32 चलनिधि जोखिम विश्लेषण में बैंकों पर परिकल्पित परिदृश्यों के प्रभावों को शामिल किया जाता है जिनमें जमा राशि की निकासी के साथ ही साथ स्वीकृत की गई/जिसके लिए वचनबद्ध हों (अनाहरित कार्यशील पूंजी सीमा एवं ऐसी अनाहरित ऋण श्रृंखला जिसके लिए वचनबद्ध हों, को हिसाब में लिया गया), ऋण श्रृंखलाओं के अप्रयुक्त हिस्से की बढ़ी हुई मांग पर विचार किया गया। परिकल्पित परिदृश्यों के अंतर्गत, गैर-बीमाकृत जमाराशियों के आहरण में वृद्धि होगी और उसी समय स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से आहरण और साथ ही साथ अपने ग्राहकों के प्रति बैंकों की ऋण प्रतिबद्धता के कारण ऋण की मांग बढ़ जाएगी। यह माना गया है कि बैंकों से यह अपेक्षा होगी कि वे अपनी चलनिधियुक्त आस्तियों {सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का पूर्ण या उसके एक हिस्से} का ही प्रयोग करते हुए इनको (मांगों को) पूरा करेंगे और निधीयन का कोई बाहरी कारक इसमें शामिल नहीं होगा। निवेशों में 10 प्रतिशत का हेयरकट/मार्जिन माना गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में परीक्षण सितंबर 2015 के आंकड़ों के आधार पर किए गए।

2.33 पहले मामले में, यह माना गया है कि दबावपूर्ण परिदृश्य में बैंकों को अपनी चलनिधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण एसएलआर निवेश तथा नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) की अतिरिक्त राशि उपलब्ध रहेगी। संकट काल में विशिष्ट नीतिगत उपायों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके पड़ने वाले असर को सारणी 2.10 में दर्शाया गया है।

2.34 विश्लेषण से पता चलता है कि दबावपूर्ण परिदृश्य में चलनिधि पर दबाव होने के बावजूद अधिकांश बैंक, अचानक और अप्रत्याशितरूप से लगभग 25 प्रतिशत जमाराशि के आहरण होने के साथ ही वचनबद्ध ऋण श्रृंखलाओं के 75 प्रतिशत का प्रयोग हो

सारणी 2.9: ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात एवं असर
(250 आधारभूत अंकों के आघात के तहत आईएनआर प्राप्ति वक्र में समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तन)

(प्रतिशत)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी	
	एफएस	एचएफटी	एफएस	एचएफटी	एफएस	एचएफटी
मोडिफाइड ड्यूरेशन	3.7	5.3	2.3	4.6	1.3	3.0
कुल निवेश में हिस्सा	34.1	0.4	29.4	3.9	75.8	23.2
सीआरएआर में कमी (बीपीएस)	106		55		144	

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.10: चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर
(चलनिधि सहयोग के लिए अतिरिक्त सीआरआर के साथ में संपूर्ण एसएलआर का प्रयोग करते हुए)

आघात ²⁵	संचयी (गैर-बीमाकृत ²⁶) जमाराशियों का आहरण (प्रतिशत)	प्रणाली के लिए उपलब्ध चलनिधि-युक्त आस्तियां (कुल आस्तियों का प्रतिशत)	परीक्षण में असफल ²⁷ होने वाले बैंकों की संख्या (चुनिंदा 60 में से)	एससीबी की कुल आस्तियों की तुलना में दबावपूर्ण परिदृश्य में असफल होने वाले बैंकों की आस्तियों का हिस्सा (प्रतिशत)
आधार रेखा	-	22.9	-	-
आघात 1	10	14.1	2	1.8
आघात 2	20	8.5	2	1.8
आघात 3	25	5.6	8	6.4
आघात 4	30	2.8	22	29.8

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

²⁵ चलनिधि आघातों में गैर-बीमाकृत जमाराशियों के एक हिस्से का आहरण तथा वचनबद्ध ऋण श्रृंखलाओं (स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के साथ ही साथ उनके ग्राहकों के प्रति ऋण प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया गया है) की 75 प्रतिशत मांग भी शामिल है।

²⁶ वर्तमान में, कुल जमाराशि में गैर-बीमाकृत जमाराशि का हिस्सा लगभग 69 प्रतिशत है (स्रोत : डीआईसीजीसी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सांख्यिकी की हैडबुक)।

²⁷ दबावपूर्ण परिदृश्यों (आघात पड़ने पर) के अंतर्गत अपनी चलनिधि युक्त आस्तियों (दबावपूर्ण परिस्थितियों में चलनिधि युक्त आस्तियों का भंडार ऋणात्मक हो गया) की मदद से अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने पर बैंक परीक्षण में असफल हुआ।

जाने की स्थिति को भी अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की मदद से झेल सकते हैं।

2.35 भारत में 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होने वाले चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)²⁸ को लागू किए जाने को ध्यान में रखते हुए दबाव परीक्षण के लिए चलनिधि युक्त आस्तियों की परिभाषा को संशोधित किया गया। यह माना गया कि बैंक अपनी दैनंदिन चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि-युक्त आस्तियों (एचक्यूएलए)²⁹ का प्रयोग करेंगे।

2.36 दूसरे मामले में, इस बात पर विचार किया गया कि बैंकों को प्रारंभिक आघातों को झेलने में तत्काल उपलब्ध एलसीआर निधियां मदद करेंगी। प्रभावों को सारणी 2.11 में दर्शाया गया है।

2.37 इस विश्लेषण से पता चलता है कि एलसीआर के लागू हो जाने पर, परिकल्पित अचानक और अप्रत्याशित रूप से होने वाले लगभग 5 से 7 प्रतिशत के आघातों के साथ ही उनकी वचनबद्ध ऋण श्रृंखलाओं के 75 प्रतिशत का प्रयोग कर लिए जाने के परिदृश्य में अधिकांश बैंक अपनी उपलब्ध एचक्यूएलए की मदद से लोचदार बने रहेंगे। बैंक, अत्यधिक गंभीर संकट होने पर वृद्धिशील आघातों की स्थिति में, आवश्यकताओं के अनुसार उठाए गए विशिष्ट नीतिगत उपायों के माध्यम से उनके शेष एसएलआर निवेशों का प्रयोग करते हुए, जमाराशियों के और अधिक आघातों को भी झेलने में समर्थ होंगे।

बैंकों के व्युत्पन्नियों के संविभाग (डेरिवेटिव्स पोर्टफोलिया)

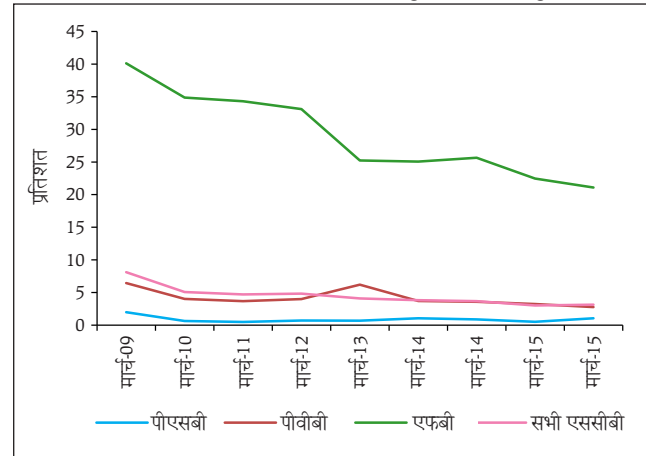
2.38 एससीबी के कुल आस्तियों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों के हिस्से में, हाल के अतीत में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। अन्य बैंक समूहों की तुलना में, विदेशी बैंकों (एफबी) की कुल आस्तियों में तुलन-पत्र से इतर आस्तियों का बहुत अधिक हिस्सा होना जारी रहा (चार्ट 2.20)।

सारणी 2.11: चलनिधि जोखिम - आघात एवं असर
(चलनिधि सहयोग के लिए एसएलआर निधियों का प्रयोग करते हुए)

आघात	संचयी (गैर-बीमाकृत ³⁰) जमाराशियों का आहरण	प्रणाली के लिए उपलब्ध चलनिधि-युक्त आस्तियां (कुल आस्तियों का प्रतिशत)	परीक्षण में असफल ³¹ होने वाले बैंकों की संख्या (चुनिंदा 60 में से)	एससीबी की कुल आस्तियों का तुलना में दबावपूर्ण परिदृश्य में असफल होने वाले बैंकों की आस्तियों का हिस्सा (प्रतिशत)
आधार रेखा	-	10.7	-	-
आघात 1	3	5.3	4	3.9
आघात 2	5	4.2	7	6.9
आघात 3	7	3.2	14	19.4
आघात 4	10	1.9	26	42.0

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 2.20: एससीबी की तुलन-पत्र से इतर आस्तियों का हिस्सा (ऋण समतुल्य)
कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

²⁸ चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानकों के संबंध में बासेल III ढांचे के संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी 120/21.04.098/2013-14 के माध्यम से जारी किए गए। एलसीआर की शुरुआत चरणबद्ध ढंग से की जा रही है, जिसके तहत 1 जनवरी 2015 से न्यूनतम अपेक्षा 60 प्रतिशत है तथा 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 100 प्रतिशत तक पहुंचना आवश्यक है।

²⁹ दबाव परीक्षण करने के लिए, एचक्यूएलए की गणना में अपेक्षित सीआरआर के अतिरेक, एसएलआर निवेश के अतिरेक, एनडीटीएल के 2 प्रतिशत एसएलआर निवेशों (एमएसएफ के अधीन) तथा एनडीटीएल के 5 प्रतिशत अतिरिक्त एसएलआर निवेशों (दिनांक 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी 52/21.04.098/2014-15 के अनुसार) को शामिल किया गया।

³⁰ वर्तमान में, कुल जमाराशि में गैर-बीमाकृत जमाराशि का हिस्सा लगभग 69 प्रतिशत है (स्रोत : डीआईसीजीसी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सांख्यिकी की हैडबुक)।

³¹ दबावपूर्ण परिदृश्यों (आघात पड़ने पर) के अंतर्गत अपनी चलनिधि युक्त आस्तियों (दबावपूर्ण परिस्थितियों में चलनिधि युक्त आस्तियों का भंडार ऋणात्मक हो गया) की मदद से अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने पर बैंक परीक्षण में असफल हुआ।

2.39 संदर्भ तिथि, 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार चुनिंदा प्रतिदर्श बैंकों³² के लिए व्युत्पन्नी संविभागों के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षणों की एक श्रृंखला चलाई गई। प्रतिदर्श में शामिल बैंकों ने ब्याज तथा विदेशी मुद्रा दरों के संबंध में चार अलग-अलग आघातों के परिणामों की रिपोर्ट किया। ब्याज दरों से संबंधित आघात 100 से 250 मूलभूत अंकों तक दायराबद्ध रहा जबकि विदेशी मुद्रा दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि/कमी के आघात पड़ने की बात मानी गई। व्यक्तिशः आघातों के संबंध में दबाव परीक्षण एकल आधार पर किए गए।

2.40 प्रतिदर्श में, बैंकों से संबंधित व्युत्पन्नी संविभाग के बाजार दर आधारित (एमटीएम) मूल्य में, 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, पीएसबी और पीवीबी में अंतर पाया गया जबकि विदेशी बैंकों का अपेक्षाकृत बड़ा धनात्मक और ऋणात्मक एमटीएम रहा। अधिकांश बैंकों का निवल एमटीएम धनात्मक रहा (चार्ट 2.21)।

2.41 दबाव परीक्षण के परिणामों से पता चला कि प्रतिदर्श बैंकों पर ब्याज दर आघातों का निवल असर बहुत अधिक नहीं पड़ा। विदेशी मुद्रा विनिमय आघात परिदृश्यों पर भी सितंबर 2015 में अपेक्षाकृत कम असर दिखाई दिया (चार्ट 2.22)।

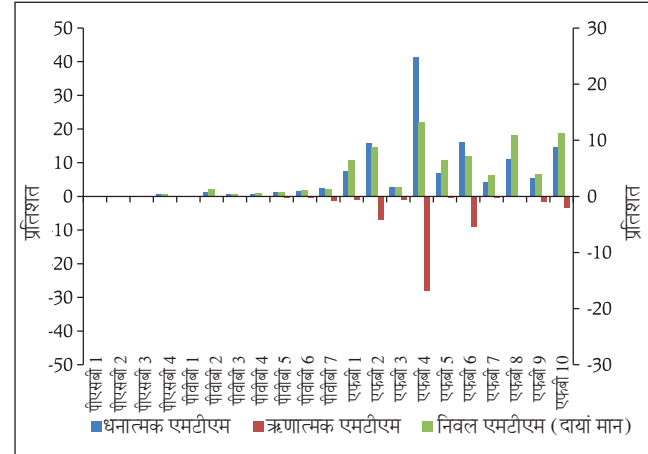
जोखिम

बैंकिंग स्थिरता सूचक

2.42 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)³³ दर्शाता है कि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट³⁴ के प्रकाशन होने के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ गया है। बीएसआई के विश्लेषण की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की परिस्थितियां 2010 के मध्य से बिगड़नी प्रारंभ हुईं। वर्तमान छायाही के दौरान जोखिमों के बढ़ने में मदद करने वाले कारक आस्ति गुणवत्ता में खराबी आ

चार्ट 2.21: कुल व्युत्पन्नियों के एमटीएम (सितंबर 2015)

तुलन-पत्र की आस्तियों की तुलना में प्रतिशत

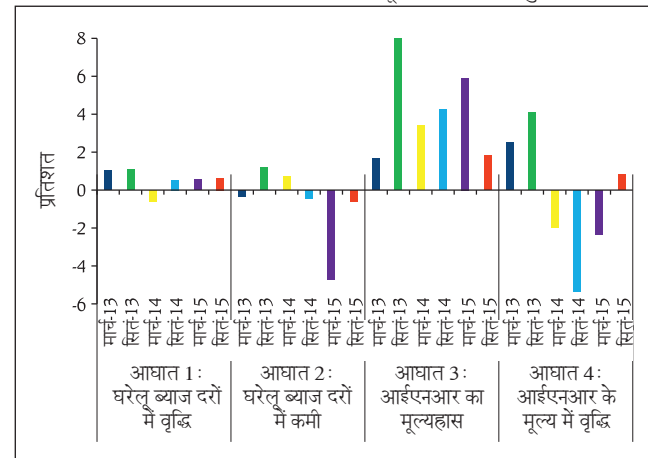


टिप्पणी: पीएसबी - सरकारी बैंक, पीवीबी - निजी बैंक, एफबी - विदेशी बैंक
स्रोत: प्रतिदर्श बैंक (व्युत्पन्नी संविभाग पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)।

चार्ट 2.22: दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी संविभागों पर आघातों का असर

(आघात पड़ने पर निवल एमटीएम में परिवर्तन)

(पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत)



टिप्पणी: आधार रेखा के संदर्भ में पड़ने वाले आघात के कारण निवल एमटीएम में परिवर्तन।
स्रोत: प्रतिदर्श बैंक (व्युत्पन्नी संविभाग पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)।

³² 21 बैंकों के प्रतिदर्श के लिए व्युत्पन्नियों के संविभागों पर दबाव परीक्षण किए गए। विवरण अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

³³ विस्तृत कार्यप्रणाली तथा बीएसआई के विभिन्न आयामों के तहत प्रयुक्त मूलभूत सूचकों के विवरण अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

³⁴ एफएसआर, जून 2015 (मार्च 2015 के अंत में आंकड़ों के संदर्भ में)।

रही है, मजबूती में कमी आ रही है और लाभप्रदता भी घट रही है (चार्ट 2.23 एवं 2.24)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी)

निष्पादन

2.43 प्रणालीगत स्तर पर³⁵, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर मार्च एवं सितंबर 2015 के बीच 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, भिन्न-भिन्न देखा जाए तो पांच बैंक सीआरएआर के न्यूनतम अपेक्षित 9 प्रतिशत के स्तर को बनाए रखने में असफल रहे। एसएयूसीबी के जीएनपीए में काफी वृद्धि हुई और ये 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान उनका प्रावधान कवरेज अनुपात 55.7 प्रतिशत से घटकर 51.2 प्रतिशत रह गया। आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में 0.7 से 0.8 की मामूली वृद्धि हुई किंतु समान अवधि के दौरान चलनिधि अनुपात³⁶ में 35.3 प्रतिशत से 35.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

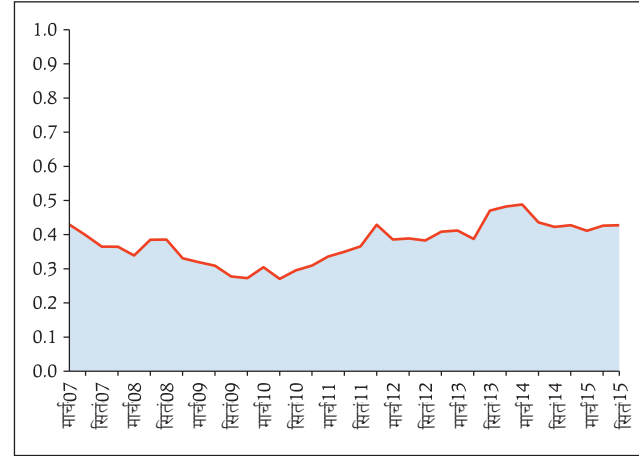
ऋण जोखिम

2.44 एसयूसीबी के संबंध में ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों का प्रयोग करते हुए दबाव परीक्षण किया गया। एसयूसीबी के सीआरएआर के संबंध में ऋण जोखिम आघातों का प्रभाव चार अलग-अलग परिदृश्यों³⁷ के अंतर्गत प्रेक्षित किया गया। परिणामों से प्रदर्शित हुआ कि सबसे खराब परिदृश्य (जीएनपीए में एक एसडी/मानक विचलन की वृद्धि, जिसे हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) को छोड़कर एसयूसीबी का प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर विनियामकीय अपेक्षा के अनुसार न्यूनतम स्तर के ऊपर बना रहा। हालांकि, व्यक्तिशः देखा जाए तो सबसे खराब परिदृश्य के अंतर्गत काफी अधिक संख्या (50 में से 30) सीआरएआर के अपेक्षित स्तरों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

चलनिधि जोखिम

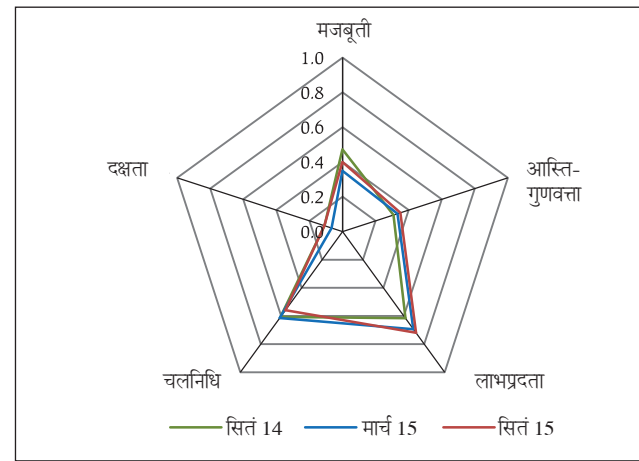
2.45 चलनिधि जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण दो अलग-अलग परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए - 1 से 28 दिवसीय समयावधि (टाइम बकेट) से नकदी बहिर्वाह में i) 50 प्रतिशत;

चार्ट 2.23: बैंकिंग स्थिरता सूचक



टिप्पणी: सूचक के मान में वृद्धि कम स्थिरता को दर्शाता है।
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 2.24: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र



टिप्पणी: केंद्र से दूरी जोखिम वृद्धि को दर्शाती है।
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

³⁵ 50 एसयूसीबी की प्रणाली।

³⁶ चलनिधि अनुपात=(नकद+बैंकों से बकाया +एसएलआर निवेश)*100/कुल आस्तियां।

³⁷ चार परिदृश्य इस प्रकार हैं : (i) जीएनपीए (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 0.5 एसडी का आघात, (ii) जीएनपीए (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 1एसडी का आघात, (iii) जीएनपीए (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण) में 0.5 एसडी का आघात, तथा (iv) जीएनपीए (हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) में 1 एसडी का आघात। एसडी के आकलन में 10 वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया।

एवं ii) 100 की वृद्धि। इसके आगे, यह भी माना गया कि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दबाव परीक्षण के परिणामों से संकेत मिलता है कि दबाव के परिदृश्य (50 बैंकों में से 27 बैंक परिदृश्य I के अंतर्गत तथा 38 बैंक परिदृश्य II के अंतर्गत) में एसयूसीबी पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा और उनको चलनिधि दबाव का सामना करना होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2.46 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, रिजर्व बैंक में 11,781 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 212 जमा स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) तथा 11,569 जमा स्वीकार नहीं करने वाली (एनबीएफसीडी-एनडी) थीं। 210 जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)³⁸ थीं। सभी एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई, रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के साथ ही पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं तथा प्रावधानीकरण मानदंडों जैसे विवेकसम्मत विनियमों के अधीन हैं।

कार्यनिष्पादन

2.47 एनबीएफसी सेक्टर³⁹ के समग्र तुलन-पत्र का वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सितंबर 2015 में 14.2 प्रतिशत का विस्तार हुआ जबकि मार्च में यह विस्तार 16.8 प्रतिशत था। ऋणों तथा अग्रिमों में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई किंतु उधार राशि में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.12)।

2.48 एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में मार्च 2015 की तुलना में सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही में गिरावट आई। मार्च एवं सितंबर 2015 के बीच कुल आय की तुलना में निवल लाभ 18.8 प्रतिशत से घटकर 15.0 प्रतिशत रह गया। आस्तियों का प्रतिलाभ (आरओए) 2.2 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर 1.0 प्रतिशत रह गया (सारणी 2.13)।

आस्ति गुणवत्ता

2.49 कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में, एनबीएफसी क्षेत्र का जीएनपीए सितंबर 2015 में बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गया जो मार्च में 3.4 प्रतिशत था। समान अवधि के दौरान, कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में, एनएनपीए भी 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.25)।

सारणी 2.12: एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन-पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)

मद	मार्च-15	सितं-15
1. शेयर पूंजी	7.5	6.7
2. आरक्षित निधि एवं अतिरिक्त	15.1	12.8
3. कुल उधारियां	18.7	14.5
4. वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	6.8	19.7
कुल देयताएं/आस्तियां	16.8	14.2
1. ऋण एवं अग्रिम	16.3	14.2
2. अवक्रीय एवं उधारपट्टा आस्तियां	9.7	5.3
3. निवेश	23.5	18.0
4. अन्य आस्तियां	16.2	9.7
आय/व्यय		
1. कुल आय	15.7	12.7
2. कुल व्यय	14.9	19.7
3. निवल लाभ	19.0	-11.5

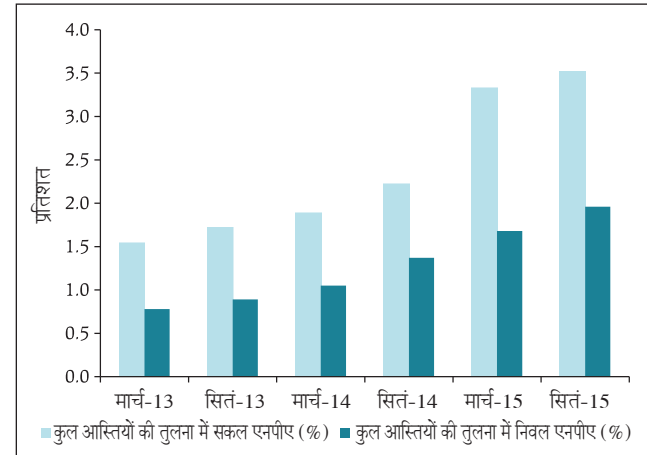
स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 2.13: एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन (प्रतिशत)

मद	मार्च-15	सितं-15
1. कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी बाजार में एक्सपोजर (सीएमई)	6.7	6.6
2. लीवरेज अनुपात	3.5	3.7
3. कुल आय की तुलना में निवल लाभ	18.8	15.0
4. आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) - (वार्षिकीकृत)	2.2	1.0

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.25: एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता (कुल आस्तियों का प्रतिशत)



स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

³⁸ एनबीएफसी-एनडी-एसआई वे एनबीएफसी-एनडी हैं जिनकी आस्तियां ₹5 बिलियन या उससे अधिक हैं।

³⁹ आंकड़े सभी एनबीएफसी-डी से संबंधित हैं तथा एनबीएफसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर गौर किया गया है।

पूँजी पर्याप्तता

2.50 मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी⁴⁰ से यह अपेक्षा होती है कि वे निर्धारित न्यूनतम पूँजी अपने पास रखें, जो टिअर-1⁴¹ तथा टिअर- II को समाहित करते हुए उनकी समग्र जोखिम-भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी का सीआरएआर सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार घटकर 23.8 प्रतिशत रह गया जो मार्च 2015 की स्थिति में 27.3 प्रतिशत था (चार्ट 2.26)। असमग्र स्तर पर, सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, आठ एनबीएफसी विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में असफल रहीं।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

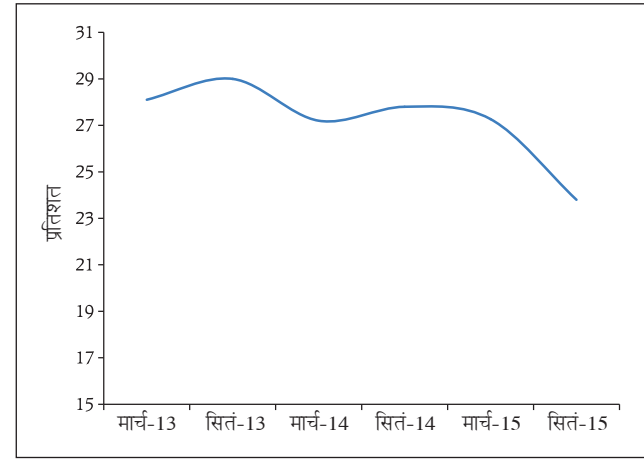
प्रणालीगत स्तर

2.51 सितंबर 2015 को समाप्त अवधि के लिए पूर्णरूपेण एनबीएफसी क्षेत्र के लिए ऋण जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण तीन परिदृश्यों के अंतर्गत किए गए : (i) जीएनपीए में 0.5 एसडी की वृद्धि हुई, (ii) जीएनपीए में 1 एसडी की वृद्धि हुई, तथा (iii) जीएनपीए में 3 एसडी की वृद्धि हुई। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि पहले और दूसरे परिदृश्यों में इस क्षेत्र का सीआरएआर थोड़ा प्रभावित हुआ किंतु तीसरे परिदृश्य में यह 23.8 प्रतिशत से घटकर 22.7 प्रतिशत रह गया। हालांकि, यह विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम 15 प्रतिशत के स्तर से काफी ऊपर था।

व्यक्तिशः एनबीएफसी

2.52 उन्हीं तीन परिदृश्यों के अंतर्गत समान अवधि के लिए व्यक्तिशः एनबीएफसी के लिए भी दबाव परीक्षण किए गए। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि परिदृश्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत क्रमशः लगभग 6 और 9 प्रतिशत कंपनियां विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम 15 प्रतिशत के स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी। जबकि, तीसरे परिदृश्य के अंतर्गत 12 प्रतिशत कंपनियां विनियामकीय अपेक्षा के निर्धारित न्यूनतम स्तर को नहीं बनाए रख पाएंगी।

चार्ट 2.26: एनबीएफसी क्षेत्र का सीआरएआर



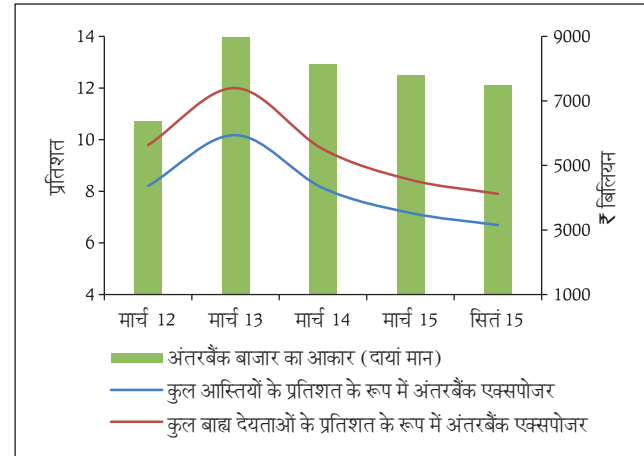
स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

परस्पर संबद्धता⁴²

अंतर-बैंक बाजार की प्रवृत्तियां

2.53 बैंकिंग संस्थानों के लिए अंतर-बैंक बाजार⁴³ निधीयन का प्रमुख स्रोत है। मार्च 2013 से इस बाजार के कारोबार की मात्रा (टर्नओवर) में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल कारोबार ₹7.5 ट्रिलियन का रहा, जिससे इसमें मार्च 2015 और जून 2015 की तुलना में क्रमशः 4.2 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत की गिरावट का पता चलता है (चार्ट 2.27)।

चार्ट 2.27: अंतरबैंक बाजार का आकार



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियां।

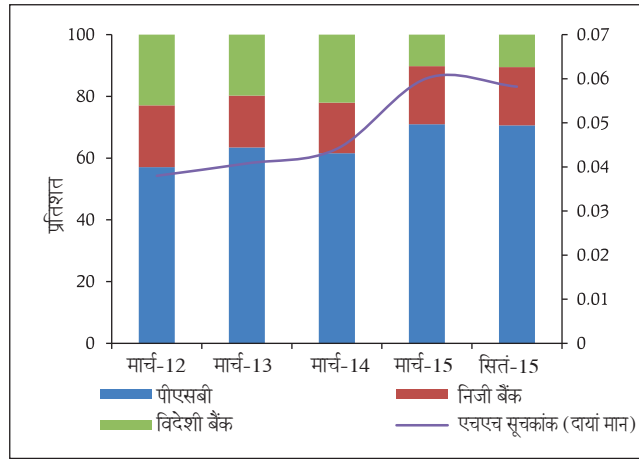
⁴⁰ ₹5 बिलियन या उससे अधिक के आस्त आकार वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी।

⁴¹ 10 नवंबर 2014 को जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई (₹5 बिलियन या उससे अधिक के आस्त आकार वाली) तथा जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए न्यूनतम टिअर-1 पूँजी को 10 प्रतिशत (पहले, टिअर-1 पूँजी 7.5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती थी) तक संशोधित कर दिया गया है और इन उपायों को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाना है (मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत तथा मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत)।

⁴² विश्लेषण में प्रयुक्त नेटवर्क मॉडल का विकास वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शेरी मार्कोसे (इस्सेक्स विश्वविद्यालय) तथा डॉ. साहमॉन गिआनसांटे (बेथ विश्वविद्यालय) ने किया।

⁴³ बैंक, आपस में काल, नोटिस तथा अन्य अल्पावधि बाजारों में लेनदेन करने के अलावा एक दूसरे के दीर्घावधि मीयादी लिखतों में भी निवेश करते हैं। वर्तमान विश्लेषण में जिस अंतरबैंक बाजार का जिक्र किया गया है वह बैंकों के बीच अल्पावधि एवं दीर्घावधि -सभी बकाया एक्सपोजरों का जोड़ है।

चार्ट 2.28: अंतरबैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा



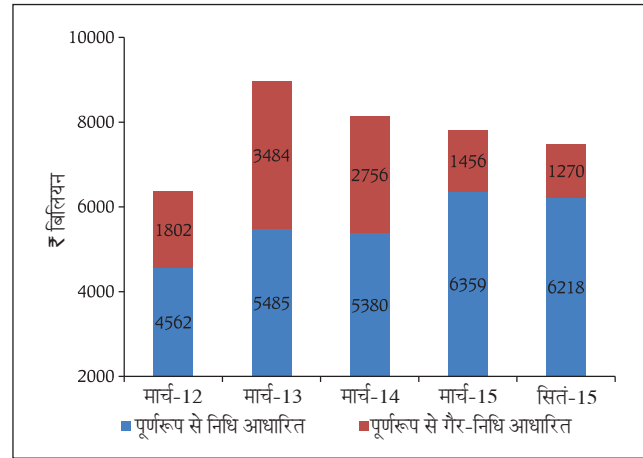
स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियां।

2.54 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ अंतर-बैंक बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रभुत्व है और यह हिस्सेदारी व्यापकरूप से बंटी हुई है, जैसा कि सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार हरफिनडाल-हर्समैन सूचकांक (एचएच इन्डैक्स) के लगभग 0.06 होने से संकेत मिलता है (चार्ट 2.28)।

2.55 अंतर-बैंक बाजार के कुल 83 प्रतिशत हिस्से को निरूपित करने वाले निधि आधारित लेनदेन, सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार ₹6.2 ट्रिलियन के स्तर पर रहे। गैर-निधि आधारित लेनदेन के हिस्से में 2013 से धीमी गति से गिरावट दिखाई दी (चार्ट 2.29)।

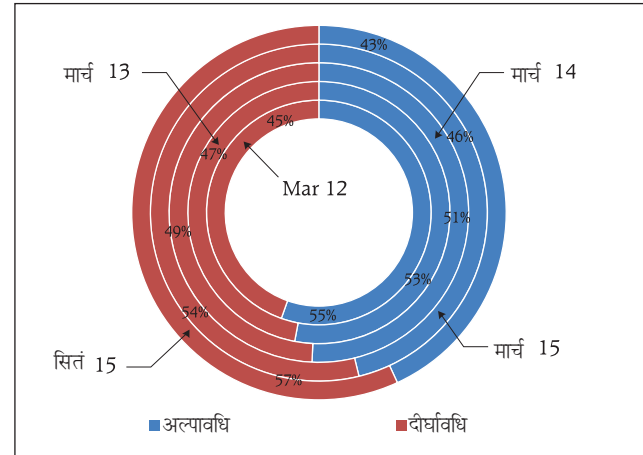
2.56 अंतर-बैंक बाजार अल्पावधि निधियां उपलब्ध कराने वाला प्रमुख स्रोत है किंतु दीर्घावधि लेनदेन⁴⁴ के संबंध में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो मार्च 2015 में बढ़कर 54 प्रतिशत (मार्च 2012 के 45 प्रतिशत की तुलना में) हो गई और इसके आगे, सितंबर 2015 में बढ़कर यह 57 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2.30)। निरपेक्ष रूप में, निधि आधारित दीर्घावधि अंतर-बैंक बाजार का कुल आकार सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार ₹3.5 ट्रिलियन से अधिक रहा। ऋणों एवं अग्रिमों, पूंजी एवं कर्ज लिखतों तथा दीर्घावधि निधि आधारित अंतरबैंक बाजार में जमाराशि जैसे अन्य का योगदान क्रमशः 67, 23 एवं 10 प्रतिशत था।

चार्ट 2.29: अंतरबैंक बाजार में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित लेनदेन



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियां।

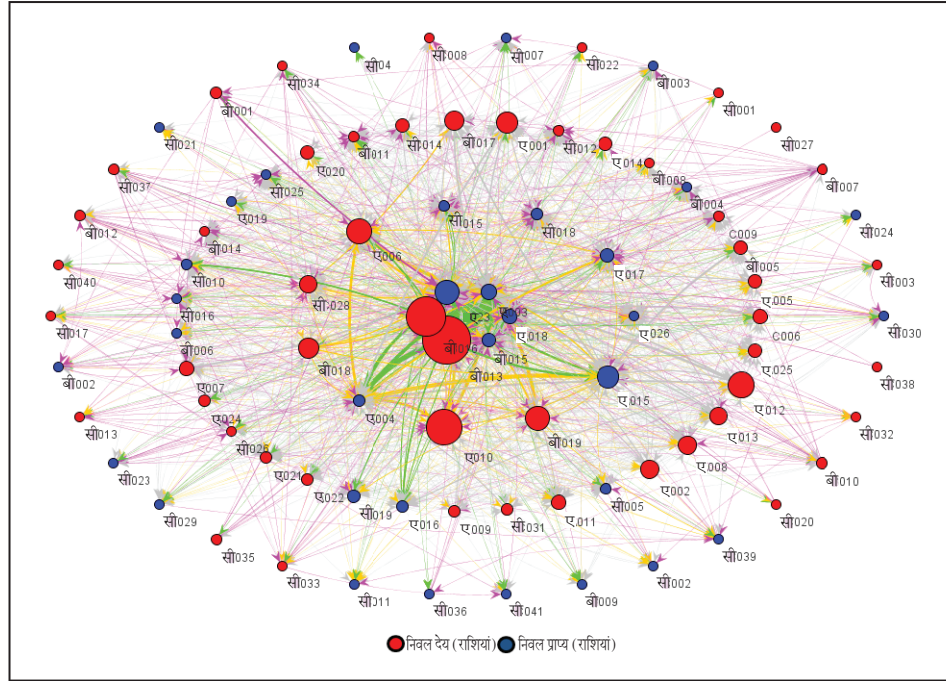
चार्ट 2.30: अल्पावधि एवं दीर्घावधि अंतरबैंक बाजार (निधि आधारित)



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी विवरणियां।

⁴⁴ वर्तमान विश्लेषण में, मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा, जमा प्रमाणपत्रों (सीडी), बाजार रिपो इत्यादि जैसे मुद्रा बाजार लिखतों के तहत हुए अंतरबैंक लेनदेन को अल्पावधि निधि आधारित लिखतों के रूप में मान्यता दी गई है। बांडों, इक्विटी निवेशों, ऋण एवं अग्रिमों, जमाराशियों इत्यादि को समाहित करने वाले निधि आधारित शेष एक्सपोजरों को दीर्घावधि निधि आधारित लिखतों के रूप में मान्यता दी गई है।

चार्ट 2.31: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (सितंबर 2015)



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

नेटवर्क की संरचना तथा अंतरसंबद्धता

2.57 जहां तक नेटवर्क की संरचना की बात है, पिछले चार वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता दृढ़ बनी रही जिसमें कुछ प्रमुख बैंकों का प्रणाली पर वर्चस्व रहा। हालांकि, संबद्धता का स्तर अलग-अलग बैंकों के लिए परिवर्तनशील रहा। जैसा कि चार्ट 2.31 में देखा जा सकता है, सबसे अधिक संबद्ध बैंक, नेटवर्क प्लॉट के सबसे भीतरी भाग (सबसे अंदरूनी घेरा) में थे। मार्च 2012 से सितंबर 2015 के बीच उनकी संख्या का दायरा नौ और छह के बीच रहा (सारणी 2.14)। पिछले तीन वर्षों के दौरान परस्पर संबद्धता का अनुमान व्यक्त करने वाले मानदंडों - संबद्धता अनुपात तथा क्लस्टर गुणांक⁴⁵ दृढ़ बने रहे।

वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क⁴⁶

2.58 अपेक्षाकृत व्यापक वित्तीय प्रणाली में अंतरसंबद्धता का आकलन करने के परिप्रेक्ष्य में बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों का प्रबंध करने वाली आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी-एमएफ),

सारणी 2.14: बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता सांख्यिकी

	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	सितं 15
संबद्धता अनुपात (%)	27.7	25.4	24.4	24.1	22.5
क्लस्टर गुणांक (%)	41.5	40.4	41.1	41.0	40.4
नेटवर्क संरचना के आंतरिक भाग में बैंकों की संख्या	9	6	7	8	6

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

⁴⁵ संबद्धता अनुपात : यह एक आंकड़ा है जो पूर्ण ग्राफ में सभी संभव संबंधों के सापेक्ष बिंदुओं के बीच संबंधों के विस्तार की माप करता है। क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक बिंदु आपस में कितना संबद्ध है। विशिष्ट रूप से, इस बात की अधिक प्रायिकता होनी चाहिए कि किसी बिंदु के दो पड़ोसियों (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) को आपसे में भी पड़ोसी होना चाहिए। नेटवर्क के लिए क्लस्टर गुणांक का अधिक होना, प्रणाली में विद्यमान उच्च स्तर पर स्थानीय परस्पर संबद्धता के अनुरूप होती है।

⁴⁶ भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रतिनिधि प्रतिदर्श के रूप में लिए गए संस्थानों में सभी एससीबी, 21 बीमा कंपनियां, 22 एएमसी-एमएफ, 34 एनबीएफसी, 20 अनुसूचित यूसीबी तथा चार अन्य एआईएफआई (नाबार्ड, निर्यात-आयात बैंक, एनएचबी तथा सिडबी) शामिल हैं।

एनबीएफसी, शहरी सहकारी बैंकों तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के बीच होने वाले निधि अंतरणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निधि उपलब्ध कराने में बीमा कंपनियों तथा उसके बाद के क्रम में एएमसी-एमएफ प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जबकि एससीबी तथा एनबीएफसी निधि प्राप्त करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत पीएसबी तथा विदेशी बैंकों के निवल आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उधार ली गई निधियों के कारण एक समूह के रूप में एससीबी अपेक्षाकृत व्यापक प्रणाली से निधियों का निवल प्राप्तकर्ता का समूह बन गया है। प्रणाली के अंतर्गत आने वाले चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) ने भी अपेक्षाकृत व्यापक प्रणाली के अंतर्गत चलनिधि में अपना योगदान दिया है (चार्ट 2.32 तथा सारणी 2.15)।

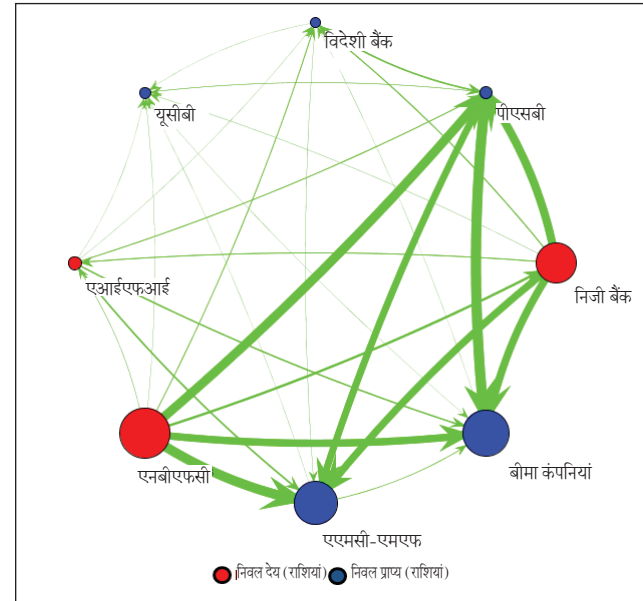
एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों एवं एससीबी की अन्योन्यक्रिया

2.59 सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों का संयुक्त एक्सपोजर ₹4.4 ट्रिलियन था, जो बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का 4 प्रतिशत था। एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह एक्सपोजर उनके प्रबंध के अधीन आस्ति (एयूएम)⁴⁷ के क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत को दर्शाता है। बैंकों में एएमसी-एमएफ का एक्सपोजर प्राथमिक रूप से जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) जैसे अल्पावधि लिखतों के माध्यम से हुआ है जबकि बीमा कंपनियों का बैंकों के दीर्घावधि लिखतों में वहनीय एक्सपोजर है। बैंकों में बीमा कंपनियों का 90 प्रतिशत के करीब एक्सपोजर दीर्घावधि लिखतों के माध्यम से हुआ। इससे बैंको की अपनी विनियामकीय पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों, विशेषरूप से बीमा कंपनियों, पर निर्भरता रेखांकित होती है (सारणी 2.16)।

एससीबी, एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों की एनबीएफसी से अन्योन्यक्रिया

2.60 जहां, एससीबी शेष वित्तीय प्रणाली से निवल निधियों के प्राप्तकर्ता हैं वहीं, एनबीएफसी शेष प्रणाली से निधियों के सबसे बड़े निवल प्राप्तकर्ता के रूप में उभरी हैं। सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, एनबीएफसी पर बैंकिंग क्षेत्र का बकाया एक्सपोजर ₹2 ट्रिलियन के करीब है। इसके अलावा, एनबीएफसी में एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों के एक्सपोजर से मार्च 2012 एवं

चार्ट 2.32: भारतीय वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट



स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.15: विभिन्न समूहों की अंतर-क्षेत्र आस्तियां और देयताएं

(₹ बिलियन)

	प्राप्य	देय
एससीबी	3362	6168
एएमसी-एमएफ	3615	272
बीमा कंपनियां	3775	101
एनबीएफसी	448	4448
यूसीबी	146	25
अन्य एफआई (नाबार्ड, निर्यात-आयात बैंक, एनएचबी, सिडबी)	1340	1672

टिप्पणी: प्राप्य राशियों और देय राशियों में एक ही समूह से संबंध रखने वाली संस्थाओं के बीच किए गए लेनदेन शामिल नहीं किए गए हैं।

स्रोत: भारिबैं, सेबी एवं आइआरडीएआई।

सारणी 2.16: बैंकों में बीमा कंपनियों के एक्सपोजर का पैटर्न (सितंबर 2015)

(₹ बिलियन)

	पूंजीगत निवेश	बांड तथा अन्य दीर्घावधि	कुल दीर्घावधि एक्सपोजर	समग्र एक्सपोजर	समग्र एक्सपोजर की तुलना में दीर्घावधि एक्सपोजर (%)
पीएसबी	454	730	1184	1375	86
पीवीबी	482	504	986	1057	93
एफबी	0	0.2	0.2	1	20
बैंकिंग क्षेत्र का कुल जोड़	936	1234.2	2170.2	2433	89

स्रोत: भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

47 1. एएमसी के एयूएम के स्रोत : भारतीय म्यूचुअल फंड संघ।

2. बीमा कंपनियों का एयूएम : व्यक्तिगत: बीमा कंपनियों द्वारा किया गया सार्वजनिक प्रकटीकरण।

सितंबर 2015 के बीच वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता चलता है (सारणी 2.17)।

संक्रामकता का विश्लेषण (कंटेजिअन एनालिसिस)⁴⁸

2.61 संक्रामकता विश्लेषण, नेटवर्क टूलों का प्रयोग करते हुए किया जाने वाला दबाव परीक्षण है जो एक या अधिक बैंकों के विफल होने होने की स्थिति में संभावित हानि का अनुमान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, किसी बैंक द्वारा प्रारंभ की गई हानि के विस्तार का पता लगाना भी इसके प्रणालीगत महत्व का सूचक है। किसी भी बैंक के विफल हो जाने से संक्रामकता की शुरुआत हो सकती है किंतु वर्तमान विश्लेषण के लिए सर्वाधिक निवल उधारकर्ताओं एवं निवल ऋणदाताओं को संक्रामकता का प्रारंभकर्ता बैंक (ट्रिगर बैंक) माना गया है। सैद्धांतिक रूप से, किसी निवल उधारकर्ता बैंक से ऋण-शोधन क्षमता की संक्रामकता प्रारंभ होगी जबकि निवल ऋणदाता बैंकों से चलनिधि की संक्रामकता प्रारंभ होगी। हालांकि, वास्तविकता में ऋण-शोधन क्षमता तथा चलनिधि संक्रामकता -दोनों के एक साथ घटित होने की संभावना है क्योंकि विशिष्ट रूप से कोई बैंक कुछ प्रतिपक्षियों के विषय में निवल उधारकर्ता होता है जबकि कुछ अन्य के संबंध में निवल ऋणदाता बना रहता है। बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष उधारकर्ता तथा शीर्ष ऋण दाता के असफल होने पर प्रणाली में उनकी टिअर-I पूंजी के आधार पर होने वाले असर का आकलन करने के लिए विश्लेषण का काम हाथ में लिया गया है (सारणियां 2.18 तथा 2.19)। संक्रामकता⁴⁹ के संबंध में विशिष्ट मान्यताओं के अधीन, शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक की विफलता बैंकिंग प्रणाली की टिअर-I पूंजी के 33.3 प्रतिशत नुकसान (संयुक्त ऋण-शोधन क्षमता चलनिधि संक्रामकता के अंतर्गत) के रूप में परिणत हो सकती है, जबकि शीर्ष ऋणदाता बैंक की विफलता टिअर-I पूंजी के 35.3 प्रतिशत नुकसान के रूप में परिणत हो सकती है। यह देखा जा सकता है कि बैंक सी (जो निवल उधारकर्ता बैंकों में तीसरे पायदान पर है) की विफलता निवल शीर्ष उधारकर्ता बैंक की विफलता की तुलना में अधिक गंभीर नुकसान में परिणत हुआ, क्योंकि शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक की संबद्धता बेहतर है।

औसत सहसंबंध पर आधारित प्रणालीगत जोखिम माप के माध्यम से संक्रामकता का विश्लेषण

2.62 बैंकों के जोखिमों के सहगामी परिवर्तनों, विशेषरूप से विपत्ति की अवस्था में, पर विचार करते हुए बैंकों के बीच परस्पर

सारणी 2.17 : एनबीएफसी में एससीबी, एएमसी-एमएफ तथा बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	सितं-15
एससीबी	1513	1453	1516	1595	1927
एएमसी-एमएफ	425	624	756	1008	1376
बीमा कंपनियां	780	880	965	1080	1064

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 2.18 : निवल उधारकर्ता बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई संक्रामकता

शीर्ष निवल उधारकर्ता बैंक	बैंकिंग प्रणाली की कुल टिअर-I पूंजी की प्रतिशत हानि		
	ऋण-शोधन क्षमता की संक्रामकता	चलनिधि की संक्रामकता	ऋण-शोधन क्षमता एवं चलनिधि की संयुक्त संक्रामकता
बैंक ए	7.6	0.9	33.3
बैंक बी	4.2	0.4	4.4
बैंक सी	6.1	1.8	41.9
बैंक डी	2.4	0.2	2.6
बैंक ई	2.1	0.1	2.3

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

सारणी 2.19 : निवल उधारदाता बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई संक्रामकता

शीर्ष निवल उधारदाता बैंक	बैंकिंग प्रणाली की कुल टिअर-I पूंजी की प्रतिशत हानि		
	ऋण-शोधन क्षमता की संक्रामकता	चलनिधि की संक्रामकता	ऋण-शोधन क्षमता एवं चलनिधि की संयुक्त संक्रामकता
बैंक ए	0.9	17.3	35.3
बैंक बी	0.4	11.8	12.9
बैंक सी	2.4	6.5	12.4
बैंक डी	2.1	7.0	9.2
बैंक ई	0.4	4.3	5.0

स्रोत : भारिबैं की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ की गणनाएं।

⁴⁸ संक्रामकता विश्लेषण में प्रयुक्त प्रणालियों के विवरण अनुबंध 2 में उपलब्ध कराए गए हैं।

⁴⁹ कृपया कार्यप्रणाली के लिए अनुबंध 2 देखें।

संबद्धता का प्रयोग करते हुए संक्रामकता का अध्ययन महत्वपूर्ण है। सहगामी परिवर्तनों की जांच से, प्रणालीगत जोखिम में परस्पर संबद्धता की माप का प्रयोग करने का संकेत मिलता है। उछाल तथा

विपत्ति की अवधियों में बैंकों के बर्ताव को समझने के लिए इक्विटी मूल्यों के प्रतिलाभ का प्रयोग करते हुए किए गए विश्लेषण के परिणामों को बॉक्स 2.1 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 2.1 : इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों पर आधारित प्रणालीगत जोखिम की माप

पृष्ठभूमि

आस्ति मूल्य अस्थिरता से मूल्यन तथा सहयोगी परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार जोखिम अंतरण का पता चलता है।

पैट्रो, एट अल (2010) का तर्क है कि प्रणालीगत असफलता के लिए बैंकों के बीच उच्च सहसंबंध का होना आवश्यक शर्त है क्योंकि यदि सहसंबंध निम्न हों तो किसी एक घटना के कारण अपेक्षाकृत अल्प समायावधि में विस्तृत आधार वाली गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि स्टॉक रिटर्न सहसंबंध समग्ररूप से बाजार के लिए प्रणालीगत जोखिम का उपयोगी संकेतक है। लेखकों ने यह प्रेक्षित किया कि स्टॉक रिटर्न सहसंबंध अधिक प्रगतिशील तथा मान्यता आधारित है। हाल के वित्तीय संकट में आस्ति प्रतिलाभों की संभावनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और इसलिए विश्लेषण के लिए स्टॉक रिटर्न सहसंबंध उपयोगी टूल हो सकता है।

कार्यप्रणाली

इस प्रणाली के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के लिए 'प्रणालीगत जोखिम माप' की एससीबी के दैनिक इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों के बीच औसत सहसंबंध के रूप में गणना की गई। इस मामले में, चुनिंदा एससीबी के दैनिक इक्विटी प्रतिलाभों के बीच औसत युग्म-वार सहसंबंधों की गणना द्वि-वार्षिक परिवर्तनशील विंडो प्रणाली का प्रयोग करते हुए की गई।

प्रेक्षण

22 एससीबी के दैनिक इक्विटी प्रतिलाभों के बीच औसत युग्म-वार सहसंबंधों के आधार पर मापे गए प्रणालीगत जोखिम से पता चलता है कि 2006 और 2009 के बीच प्रणालीगत जोखिम बढ़ा, किंतु उसके बाद इसमें कमी आना प्रारंभ हो गया। प्रणालीगत जोखिम में 2011 के उत्तरार्द्ध में वृद्धि पुनः प्रारंभ हुई जिससे बैंकों के इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों में अधिक सह-परिवर्तन का संकेत मिलता है। हाल के वर्षों में इसमें अधोगामी परिवर्तन देखा गया है (चार्ट 1)।

उछाल के समय और मंदी के समय में सहसंबंध आधारित प्रणालीगत जोखिम माप में परिवर्तन के अंतर को स्पष्ट करने के लिए दो उप-अवधियों मार्च 2009 से अक्टूबर 2010 (उछाल का समय) और जनवरी 2008 से नवंबर 2008 (मंदी का समय) के लिए निफ्टी तथा बैंक-निफ्टी सहित प्रणालीगत जोखिम माप का अनुमान किया गया। विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक के इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों के बीच सह-परिवर्तन मंदी के दौरान उछाल की अवधि की तुलना में अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंकों के इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों के बीच सहसंबंध वित्तीय विपत्ति/संकट के समय बढ़ता है और उछाल के समय में इसमें गिरावट आती है।

चार्ट 1 : प्रणालीगत जोखिम माप में परिवर्तन : एससीबी



स्रोत : ब्लूमबर्ग के आंकड़े तथा स्टॉफ की गणनाएं

वास्तविक जीडीपी वृद्धि (समकालीन के साथ ही एक तिमाही पीछे की) के साथ प्रणालीगत जोखिम सहसंबंध ऋणात्मक पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि प्रणालीगत जोखिम माप तथा वास्तविक जीडीपी वृद्धि में विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है अर्थात्, प्रणालीगत विपत्ति (वित्तीय बाजारों में) का आर्थिक गतिविधियों (वास्तविक जीडीपी वृद्धि द्वारा मापी गई) से प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। हालांकि, सहसंबंधों के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले संबंध गैर-कारक रूप में दर्शाए गए हैं और इससे, संबंध में कारण और प्रभाव पता नहीं चलता किंतु यह सिर्फ सह-परिवर्तन की दिशा और शक्ति को समाहित करता है।

बैंकों के इक्विटी मूल्य प्रतिलाभों के औसत युग्म-वार सहसंबंध पर आधारित सूचक के संबंधों के साथ में वित्तीय बाजारों (निफ्टी और बैंक-निफ्टी का प्रयोग करते हुए) के व्यवहार के साथ ही आर्थिक गतिविधियों (वास्तविक जीडीपी वृद्धि) से संकेत मिलता है कि यह प्रणालीगत जोखिमों के लिए उपयोगी सूचक हो सकता है।

संदर्भ

बिलिओ मोनिका, मिला गेटमान्स्की, एन्ड्रू डब्लू. लो एवं लोरिआना पेलिज्जॉन (2012), 'वित्त एवं बीमा क्षेत्रों में संबद्धता और प्रणालीगत जोखिम की अर्थमितीय माप', वित्तीय अर्थशास्त्र पत्रिका, 104 (3), 535-59.

चैन-लाउ जॉर्ज ए. (2013), 'प्रणालीगत जोखिम निगरानी' जोखिम पुस्तकें।

पैट्रो दिलीप के., मिन क्वी एवं जिआन सुन (2010) 'प्रणालीगत जोखिम का एक सामान्य सूचक', मिमीओ, मुद्रा नियंत्रक का कार्यालय तथा जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय।

अध्याय III वित्तीय क्षेत्र विनियमन

वैश्विक वित्तीय क्षेत्र विनियामकीय सुधार की कार्यसूची को यद्यपि धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, क्योंकि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की संरचना अलग-अलग है और उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं भिन्न हैं, वहीं समस्त क्षेत्रों में इन सुधारों के लागत-लाभ के मैट्रिक्स को बेहतर तौर पर समझने की आवश्यकता है। नई और अत्यधिक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के आगमन से शायद जोखिम के प्रमुख संचालक अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं जहां अधिकांश परिवर्तन इस गति से घटित हो रहे हैं कि वे सतत रूप से विनियामक के विवेक को चुनौती देंगे। जहां भारत में कारपोरेट ऋण बाजार को विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों के कुछ परिणाम दिखाई देने लगे हैं, वहीं पर बैंक से वित्त लेने की निर्भरता निरंतर बनी हुई है, भले ही बैंक, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंक आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता और पूंजी की चुनौतियों का सामना क्यों न कर रहे हों।

भारतीय पूंजी बाजार का विनियमन बदलते हुए कारोबारी वातावरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई शुरुआत करने वाली कंपनियों की पहुंच पूंजी बाजार तक बनाने के लिए विशेष प्लेटफार्म का निर्माण करना रहा है। यह पाया गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाहों के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित अस्थिरता को घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा स्थिर बनाने में सहायता मिल रही है। बीमा और पेंशन क्षेत्र से भी पूंजी बाजार को स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो रही है क्योंकि इन क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय सुधार की कार्यसूची

कार्यान्वयन में हुई प्रगति और कतिपय दुविधाएं

3.1 जी-20 के सुधार उपायों की डिजाइन का चरण लगभग पूरा होने को है, किंतु अभी भी इनके कार्यान्वयन एवं प्रभाव के संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा कतिपय विनियामकीय उपायों से उत्पन्न होने वाले गैर-इरादी परिणामों की चुनौती के बारे में बहस जारी है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की रिपोर्ट¹ में भी यह पाया गया है यद्यपि समस्त सुधारों को लागू करने की प्रगति नियमित किंतु असमान रही। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के पिछले अंकों में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की अलग-अलग संरचना और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त क्षेत्रों में इन सुधारों के लागत-लाभ के मैट्रिक्स को बेहतर तौर पर समझने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह बहस का मुद्दा बना हुआ है कि जहां वित्तीय प्रणाली कम जटिल है वहां अत्यधिक जटिल पूंजीगत रेगुलेशन पर फोकस करना कितना उचित है। यदि उभरते हुए पूंजीगत रेगुलेशंस इस तथ्य से संचालित हैं कि कुछ

न्यायाधिकारक्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं ने अपने डोमेन को जोखिमपूर्ण क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है और प्रत्याशित अपर्याप्त पूंजी का लीवरेज ले रही हैं, तब ऐसी स्थिति में कम जटिल क्षेत्रों में जहां बुनियादी वित्तीय सेवाओं का विस्तार अपेक्षाकृत कम है वहां कठोर पूंजीगत रेगुलेशंस लागू किए जाने का बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में यह भी मत है कि इस स्थिति से एक 'भ्रामक संरचना' पैदा होगी जो प्रणालीगत स्थिरता तथा उसके असर को प्रभावित करेगी भले ही पृथक संस्थाएं कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हों।²

3.2 वित्तीय बाजार एक जटिल प्रणाली है और उसमें निहित एक सीधी रेखा में न चलने वाली प्रक्रियाओं की स्वतः प्रतिक्रियाएं होती हैं, यहां तक कि एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी बड़े पैमाने पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। एक-दूसरे से अत्यधिक निकट से जुड़ती हुई वित्तीय प्रणाली में नई और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के आगमन से शायद जोखिम के प्रमुख संचालक अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं जहां अधिकांश परिवर्तन इस गति से घटित हो रहे हैं कि वे सतत रूप से विनियामकों की पहुंच और उनके विवेक को चुनौती दे रहे हैं।

¹ एफएसबी (2015), 'जी-20 वित्तीय विनियामकीय सुधार का कार्यान्वयन और प्रभाव', वार्षिक रिपोर्ट, 9 नवंबर। <http://www.financialstabilityboard.org/2015/11/implementation-and-effects-of-the-G20-financial-regulatory-reforms/> पर उपलब्ध

² "विनियामकीय सुधार - पुनःचिंतन", नोबूचिका मोरी, आयुक्त, वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान। थामसन रॉयटर छठी वार्षिक पैन एशिया रेगुलेटरी सम्मेलन, 13 अक्टूबर 2015, हांगकांग

बॉक्स 3.1 : 'परिवर्तनकारिता' (डिसरप्टिव) का प्रभाव - 'ब्लॉक श्रृंखला' प्रौद्योगिकी³

वर्चुअल करेंसी योजना (डिजिटल करेंसी जैसे बिट क्वाइन) के आविर्भाव के संबंध में जो प्रारंभिक चिंताएं उत्पन्न हुईं वे बड़े मुद्दों को लेकर थीं जिसका संबंध ऐसी निजी-स्वामित्व वाली, इंटरनेट युक्त वैकल्पिक करेंसी प्रणाली की निहित डिजाइन एवं प्रोत्साहन परक-संरचना तथा परंपरागत मौद्रिक प्रणाली पर उनसे पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। यद्यपि उनके गुण-दोष के बारे में विभिन्न मत हैं, फिर भी उनके मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता की घटनाओं और कतिपय वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजों की असफलता ने उनके पुनः उभरने की संभावना को क्षीण सिद्ध कर दिया है। दूसरी ओर, उनका गुमनाम स्वरूप विश्व के धन-शोधन नियमों के विरुद्ध है और इस प्रकार उनका अस्तित्व ही प्रश्नों के घेरे में है। जहां इन सब मुद्दों और उपभोक्ता संरक्षण की चुनौतियों एवं कराधान संबंधी पहलुओं पर बहस जारी है, वहीं 'ब्लॉक श्रृंखला' जैसी प्रमुख तकनीकी अवधारणा, जो इस प्रकार की गुप्त-संदेश-करेंसी प्रणाली को प्रश्रय देती है, पर अब लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित हो रहा है। जालसाजी से लड़ने की इसकी क्षमता को देखते हुए 'ब्लॉक श्रृंखला' प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय बाजार की कार्यप्रणाली, संपार्श्विक शिनाख्त (उदाहरण के लिए भूमि संबंधी अभिलेख) और भुगतान प्रणाली में भारी परिवर्तन आने की संभावना है।

पारंपरिक (और वर्तमान में प्रयुक्त) प्रणाली 'विश्वास' और इस प्रकार की 'केंद्रीय' संस्थाओं/प्रतिपक्षों की 'विनियामकीय' एवं 'नियंत्रण'

शक्तियों के आधार पर कार्य करती है। इसके विपरीत, 'ब्लॉक श्रृंखला' प्रौद्योगिकी साझा, सुरक्षित एवं सरकारी लेजर प्रणाली पर आधारित है जिसपर किसी एक यूजर ('केंद्रीय') का नियंत्रण नहीं होता है और उसका रखरखाव आमतौर पर इस प्रणाली में सभी यूजर्स/सहभागियों द्वारा सामूहिक रूप से सहमत एवं कड़ाई से लागू किए गए नियमों पर आधारित होता है। अतः 'ब्लॉक श्रृंखला' प्रौद्योगिकी उन सहभागियों/संस्थाओं के बीच लेनदेन/सहयोग को सहज बनाती है जिनके पास एक-दूसरे पर विश्वास, और इसके लिए उन्हें अनावश्यक रूप से किसी पृथक एवं भरोसेमंद 'केंद्रीय' प्रतिपक्षी⁴ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जहां साझा और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुरक्षित सरकारी लेजर्स की संकल्पना ने वित्तीय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना बढ़ा दी है, वहीं इस प्रणाली की पूरी क्षमता तथा उसके उपयोग से होने वाले प्रभाव अभी भी ज्ञात नहीं हैं।

वहीं पर, रेगुलेटर्स तथा प्राधिकारियों को इस संबंध में होने वाली प्रगति पर नजर रखनी होगी क्योंकि विश्व के कई बड़े बैंकों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वे 'निजी ब्लॉक श्रृंखला' की स्थापना करने एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग को मानकीकृत करने हेतु उद्योग-स्तर पर प्लेटफार्म बनाने की दिशा में संयुक्त प्रयास को समर्थन प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बैंकों के बैंक-ऑफिस की कार्यप्रणाली को बदलने, भुगतान प्रणाली एवं व्यापार वित्त की गति को बढ़ाने एवं किफायती बनाने की अपार क्षमता है।

3.3 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी इस जरूरत पर बल दिया गया था कि रेगुलेटर्स और नीति-निर्याताओं को चाहिए कि वे संस्थाओं की स्थापित संरचना तथा बाजार-प्रणाली के संबंध में प्रौद्योगिकीयुक्त नवोन्मेष जैसे - 'आभासी मुद्रा योजनाओं' और 'समूह-से-समूह को उधार' से उत्पन्न चुनौतियों का उत्तर देने के लिए तैयार रहा करें। जहां इस प्रश्न पर कि इस प्रकार के कतिपय नवोन्मेष का मौद्रिक नीति और मैक्रो-पूडेंशियल नीतियों के कारगर होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहस जारी है, वहीं यह समझने की आवश्यकता है कि लागत में कटौती, प्रभावकारिता में सुधार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कारोबार तथा सेवा-डिलीवरी मॉडल्स को पुनः बनाने हेतु इस प्रकार के नवोन्मेष में निहित प्रौद्योगिकियों की क्षमता को समझा जाए(बॉक्स 3.1)।

परिचालनगत जोखिम के लिए व्यापक परिदृश्य की आवश्यकता

3.4 वैश्विक वित्तीय संकट को संकट के दौरान और उसके तुरंत बाद इसे ऋण तथा चलनिधि जोखिम के संकट के रूप में अभिहित किया गया था। लेकिन, अब यह निश्चित हो गया है कि प्रणालीगत जोखिम के जितने भी स्रोत थे वे परिचालनगत जोखिमों⁵ से संबंधित कारकों से उत्पन्न हुए थे या निकले थे और प्रसारित हुए थे। इनमें से कुछ कारकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे - निष्पादित कार्यों में अंतर्निहित 'हितों का टकराव', प्रतिकूल चयन, अपर्याप्त सावधानी, प्रलेखीकरण प्रक्रिया का गलत उपयोग, अपर्याप्त उत्पाद और जोखिम के प्रति कम जागरूकता एवं समझ, नैतिकता का पतन, कारपोरेट गवर्नेंस तंत्र की कमजोरी और कमजोर

³ ब्लॉक श्रृंखला एक वर्गीकृत डाटाबेस है जिसमें डाटा अभिलेखों की सूची निरंतर बढ़ती रहती है जिसमें हेरफेर या संशोधन नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि डाटा-संग्रहण नोड पर कार्य करने वाले आपरेटर द्वारा भी नहीं किया जा सकता (विकीपीडिया)

⁴ बैंक ऑफ इंग्लैंड, तिमाही बुलेटिन 2014 तीसरी तिमाही, "भुगतान प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष और डिजिटल करेंसी का आविर्भाव"

⁵ परिचालनगत जोखिम वह हानि है जो अपर्याप्त प्रक्रियाओं या उनके असफल हो जाने, लोगों और प्रणाली या बाह्य घटनाओं के कारण होती है। इस परिभाषा में विधि जोखिम शामिल है किंतु कार्यनीति और प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)। संकट की गहनता ने उस समय के प्रचलित जोखिम प्रबंधन ढांचे की अपर्याप्तता को रेखांकित किया है और इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है कि वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार से अपने जोखिमों को नियंत्रित करें।

3.5 उभरते हुए अनेक जोखिम जैसे - प्रौद्योगिकीगत जोखिम, सायबर जोखिम, धोखाधड़ी का जोखिम, लोगों और गवर्नेंस से जुड़े जोखिम, व्यवसाय और नियंत्रण प्रक्रियाएं, विधिक जोखिम आदि सभी परिचालनगत जोखिम की परिधि में आते हैं। परिचालनगत जोखिम, वित्तीय संस्था की कार्य-प्रणाली के प्रत्येक पहलू में व्याप्त होता है। परिचालनगत जोखिमों की पहचान करना, उनको मापना तथा प्रबंधन करना अभी भी वित्तीय संस्थाओं तथा रेगुलेटरी प्राधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

3.6 बाजार-तंत्र और विधिक कार्यवाहियों में हेराफेरी करने में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बड़े विश्व स्तरीय बड़े बैंकों की भूमिका एवं उनके कार्य-संचालन की रिपोर्ट किए जाने पर भारी दण्ड लगाए गए हैं और कुछ मामलों में निपटान स्वरूप भारी राशि देनी पड़ी है, जिसने वित्तीय प्रणाली के सहज रूप से कार्य करने के लिए 'नैतिकता' संबंधी आचरण के महत्व के मुद्दे को उठा दिया है। वहीं पर, इन मुद्दों का प्रत्येक संस्था एवं पूरी प्रणाली दोनों स्तर⁶ पर समाधान करना रेगुलेटर्स के लिए और भी चुनौतीपूर्ण बन गया है।

3.7 अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेगुलेटरी उपकरणों को और भी कुशाग्र बनाने की आवश्यकता है क्योंकि रेगुलेटरी रुझान स्वयं भी त्रुटिपूर्ण, पश्चगामी हो सकते हैं और उनमें "ईस्टलैंड सिंड्रोम"⁷ की संभावना हो सकती है और / अथवा आंतरिक तौर पर तथा समस्त रेगुलेटरी भूमि दोनों पर असंगत हों, और इस प्रकार से वे स्वयं परिचालनगत जोखिम के संचालक बन रहे हों।

3.8 परिचालनगत जोखिम के महत्व को रेखांकित करना अनिवार्य है क्योंकि यह संपूर्ण प्रणाली में जोखिम के स्तर को तीव्र बना सकता है तथा इसमें भयंकर रूप से घटित होने की क्षमता होती है, जो वित्तीय संस्थाओं के बड़े हुए आकार, अंतर-संबद्धता तथा जटिलताओं पर निर्भर करता है। अतः, परिचालनगत जोखिम के मुद्दों तथा इसके प्रणालीगत महत्व के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे

परिचालनगत जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार के मापने की चुनौतियों से कहीं आगे रखकर देखने की आवश्यकता है।

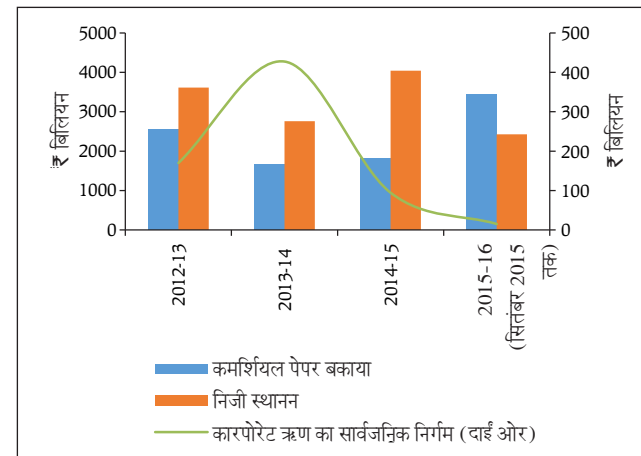
घरेलू वित्तीय प्रणाली

बैंकिंग क्षेत्र

आर्थिक वृद्धि के लिए बैंक ऋण का महत्व बना हुआ है

3.9 बैंक ऋण की वृद्धि में गिरावट, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां आस्ति-गुणवत्ता का दबाव अपेक्षाकृत अधिक है (चार्ट 2.1 और 2.2 अध्याय 2), से यह संकेत मिलता है कि बैंकों का वर्तमान फोकस अन्य कारकों के साथ-साथ तुलनपत्र के परिमार्जन पर है। इसे ध्यान में रखते हुए कारपोरेट बाण्ड बाजार का विकास करना अत्यंत जरूरी हो गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 के दौरान कारपोरेट बाण्ड बाजार के माध्यम से वाणिज्य-क्षेत्र को ऋण का प्रवाह काफी बढ़ गया है जैसाकि कारपोरेट बाण्ड के निजी स्थानन तथा कमर्शियल पेपर के बकाया निर्गमों की प्रवृत्ति से देखा जा सकता है (चार्ट 3.1)। चूंकि, कारपोरेट बाण्ड का सरकारी निर्गम मंद था इसलिए कारपोरेट बाण्ड बाजार की समग्र प्रवृत्ति से शायद अभी यह संकेत न मिलें कि कारपोरेट क्षेत्र अब इस पर पूरी तरह निर्भर हो

चार्ट 3.1: कारपोरेट ऋण और कमर्शियल पेपर के बकाया निर्गम



टिप्पणी: निजी स्थानन और कारपोरेट ऋण के सार्वजनिक निर्गम संबंधित सेबी के आंकड़े सितंबर 2015 के अंत के हैं। भारिबैंक के कमर्शियल पेपर के आंकड़े 15 नवंबर, 2015 तक के अद्यतन आंकड़े हैं।

स्रोत: सेबी और भारि. बैंक

⁶ संकल्पना "प्रणालीगत परिचालनात्मक जोखिम" [मैक्कनेल और ब्लैकर (2011)]

⁷ वर्ष 1915 में दृश्य-दर्शन हेतु बनाया गया एसएस ईस्टलैंड जहाज मिचिगन झील में उलट गया था जिसमें 824 लोगों की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह अतिभार था और यह टाइटेनिक आपदा के बाद लागू किए गए कानून के पालन के कारण हुआ था। 'समुद्र में जीवन रक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' के अनुसार जहाज पर 2500 से अधिक यात्रियों के लिए जीवन-रक्षा नाव रखी गई थी। (<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5ca05faa-353c-11e5-bd8b-35e55c8ae175.html#axzz3rRANZaqW>)।

गया है, तथापि, विशेष रूप से बुनियादी सुविधा क्षेत्र (दीर्घकालिक वित्त हेतु) की आवश्यकताएं बैंकिंग क्षेत्र से अभी भी दूर हैं।

पूंजी डालने के साथ ही दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की तात्कालिकता

3.10 बैंकों, विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निष्पादन में सुधार आने में सबसे बड़ी बाधा आस्ति की गुणवत्ता पर दबाव बने रहना है, जिसका निवारण सबसे पहले किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के ऋण की वृद्धि को एक इष्टतम स्तर के नीचे न रहने दिया जाए। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आस्ति-गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी, साथ ही यह भी लिखा गया था कि इनके समाधान करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण रेगुलेटरी उपाय किए गए थे (बॉक्स 3.2)। जहां कुछेक दबावग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में किए गए

नये नीतिगत उपायों से दबाव को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं इसके पूरे परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा।

3.11 रेगुलेटरी अभिनिर्धारण (बासेल III की अपेक्षाओं को चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने पर) के कारण अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के अलावा बैंकों को थोड़ी और पूंजी के सहारे की जरूरत पड़ती है ताकि आस्ति गुणवत्ता दबाव के प्रभाव के कारण वे अपनी वर्तमान स्थिति को कस सकें। लेकिन, चूंकि 'चूक करने की दूरी' का मार्ग सीधा नहीं होता है और आस्ति-गुणवत्ता में मामूली सी कमी 'चूक करने की संभावना' को बढ़ा देता है, इसलिए अशोध्य आस्तियों के समाधान के लिए उपयुक्त रणनीति बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि लगाई गई किसी अतिरिक्त पूंजी के फायदे हासिल किए जा सकें। इसके व्यवहारगत आयाम भी हैं, क्योंकि संभावित हानि अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति में उधारदाता और उधारकर्ता दोनों 'पूरी तरह से जोखिम विमुखता' तथा 'बड़ा

बॉक्स 3.2 : आस्ति-गुणवत्ता के संबंध में हाल में की गई विनियामकीय पहल

रिजर्व बैंक ने बैंकों में ऋण-जोखिम प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए कई विनियामकीय पहल की हैं जैसे - 01 अप्रैल, 2015 से अग्रिमों के पुनर्वर्गीकरण पर दिए गए विशेष आस्ति-वर्गीकरण लाभ को हटा लेना, 'मानक' पुनर्वर्गीकृत आस्तियों के प्रावधान की राशि को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना और अन्य के मध्य पुनर्वर्गीकृत आस्तियों में प्रवर्तकों के अंशदान को बढ़ाना। ये उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप किए गए हैं और पुनर्वर्गीकरण के नाम पर ऋण को सदाबहार रखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए हैं।

जनवरी, 2014 में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन हेतु संरचना व्यापक रूप से प्रारंभ की गई थी जिसमें बड़े ऋणों से संबंधित जानकारी के लिए एक केंद्रीय सूचना रिपाजिटरी की स्थापना का उल्लेख किया गया था ताकि उधारदाताओं के लिए सूचना एकत्रित की जा सके, उनका भंडारण और ऋण संबंधी आंकड़ों का प्रसारण किया जा सके। अन्य जो उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं - संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) की स्थापना, बैंकों द्वारा समस्यामूलक खातों की शीघ्र पहचान करना, ऐसे ऋण खातों का समय पर पुनर्वर्गीकरण जो अर्थक्षम हैं, और बैंकों को ऋणों की वसूली के लिए तत्परता से कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना। असहयोगी उधारकर्ताओं जैसी अवधारणा भी प्रारंभ की गई है, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए अधिक प्रावधान करने के मानदंड बनाए गए हैं। जेएलएफ में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तथा निष्पक्ष नज़रिया रखने वाली उच्च स्तरीय निकाय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) को अनुमोदन प्रदान करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने हाल ही में जेएलएफ - सशक्त समूह

(जेएलएफ - ईजी) प्रारंभ किया है, जिसमें जेएलएफ के अंतर्गत विशेष उधारकर्ता को उधार देने या न देने वाले बैंकों के शीर्षस्थ प्रबंधन से कार्यपालक निदेशक के स्तर का प्रतिनिधित्व है।

रिजर्व बैंक के कार्यनीति ऋण पुनर्वर्गीकरण (एसडीआर) में यह प्रावधान है कि जेएलएफ के अंतर्गत उधारदाता के पास यह विकल्प है कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के संशोधित प्राइसिंग फार्मूला के तहत अपने मौजूदा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि वे उधार लेने वाली उस कंपनी के सामूहिक रूप से बड़े शेयरधारक बन जाएं जो पुनर्वर्गीकरण पैकेज के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही हैं। इस प्राइसिंग फार्मूला से बैंकों को परिवर्तन-संबंधी हानि न्यूनतम होती है, जिसे 18 महीने का अच्छा खासा आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान किया गया है। उधारकर्ता संस्थाओं, जो उधारदाता बैंकों द्वारा अत्यधिक त्याग के बावजूद दबाव में हैं जिसकी प्राथमिक वजह उनकी परिचालनगत/प्रबंधकीय अक्षमताएं हैं, के स्वामित्व में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में बैंकों को ढील प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे उन उधारकर्ता संस्थाओं को दी गई ऋण सुविधा का उन्नयन कर सकते हैं जिनके स्वामित्व एसडीआर से बाहर रहकर (उदाहरण के लिए गिरवी को तलब करके, बाद में शेयरों की बिक्री करना, नये शेयरों को नये प्रवर्तकों को जारी करना तथा नये प्रवर्तक द्वारा उधारकर्ता कंपनी का अभिग्रहण करना) बदल दिए गए हैं और कतिपय शर्तों के अधीन इस प्रकार से स्वामित्व में परिवर्तन करके उसे 'मानक' की श्रेणी में लाया गया है।

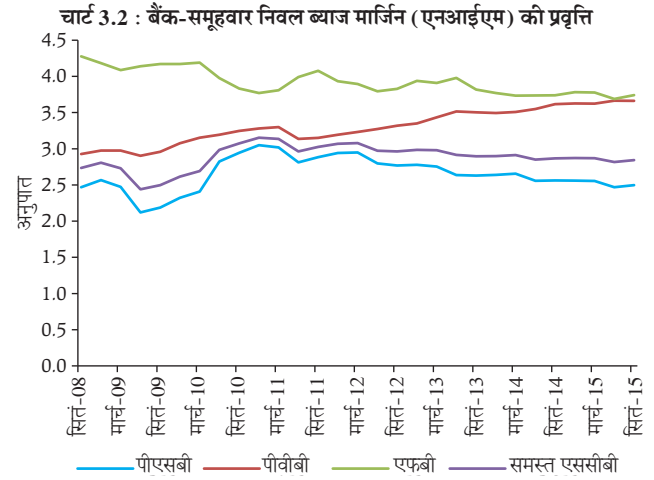
दांव खेलने के प्रलोभन' के बीच स्वयं को परम स्थिति में रखना चाहेंगे। इस संदर्भ में प्रस्तावित दिवालियापन और बैंकरप्सी संहिता विधेयक शीघ्र पारित होने से, जिसमें समयबद्ध एवं पूर्वानुमानित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया होगी और साथ ही वित्तीय क्षेत्र के लिए समाधान कारपोरेशन की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

3.12 ऋण की धीमी वृद्धि के वातावरण में बैंकों को पूंजी जुटाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादातर बैंक प्रावधान के स्तर को कम करने लगेंगे ताकि अपनी लाभप्रदता की रक्षा कर सकें। यदि एक सीमा तक किए गए 'प्रावधान' पर्याप्त नहीं हैं और 'प्रत्याशित' एवं 'अप्रत्याशित' हानि के बफर के रूप में पूंजी में वृद्धि नहीं हो पाती है, तब बैंकों को निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) अधिक रखने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसे बैंकिंग उद्योग के कुछ क्षेत्र में रेगुलेटरी पूंजी के प्रति विकल्प के रूप में माना जाता है। एससीबी के निवल ब्याज मार्जिन, विशेष रूप से पीएसबी और विदेशी बैंकों, में हाल के समय में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है (चार्ट 3.2)।

दबावग्रस्त आस्तियों का तत्काल समाधान प्राप्त करने की चुनौतियां

3.13 बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने उन संसाधनों को मुक्त करें जो दबावग्रस्त आस्तियों से बंध गए हैं और उसके लिए अधिक प्रावधान करने से उनपर बोझ बढ़ेगा। ऐसा करने के लिए एक रास्ता यह भी है कि वे इस प्रकार की दबावग्रस्त आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को बेच दें। पूरे विश्व में अशोध्य आस्तियों की समस्या का निदान करने वाली संस्थाओं का निर्माण प्रणालीगत संकट को रोकने के लिए हुआ है ताकि वे 'एक अशोध्य बैंक' बनाते हुए कमर्शियल बैंकों की सुरक्षा कर सकें और जो समस्त प्रणाली से दबावग्रस्त ऋणों को अपने पास ले लें। सरकार, इन संस्थाओं को कानूनी, विनियामकीय, राजकोषीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार की संस्था बनाने का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की पूंजी की रक्षा करना है क्योंकि बैंकों को अशोध्य आस्तियों के लिए धन अलग से रखना पड़ता है जो उनकी पूंजी को खाली कर देता है।

3.14 हालांकि, भारतीय एआरसी मॉडल में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राजकोषीय सहायता या कर संबंधी रियायत की बात नहीं कही गई है। इसमें बैंकिंग प्रणाली की अशोध्य आस्तियों को अनिवार्य रूप से अंतरित करना भी नहीं दिया गया है। यह

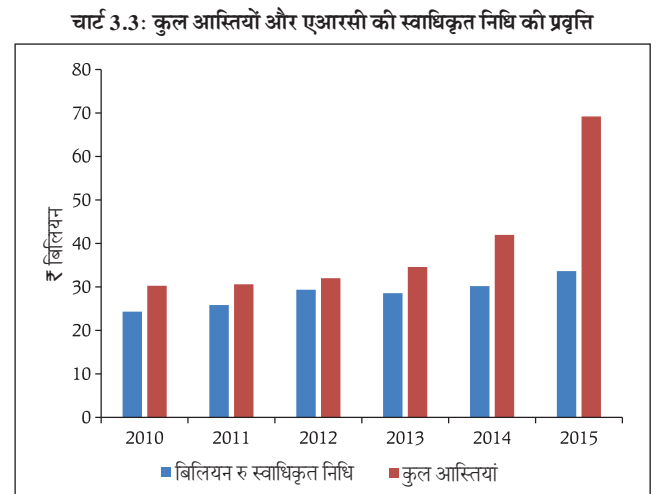


टिप्पणी: एनआईएम की गणना निवल ब्याज आय को कुल औसत आस्ति से भाग करके की जाती है।

स्रोत: भारत बैंक पर्यवेक्षी विवरणी

बाजार द्वारा संचालित मॉडल है जिसके तहत बैंकों को इस बात का निर्णय स्वयं लेना होता है कि अशोध्य ऋणों को एआरसी को बेचा जाए या नहीं, जो द्विपक्षीय सौदेबाजी और/अथवा नीलामी द्वारा किया जाता है। उन्हें गैर-सरकारी साधनों के रूप में स्थापित किया गया है और वे सतत कारोबारी मॉडल के आधार पर कार्य करती हैं। भारतीय प्रणाली में एआरसी के लिए कोई समापन संबंधी खंड नहीं है।

3.15 भारत में दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बहुत विकसित बाजार नहीं है और एआरसी को पूंजी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है (चार्ट 3.3)। इसके अलावा, मौजूदा व्यवस्था में अत्यधिक छूट (चार्ट 3.4) प्रदान किए जाने से बैंकों/वित्तीय



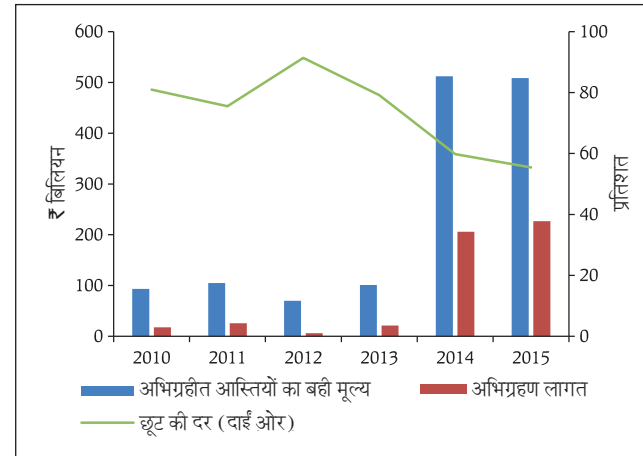
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

संस्थाओं द्वारा जिस मूल्य की अपेक्षा की जाती है और एआरसी द्वारा जो बोली लगाई जाती है उन दोनों में कोई सहमति बिंदु नहीं होता है जो नीलामियों की न्यून सफल दर से स्पष्ट है।

आईएफआरएस समरूपी लेखा मानक की ओर जाने की तैयारी

3.16 जहां बैंक अपने तुलनपत्रों के समेकन पर अत्यधिक फोकस कर रहे हैं वहीं रिजर्व बैंक इस बात की व्यापक समीक्षा कर रहा है कि बैंकों ने अपने आस्ति-पोर्टफोलियो में दबाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया है और उनसे जुड़ी प्रावधानीकरण की जरूरतें कितनी थीं। इससे बैंकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) जिसके समरूप भारतीय लेखांकन मानक (इंड, एएस) बनाया गया है, के कार्यान्वयन की तैयारी करने में सहायता मिलेगी 1 अप्रैल, 2018 से या उसके बाद की लेखा-अवधि हेतु लागू किया जाएगा। इंड एएस, विशेषतया इंड एएस 109 (आईएफआरएस 9) बैंकों द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा लेखांकन संरचना के स्थान पर लाया गया है जो एक आमूल-चूल परिवर्तन है, और यह लेखांकन मानक तथा रेगुलेटरी दिशानिर्देशों के मिश्रण पर आधारित है, विशेष रूप से कुछ खास क्षेत्रों से संबंधित दिशानिर्देश जैसे - वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण तथा उनकी माप, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार दर पर होने वाले लाभ एवं हानि का निर्धारण तथा वित्तीय आस्तियों के हासित होने से संबंधित दिशानिर्देश

चार्ट 3.4: एआरसी द्वारा अभिग्रहीत आस्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

शामिल हैं। इस बदलाव से यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय बैंकों के वित्तीय एवं परिचालनगत परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए आवश्यक है कि सावधानीपूर्वक तैयारी की जाए तथा समस्त हितधारकों पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों का परीक्षण किया जाए। जहां इस चरण में इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव को ठीक-ठीक बता पाना संभव नहीं होगा, वहीं बैंकों तथा हितधारकों को इससे पड़ने वाले कतिपय प्रमुख प्रभावों को ध्यान में रखना होगा (बॉक्स 3.3)।

बॉक्स 3.3 : भारतीय बैंकों द्वारा इंड ए एस 109 के कार्यान्वयन से पड़ने वाले कतिपय प्रमुख प्रभाव

रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आईएफआरएस के परिवर्तित रूप भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) को 1 अप्रैल, 2018 से या उसके बाद प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधि से लागू किया जाए।

प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) संबंधी क्षति मॉडल : इंड ए एस 109 क्षति मॉडल का एक उन्नत किस्म का मॉडल है जो प्रत्याशित हानियों पर आधारित है। इस मानक में यह अपेक्षित है कि संस्थाएं सतत आधार पर प्रत्याशित हानियों का मूल्यांकन करें तथा होने वाली ऋण की हानियों की पहचान शीघ्र कर लें। यह उम्मीद की गई है कि ईसीएल मॉडल को लागू करने से क्षति के लिए और अधिक प्रावधान करना होगा, जो पूंजी पर्याप्तता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और माप : इंड ए एस 109 के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण एवं माप संस्था के कारोबारी मॉडल और आस्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह की प्रकृति पर आधारित होगा और यह एक प्रकार से बैंकों द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही लेखांकन संरचना से प्रस्थान करने जैसा होगा जो इस संबंध में रेगुलेटरी

दिशानिर्देशों पर आधारित है। इंड ए एस 109 में यह जानना अपेक्षित है कि लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) आंकने के अंतर्गत वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में लाभ-हानि लेखा में उचित मूल्य लाभ कितना है। इसका परिणाम यह होगा कि बैंकों को अप्राप्त लाभ का भी पता चल जाएगा जिसकी अभी तक अनुमति नहीं थी।

अन्य बड़ी आय (ओसीआई) : मौजूदा भारतीय जीएएपी संरचना आरक्षित राशियों में से सीधे-सीधे समायोजन करने को प्रोत्साहित नहीं करती है। किंतु इंड ए एस के अंतर्गत, अनेक मदों को, विशेष रूप से कतिपय वित्तीय लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तन (एफवीओसीआई) और निवल परिभाषित लाभ दायित्व की पुनः माप को ओसीआई के माध्यम से सीधे-सीधे समायोजित किया जा सकता है।

प्रभावी ब्याज दर : इंड ए एस के अंतर्गत ब्याज आय का निर्धारण प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के आधार पर किया जाएगा जिससे कतिपय मदों का परिशोधन किया जा सकेगा जैसे - प्रोसेसिंग शुल्क, ऋण की वृद्धिशील एवं सीधी प्रोद्भूत लागतें।

(जारी...)

(समाप्त)

प्रकटीकरण : इंड ए एस में बृहत रूप से प्रकटीकरण की सुविधा है, विशेष रूप से वित्तीय लिखतों एवं उनसे जुड़े जोखिमों (इंड ए एस 107), उचित मूल्य माप (इंड ए एस 113) और समेकन से संबंधित अपेक्षाओं (इंड ए एस 110, 111 और 112) के संबंध में। बैंकों के लिए आवश्यक है कि इस व्यवस्था को लागू रखें और इस संबंध में व्यापक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास करें।

अत्यधिक वस्तुनिष्ठता और प्रबंधन का स्वविवेक : इंड ए एस एक 'सिद्धांत आधारित' संरचना है जो भारतीय बैंकों द्वारा वर्तमान में प्रयोग की जा रही काफी हद तक 'नियम आधारित' सूचना की तुलना में बेहतर प्रबंधन-निर्णय की सुविधा मुहैया कराती है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षकों की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए और भी

महत्वपूर्ण हो जाती है कि वित्तीय विवरण बैंक के कार्यों की सही और सच्ची तसवीर पेश करते हैं।

मानव संसाधन को कुशल बनाना : बैंक न केवल वित्तीय विवरण तैयार करते हैं बल्कि उसका उपयोग भी करते हैं इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उनके अधिक से अधिक स्टाफ इंड ए एस वातावरण में कार्य करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हों।

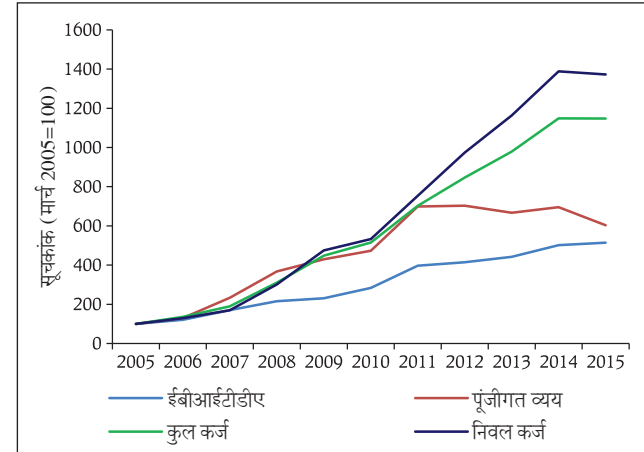
आईटी प्रणाली में बड़े पैमाने पर संशोधन : बैंकों को अपनी आईटी प्रणाली अद्यतन करने के लिए निवेश करने की जरूरत होगी ताकि वे इंड एएस की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में हों। इंड एएस 109 में खासतौर से पुराने, मौजूदा एवं भावी सूचनाओं की भी आवश्यकता होगी इसलिए इसे एक तीव्र डाटा प्रबंधन प्रणाली भी चाहिए होगी।

कारपोरेट क्षेत्र को बैंक से दिए जाने वाले उधार से संबंधित मुद्दे

3.17 जैसाकि पूर्व में चर्चा की जा चुकी है कि बैंक के समग्र ऋण पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया ऋण होता है, साथ ही इसके अधिकांश ऋण दबावग्रस्त हैं। आस्ति-गुणवत्ता का यह पहलू भारतीय कारपोरेट के बढ़ते लीवरेज के मुद्दे से संबंधित है। भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का एक वांछित अनुपात में बना रहना जहां आवश्यक है वहीं यह पाया गया है कि पूंजीगत व्यय जो बहुत तेजी से बढ़ गया था अब कर्ज में वृद्धि के बावजूद घट रहा है (चार्ट 3.5)। इस अवधि में कंपनियों की लाभप्रदता घटी है जिससे उनकी ऋण चुकाने की क्षमता में कमी आई है (चार्ट 1.20⁸, अध्याय 1 देखें)। इस प्रकार की प्रवृत्ति से यह संकेत मिलता है कि परियोजनाएं रुकी हुई हैं, प्रति यूनिट पूंजीगत व्यय से कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज में समग्र रूप में वृद्धि हो रही है तथा लगाए गए संसाधनों से कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति, बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों के तेजी से बढ़ने के कारण से संबंधित है, जिससे 'बाह्य ऋण प्रीमियम'⁹ बढ़ता जा रहा है जो सहज मौद्रिक नीति के रुझान के प्रसारण के प्रति रुकावट बन सकता है। 'औद्योगिक' क्षेत्र की यह तकलीफ दूसरों के लिए संकेत का कार्य करती है और नये निवेश को रोक देती है।

3.18 जहां कतिपय विशेष क्षेत्रों से संबंधित प्रतिकूल आर्थिक स्थितियां तथा अन्य कारक आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में मुख्य भूमिका निभा रही हैं वहीं इस संबंध में पाया गया

चार्ट 3.5: भारतीय कंपनियों के कर्ज, पूंजी व्यय और आमदनी*



टिप्पणी: *: नमूने में शीर्ष की 1000 गैर-साफ्टवेयर, गैर-वित्तीय फर्म शामिल हैं, कुल आस्तियों के अनुसार हैं, ब्लूमबर्ग द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। निवल कर्ज में कंपनियों की समग्र कर्ज की स्थिति दी गई है जो उसकी नकदी तथा अन्य समान स्वरूप की आस्तियों जैसे बेचने योग्य प्रतिभूतियों के मूल्यों से देयताओं का मूल्य घटाकर आंकी गई है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग

⁸ कंपनियों के डाटा स्रोत और नमूने जो चार्ट 1.20 में प्रयोग किए गए हैं वे चार्ट 3.5 में प्रयुक्त स्रोत एवं नमूनों से भिन्न हैं।

⁹ विश्वसनीयता में अंतर्जात परिवर्तन से कारोबारी चक्र में 'लगातार' और 'आयाम' में वृद्धि होगी : "वित्तीय त्वरित और ऋण चैनल", बेन एस. बर्नान के <http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070615a.htm> पर उपलब्ध है।

मिलता है, बैंकों को अपने आस्ति पक्ष की ओर से कम जोखिमगत होने के जरूरत है। इसके अलावा, चलनिधि अनुपात के जरिए आस्ति देयता संतुलन की अपेक्षाएं बैंकों की 'परिपक्वता परिवर्तन' हेतु उनकी क्षमता को आगे और बाधित करती हैं।

3.22 ऐसी परियोजनाओं को दिए गए ऋण, जो कार्यान्वयन के अधीन हैं और जिनकी आस्ति गुणवत्ता उनके द्वारा वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख की प्राप्ति से (डीसीसीओ) से जुड़ी हुई है, उनको लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है, परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली जटिलताओं और साथ ही किसी परियोजना के डीसीसीओ को प्रभावित करने वाले कई सारे बाहरी कारकों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने परियोजना ऋण के लिए डीसीसीओ की प्राप्ति के संबंध में कुछ रियायतें दी हैं। परियोजना ऋणों के संबंध में संरचनागत वित्तपोषण के तहत, बैंकों को अनुमति दी गई कि वे परिशोधन शेड्यूल के साथ संरचनात्मक दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करें जो उनके आर्थिक जीवन से जुड़ा हो और यह भी अनुमति दी गई कि वे इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख उद्योग क्षेत्र में परियोजनाओं को आवधिक पुनर्वित्त विकल्प उपलब्ध कराएं। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई कि वे अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ किसी भी पूर्व निर्धारित करार के बगैर भी अंतरण वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनेंसिंग) के जरिए अपने मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं।

3.23 यद्यपि विनियामकीय और साथ-ही-साथ 'अंतरण-वित्त पोषण' से जुड़े ऐसे कदमों और बैंकों को उनकी परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए उनके द्वारा दीर्घावधि बॉण्ड लेने की खातिर विनियमों को सक्षम बनाने से कुछ चिंताओं को दूर करने की कोशिश हुई है, तथापि ऋण की अवधि के कारण जोखिम के मद्देनजर बैंक की प्रक्रियागत क्रियाविधि और कारोबारी मॉडल अभी भी दीर्घावधि परियोजना ऋण देने, उनकी निगरानी और प्रबंधन करने में पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में पेंशन निधियों और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिनके पास दीर्घावधि निवेश योग्य संसाधन हैं (पैरा 3.45 देखें)।¹²

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को दूर करना

3.24 जैसाकि पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में चर्चा की गई थी, एक ओर जहां सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई कारणों, जिसमें विरासत से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, से वे कार्यानिष्पादन और कार्यक्षमता के संकेतकों में निजी क्षेत्र के अपने समकक्षों से पिछड़ते आ रहे हैं। वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र के बैंक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में काफी प्रमुखता से अधिक भागीदारी के साथ ही अपनी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में उच्चतम दबाव झेलते हुए देखे जा रहे हैं। अपने विकासात्मक उद्देश्यों के बावजूद, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में, व्यवहार्य बने रहने के लिए वाणिज्यिक लाभों पर परिचालन करने की आवश्यकता है।

सरकार की 'इन्द्रधनुष' पहल के तहत सुधार

3.25 अगस्त 2015, में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यानिष्पादन में सुधार को ध्येय बनाते हुए एक सात-सूत्रीय योजना (नाम 'इन्द्रधनुष'¹³) की शुरुआत की। इस सुधार योजना के तहत प्रयासों में कई पहलू शामिल हैं जैसे (i) सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों में प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अलग-अलग नियुक्ति, (ii) एक बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का प्रस्ताव, (iii) पूंजीकरण की योजना (वित्तीय वर्ष 2018-19¹⁴ तक चार वर्षों के लिए बजट आबंटन से ₹700 बिलियन) (iv) बैंक बहियों में दबाव कम करने की योजना (v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार के हस्तक्षेप के बगैर स्वतंत्र रूप से कारोबारी निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित करते हुए उनका सशक्तीकरण (vi) जवाबदेही के संबंध में एक नया फ्रेमवर्क जो महत्वपूर्ण कार्यानिष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित हो और (viii) बैंकों की सतत भागीदारी के साथ बेहतर गवर्नेंस। जैसाकि इन सुधारों में परिकल्पना की गई है और जब सरकार भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक बड़े परोक्ष शेयरधारक के रूप में बने रहना चाहती है, उनसे अपेक्षा है कि वे अपनी कारोबारी रणनीति, परिचालन, नियंत्रण और वित्तीय लक्ष्य में 'निजी' संस्थाओं की तरह कार्य करें। इसलिए, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कारोबारी मॉडल, उनकी पूंजीगत संरचना, लाभांश नीति और वित्तीय समावेशन के उनके प्रयासों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

¹² अभी हाल ही में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा भारतीय रेलवे को दिया गया रु. 1.5 ट्रिलियन का दीर्घावधि ऋण और रिजर्व बैंक द्वारा एनआरआई को राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने की अनुमति देना इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

¹³ 'इन्द्रधनुष' रेन्बो का हिंदी नाम है। विवरण financialservices.gov.in/Pressnote/Indardhanush.pdf पर उपलब्ध है।

¹⁴ उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अनुमानित रु. 1.8 ट्रिलियन की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता में से रु.1.1 ट्रिलियन की राशि बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से जुटाना अपेक्षित है।

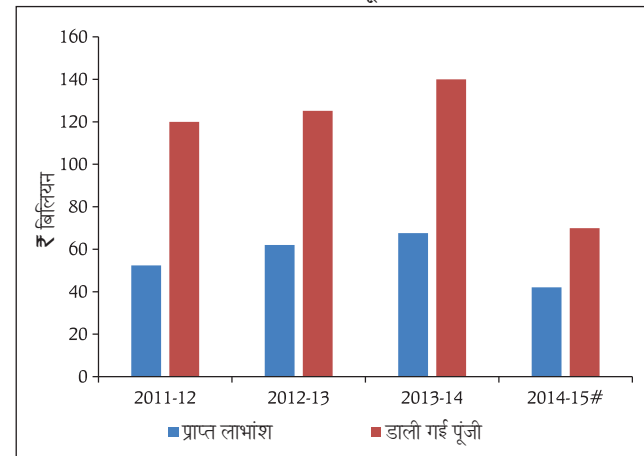
निर्देशित उधार और वित्तीय समावेशन के प्रयास

3.26 निर्देशित उधार में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सब्सिडी शामिल है और इस प्रकार की लागत का वहन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम बैंकिंग प्रथाओं और उधार संबंधी अनुशासन से समझौता न करना पड़े। लोकोपयोगी निकायों को दिए गए ऋणों (उदाहरण के लिए 'डिस्कॉम्स') का अंततः अर्द्ध-राजकोषीय प्रभाव होता है और यह महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी का प्रयोग करते समय उधार मानदंडों को किसी प्रकार प्रभावित किए बगैर अलग से प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करने की आदत को आत्मसात किया जाए। दूसरी ओर, 'वित्तीय समावेशन' की नीति को इस प्रकार क्रिसान्वित करने की आवश्यकता है कि यह स्थापित वाणिज्य बैंक प्रथाओं के लिए अहितकर न हो। यदि वित्तीय समावेशन को एक बिन्दु से आगे ले जाया जाता है तो इससे प्रणाली में ऋणात्मक लागत की स्थिति पैदा हो सकती है। चूंकि गवर्नेंस और परिचालन संबंधी सुधार पर प्रगति साकार हो रही है, इसलिए निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यसंस्कृति और कार्यनिष्पादन के बीच के अंतर के कम होने की आशा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक बड़े भौगोलिक और जनसांख्यिकीय भूभाग में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराने संबंधी पहुंच और अनुभव की उनकी अंतर्निहित ताकत का यदि उपयोग किया जाना है, तो उनके प्रयासों के लिए उचित रूप से वाणिज्यिक लाभों के आधार पर उन्हें क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालना और लाभांश निर्णय

3.27 यह पाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार और अन्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में काफी राशि देते हैं (चार्ट 3.8) जिसका उनकी बैलेंस शीट की मजबूती तथा पूंजी योजना से कोई सरोकार नहीं है। यह एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन की स्थिति को भी उजागर करता है जिसे बेहतर बैंकों द्वारा किया जाता है (उनके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अदायगी की जाती है परंतु सरकार द्वारा कमजोर बैंकों में असंगत रूप से अधिक पूंजी डालनी पड़ती है)। लाभांश अदायगी का यह पैटर्न लाभांश असंगति सिद्धांत¹⁵ के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक लाभांश के निर्णय को एक रणनीतिक कारोबारी निर्णय के रूप में लें और अपने शेयरधारकों की संपत्ति को उच्चतम सीमा तक ले जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखें।

चार्ट 3.8: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सरकार को प्राप्त लाभांश और उनके द्वारा बैंकों में पूंजी डालना



टिप्पणी #: 2014-15 के लिए डाली गई पूंजी के आंकड़े कुल बजट आबंटन पर आधारित हैं। 2014-15 के लिए सरकार द्वारा प्राप्त किए गए लाभांश की राशि की गणना संबंधित बैंक द्वारा लाभांश की अदायगी और पूंजी में सरकार की भागीदारी के आधार पर की गई है।

स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैसाकि इंडिस्टैट को दिया गया।

(www.indiastat.com)

¹⁵ वैसे तो, सरकार को अदा किए गए लाभांश का एक भाग का पूंजी डालने पर पुनः वापस आ जाता है, फिर भी अदायगी का काफी बड़ा हिस्सा सार्वजनिक शेयरधारकों को भी जाता है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन योजना: अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान हुई प्रगति

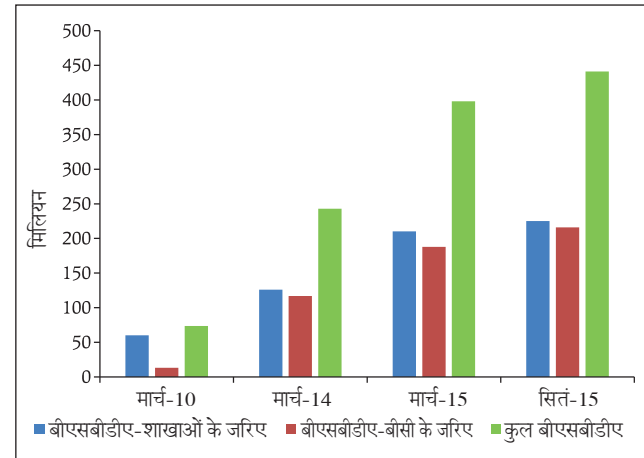
3.28 बैंकों द्वारा उनके बोर्ड से उचित अनुमोदन के बाद प्रस्तुत की गई वित्तीय समावेशन योजना बैंकों की कारोबारी रणनीति का हिस्सा है। व्यापक वित्तीय समावेशन योजना में विभिन्न मापदण्डों के आधार पर हुई प्रगति से संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं जिसमें बेसिक बचत बैंक खाता (बीएसबीडीए), लघु क्रेडिट, और कारोबारी प्रतिनिधि - सूचना और संचार टेक्नॉलजी (बीसी-आईसीटी) लेनदेन से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किए गए प्रयासों के मद्देनजर बीएसबीडीए खाता खोलने में काफी अधिक वृद्धि हुई। मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में बीएसबीडीए 398 मिलियन था जो सितंबर 2015 को समाप्त अवधि में 441 मिलियन तक पहुंच गया (चार्ट 3.9)।

3.29 मार्च 2015 के अंत तक बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या 553,713 थी जो सितंबर 2015 के अंत में बढ़कर 567,530 हो गई (517,328 शाखा रहित मोड और 50,202 शाखा सहित)। मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में बीएसबीडीए में 477 मिलियन बीसी-आईसीटी लेनदेन हुए थे जबकि अप्रैल 2015-सितंबर 2015 के दौरान 359 मिलियन लेनदेन के साथ इसमें स्थिर वृद्धि देखी गई। कीमत के रूप में, बीसी-आईसीटी लेनदेन 2013-14 के रु. 524 बिलियन से बढ़कर 2014-15 के दौरान रु. 859 बिलियन हो गए। 2015-16 की पहली छमाही के दौरान रु. 688 बिलियन कीमत के बीसी-आईसीटी लेनदेन हुए (चार्ट 3.10)। लघु कृषि क्षेत्र में उद्यमिता कर्ज कुल 42 मिलियन खातों में ₹4,860 बिलियन शेष के साथ बकाया था। गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमिता गतिविधियों में लघु कर्ज कुल 11 मिलियन खातों में ₹1,390 बिलियन शेष के साथ बकाया था।

बैंकिंग क्षेत्र में नए खिलाड़ी - वित्तीय समावेशन को बल

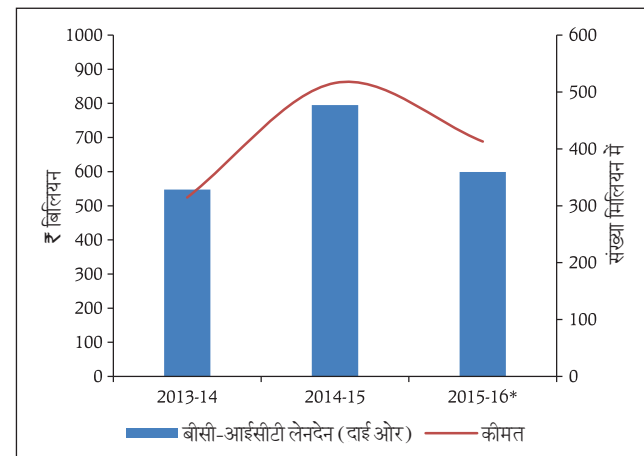
3.30 रिजर्व बैंक ने 11 भुगतान बैंक और 10 लघु वित्तीय बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।¹⁶ इन 21 आवेदनों में सात प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (पीपीआई), नौ

चार्ट 3.9: बीएसबीडीए खातों में रुझान



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 3.10: बीसी-आईसीटी लेनदेन और कीमत संबंधी रुझान



* सितंबर 2015 तक
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

¹⁶ भारिबैं (2015), प्रेस विज्ञप्ति, अगस्त और सितंबर https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=34754 और https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35010 पर उपलब्ध है।

बॉक्स 3.4: भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक

भुगतान बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय वाले हाउसहोल्ड, छोटे कारोबारियों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य प्रयोक्ताओं को एक सुरक्षित टेक्नॉलजी चालित वातावरण में जमा और भुगतान/विप्रेषण सेवाओं में उच्च मात्रा-निम्न मूल्य लेनदेन को सक्षम बनाते हुए उन्हें लघु बचत खाता और भुगतान/विप्रेषण सेवाएं उपलब्ध कराना है। भुगतान बैंकों को उधार देने के कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं दी गई है और शुरुआत में उन्हें प्रति वैयक्तिक ग्राहक ₹100,000 अधिकतम बैलेंस रखने की सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के रूप में आउटसाइड मांग और मीयादी देयताओं पर राशि बनाए रखे जाने के अलावा, इन बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी ठामांग जमाशेष ड का न्यूनतम 75 प्रतिशत एक वर्ष परिपक्वता अवधि वाली ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करें जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर रखे जाने के प्रयोजन से पात्र प्रतिभूतियों के रूप में चिन्हित किया गया है और अपने परिचालनिक प्रयोजन तथा चलनिधि प्रबंधन के उद्देश्य से अधिकतम 25 प्रतिशत अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की चालू और सावधि/मीयादी जमाराशियों में धारित करें। 11 आवेदकों, जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन मिला है, से उनके परिचालन के पहले वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में

1,140 बैंक शाखाओं के अलावा ₹16.22 बिलियन नई पूंजी लाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने का उद्देश्य (i) मुख्य रूप से आबादी के ऐसे भाग को जो अभी तक बचत सुविधाएं से वंचित या अपात्र हैं, उन्हें बचत के साधन मुहैया करवाकर, (ii) छोटे कारोबारी इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को उच्च टेक्नॉलजी-निम्न परिचालन लागत के जरिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध करवाकर वित्तीय समावेशन के मुद्दों को आगे और बढ़ाना है। लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत है और ऋण संविभाग के कम से कम 50 प्रतिशत में ₹2.5 मिलियन तक के उधार और अग्रिम होने चाहिए। 10 आवेदकों, जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन मिला है, से उनके परिचालन के पहले वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में 2,444 बैंक शाखाओं के अलावा ₹57.34 बिलियन की नई पूंजी आने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को परखने और अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है। वर्तमान में यह दल इन बैंकों के आकार और दायरे से जुड़े ऐसे मुद्दों की जांच कर रहा है जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एक स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) शामिल हैं (बॉक्स 3.4)। इन नई प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं के प्रवेश से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आने की और बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, इन अलग प्रकार के नए बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यम-अवधि (पांच-वर्ष) की सुस्पष्ट कार्रवाई योजना तैयार करने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर एक मध्यम अवधि का रास्ता लेते हुए एक समिति गठित की है।¹⁷

प्रतिभूति बाजार

विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक की तुलना में घरेलू संस्थागत निवेशक

3.31 यद्यपि विदेशी पोर्टफोलिओ निवेश (एफपीआई) के प्रवाह से भारतीय इक्विटी बाजार में चलनिधि की स्थिति और बाजार की पैठ सुधरने में मदद मिली है, तथापि इन प्रवाहों से अक्सर भेड़चाल की स्थिति उत्पन्न होने की चिंता और बाह्य कारकों द्वारा

चालित अत्यधिक अस्थिरता के आवेग की चिंता बनी रहती है। वर्ष 2014-15 की पहली छमाही में भारतीय इक्विटी बाजार में एफपीआई द्वारा निवल निवेश में एक जबर्दस्त रुझान देखा गया - इक्विटी में एफपीआई निवेश ₹610 बिलियन था, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने ₹126.10 बिलियन की निवल बिकवाली की थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों में म्यूच्युअल फंड अपवाद रहे क्योंकि उनका निवल निवेश ₹156.25 बिलियन था, जबकि इसी अवधि में अन्य घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे बैंक, बीमा कंपनियां और घरेलू वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) निवल बिकवाल रहे थे। तथापि 2015-16 की पहली छमाही के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी में लगभग ₹600 बिलियन का निवेश किया था, जिसमें से ₹450 बिलियन का निवेश म्यूच्युअल फंडों द्वारा किया गया था। घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीद प्रवृत्ति से प्रतीत होता है कि एक ऐसे बाजार में, जब इक्विटी में एफपीआई की ओर से ₹152 बिलियन का निवल बहिर्वाह देखा गया हो, तब उसी अवधि में इंडेक्स मूल्य में तेज उतार-चढ़ाव को प्रतिरोध मिल रहा है।

¹⁷ अध्यक्ष, श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक।

3.32 2014-15 के दौरान, इक्विटी में घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश का मासिक रुझान मोटे तौर पर ऋणात्मक रहा था और 12 में से 8 महीनों के लिए ये रुझान एफपीआई की ट्रेडिंग रणनीति का बराबर बल के साथ प्रतिकार कर रहे थे। तथापि, म्यूच्युअल फंडों द्वारा जून 2014 की शुरुआत से ही इक्विटी में सतत निवल निवेश देखा गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल निवेश और एफपीआई द्वारा 6 में से 4 महीने के दौरान बहिर्वाह के चलते घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से काफी अधिक निवेश देखा गया। (चार्ट 3.11)

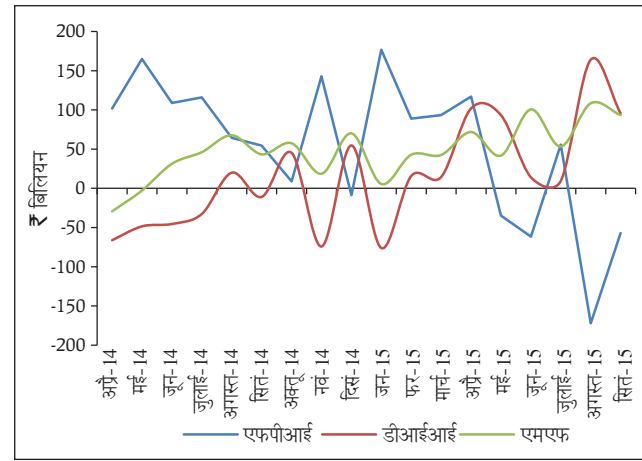
3.33 इक्विटी निवेश के संबंध में दो तुलनात्मक अवधियों (2014-15 और 2015-16 की पहली छमाही) के लिए दिन-वार आंकड़ों के एक विश्लेषण से मालूम होता है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी खरीदी में तेजी लाई है और ऐसे दिनों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से काफी वृद्धि हुई है जब वे निवल खरीददार थे, जबकि उसी समय एफपीआई निवल बिकवाली कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि घरेलू संस्थागत निवेशकों में से म्यूच्युअल फंड ने इक्विटी में अपने व्यापक निवेश के साथ ही एक ऐसे बड़े प्रतिकारी बल के रूप में काम किया जिससे भारतीय इक्विटी में एफपीआई द्वारा निवल बिकवाली की स्थिति बराबर हो गई (चार्ट 3.12)।

कॉर्पोरेट बॉण्डों में म्यूच्युअल फंड का निवेश

3.34 हाल ही में कुछ कॉर्पोरेट बॉण्डों की रेटिंग डाउनग्रेड होने और परिणामस्वरूप कुछ म्यूच्युअल फंडों द्वारा मोचन पर कुछ प्रतिबंध लगाने के साथ ही कॉर्पोरेट बॉण्डों में म्यूच्युअल फंड के एक्सपोजर की सीमा को लेकर चिंताएं प्रमुखता से सामने आई हैं। क्रेडिट जोखिम के अलावा, अन्य संबंधित पहलुओं जैसे चलनिधि जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और निवेशकों की जागरूकता का स्तर भी केंद्रबिन्दु में रहा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अक्टूबर 2015 में भी म्यूच्युअल फंडों और अन्य संस्थागत निवेशों द्वारा बड़ी मात्रा में कॉर्पोरेट बॉण्ड धारित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में चलनिधि और संकेंद्रण जोखिम पर बाजार संरचना के परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव पर चर्चा हुई है और साथ ही बॉण्ड बाजार में लघु बॉण्ड निर्गमों के विस्तार से चलनिधि पर होनेवाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर भी चर्चा हुई है।

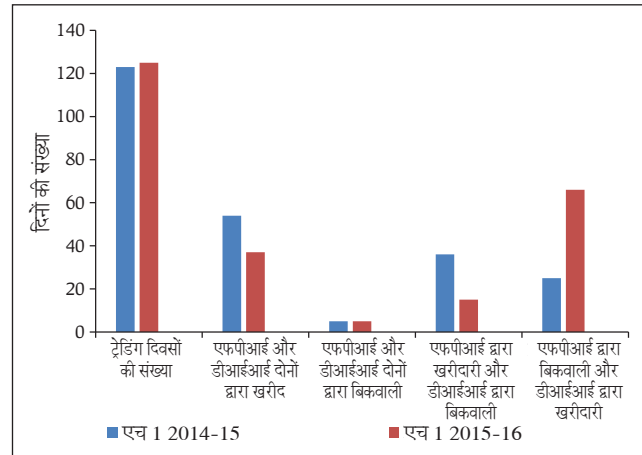
3.35 भारत में म्यूच्युअल फंड द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्डों में एक्सपोजर और विशेषकर ऐसे कॉर्पोरेट बॉण्डों में एक्सपोजर जिन्हें पिछले छः महीनों में डाउनग्रेड किया गया है, के विश्लेषण से मालूम होता है कि 'कर्ज उन्मुख योजनाओं' की प्रबंधनाधीन आस्तियां

चार्ट 3.11: डीआईआई और एफपीआई द्वारा इक्विटी में निवल निवेश



स्रोत: सेबी

चार्ट 3.12: अप्रैल-सितंबर 2014 और 2015 के दौरान एफपीआई और डीआईआई की खरीदारी/बिकवाली रुझानों का दैनिक-वार ब्रेकअप



स्रोत: सेबी

(एयूएम) म्यूचुअल फंड उद्योग के कुल एयूएम के 64 प्रतिशत के करीब हैं - जिसमें से 39 प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉण्डों में निवेशित हैं। तथापि, ऐसे म्यूचुअल फंडों का भाग छोटा है जिनका कॉर्पोरेट बॉण्ड में एक्सपोजर औसत स्तर से अधिक है (सारणी 3.1)।

3.36 कर्ज उन्मुख भारतीय म्यूचुअल फंडों के संदर्भ में, कर्ज उन्मुख योजनाओं के एयूएम का ऐसे कॉर्पोरेट बॉण्डों में एक्सपोजर जिन्हें पिछले छः महीने में डाउनग्रेड किया गया है, 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार उनके कुल एयूएम का महज लगभग 1.6 प्रतिशत ही है। डाउनग्रेडेड बॉण्ड में एक्सपोजर के भाग का उच्चतम स्तर लगभग 9 प्रतिशत है और यह एक आस्ति प्रबंध कंपनी के मामले में है, जबकि शेष आस्ति प्रबंध कंपनियों के मामलों में डाउनग्रेडेड बॉण्डों में उनके कर्ज उन्मुख फंडों का एक्सपोजर 1 से 3 प्रतिशत के दायरे में था। इस प्रकार, ऐसे एक्सपोजर के प्रणालीगत रूप से परिणामी होने की आशा नहीं है, जब तक कि क्रेडिट की दरें डाउनग्रेड न हो जाएं या कॉर्पोरेट चूक की दरें अचानक से न बढ़ जाएं।

म्यूचुअल फंडों में उत्पाद नामकरण

3.37 उत्पाद नामकरण पर सेबी के ढांचे का उद्देश्य यह है कि गलत-तरीके से बिक्री के मुद्दे का निदान किया जा सके और निवेशकों को इस प्रकार की समझ प्रदान की जा सके कि वे किस प्रकार के उत्पाद/योजना में निवेश कर रहे हैं और यह उनके लिए कितनी उचित है। तदनुसार, म्यूचुअल फंडों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपनी योजनाओं का उसकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुरूप जैसे मानदंडों (संपत्ति निर्माण/ नियमित आय; ऋण/ईक्विटी अथवा हाईब्रिड) और सांकेतिक समयावधि (अल्प/मध्यम/दीर्घावधि) के आधार पर नामकरण करें। जोखिम का स्तर दर्शाने के लिए यह अपेक्षित कि उन्हें रंगीन कूट चौकरों (नीला जहां मूलधन पर जोखिम कम है, पीला जहां मध्यम दर्जे का जोखिम है और उच्च जोखिम को भूरे रंग) के माध्यम से दर्शाया जाए। म्यूचुअल फंडों द्वारा उत्पाद के नामकरण के ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अप्रैल 2015 में सेबी ने म्यूचुअल फंडों के नामकरण के लिए जोखिम श्रेणियों को बढ़ाकर पांच कर दिया, इसमें 'सीमित रूप से कम' और

सारणी 3.1: अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्डों में म्यूचुअल फंडों का एक्सपोजर

(राशि ₹ बिलियन में)

म्यूचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम)	12331.97
डेट उन्मुख योजनाओं की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम)	7929.10
कुल एयूएम में डेट उन्मुख योजनाओं के एयूएम का प्रतिशत	64
कॉर्पोरेट बॉण्डों में डेट उन्मुख योजनाओं का कुल एक्सपोजर	3124.82
डेट उन्मुख योजनाओं के एयूएम में डेट उन्मुख योजनाओं के कॉर्पोरेट बॉण्ड में एक्सपोजर का प्रतिशत	39
डाउनग्रेडेड कॉर्पोरेट बॉण्डों में डेट उन्मुख फंडों का एक्सपोजर (ऐसे कॉर्पोरेट बॉण्डों में डेट उन्मुख फंडों की निवेशित आस्ति का मूल्य जिन्हें उक्त अवधि के दौरान डाउनग्रेड किया गया है)	128.17
डेट उन्मुख योजनाओं के कुल एयूएम में डाउनग्रेडेड कॉर्पोरेट बॉण्डों का प्रतिशत	1.62

स्रोत: सेबी

'सीमित रूप से उच्च' नामकरणों को जोड़ा गया है। इसके अलावा, 01 जुलाई 2015 से, रंग कूटों का उपयोग करते हुए जोखिम दर्शाए जाने को चित्रांकन मीटर द्वारा बदल दिया गया है जिसे 'रिस्कोमीटर' नाम दिया गया है क्योंकि जोखिम के दृश्य संकेतक संदेश प्रदान करने में कहीं अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं और ये सरल तथा स्वयं सपष्ट भी होते हैं जिन्हें निवेशक आसानी से समझ सकता है¹⁸।

नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा

3.38 2003 में जबसे आधुनिक डी-म्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंजों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों को प्रारंभ किया गया है तब से भारत में कमोडिटी डेरीवेटिव बाजार में तीव्र संवृद्धि देखी गई है। भारत में कामोडिटी बाजारों को मजबूत बनाने में सामने आने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों का पिछली एफएसआर में उल्लेख किया गया था, इसका कारण 'स्पाट' बाजारों में बिखराव और अन्य विधिक तथा कराधान संबंधी पहलू थे। 2015-16 के केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद वायदा व्यापार आयोग (एफएमसी), जो कि भारत में कमोडिटी डेरीवेटिव का पूर्ववर्ती विनियामक था, का 28 सितंबर 2015 को सेबी के साथ विलय कर दिया गया। इस विलय के पश्चात् सेबी ने जोखिम प्रबंधन ढांचे¹⁹ पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए ताकि भारत में मौजूद सभी नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंजों में जोखिम प्रबंधन ढांचे में एकरूपता लाई जा सके और उसे युक्तिसंगत बनाया जा सके। इस ढांचे को अधिकतम 01 जनवरी

¹⁸ सेबी (2015ए), प्रोडक्ट लेबलिंग इन म्यूचुअल फंड्स', परिपत्र, अप्रैल, http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1430388883147.pdf पर उपलब्ध

¹⁹ सेबी (2015बी), राष्ट्रीय कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज के लिए विस्तृत जोखिम प्रबंधन ढांचा', परिपत्र, अक्टूबर http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1443700933819.pdf पर उपलब्ध

2016 तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा। सेबी ने क्षेत्रीय कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंजों²⁰ के लिए भी जोखिम प्रबंधन मानदंड निर्धारित कर दिए हैं जिन्हें अप्रैल 01, 2016 से लागू किया जाना है।

नए छोटे उद्यमों (स्टार्ट-अप्स) द्वारा निधि जुटाने के लिए सेबी का ढांचा

3.39 हाल के वर्षों में भारत में प्रौद्योगिकी आधारित नए छोटे उद्यमों (स्टार्ट-अप्स) की स्थापना में तीव्र संवृद्धि देखी गई है और यह वैश्विक स्टार्ट-अप आर्थिक-प्रणालियों वाले शीर्ष देशों में शुमार है। इनमें से अधिकतर नए छोटे उद्यमों के नवोन्मेषी व्यापारिक मॉडल हैं और उन्हें आरंभिक वर्षों में भारी मात्रा में जोखिमपूर्ण पूंजी की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के आधार पर उनके मूल्यांकन के मॉडल में विभिन्नता होती है, उन्हें विशिष्ट संस्थागत निवेशकों द्वारा विश्लेषित किया जाता है और उनकी जोखिम-प्रतिफल प्रोफाइल को सामान्य निवेशकों द्वारा समझ पाना आसान नहीं होता है। निधियां जुटाने के लिए इन कंपनियों पर लगी सीमाओं के कारण वे विदेशी पूंजी बाजार की ओर झुकते हैं। अतः, छोटे नए उद्यमों के लिए घरेलू स्रोतों से निधियां

जुटाने हेतु सरलीकृत विनियामकीय व्यवस्था सहित उन्हें उचित प्रकार से प्रोत्साहित करना एक चुनौती है क्योंकि छोटे निवेशक का असफल होने के संभावित उच्चतर जोखिम से बचाव भी करना है क्योंकि इनमें उन कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक जोखिम होता है जो कि पहले ही काफी बड़ी हो चुकी है और संदर्भ देखने के लिए पर्याप्त रूप से उनका लंबा ट्रैक रिकार्ड उपलब्ध होता है।

3.40 तदनुसार, सेबी ने 15 अगस्त 2015 से प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप्स और अन्य कंपनियों द्वारा संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आईटीपी) पर निधियां जुटाने के लिए ढांचे को सरल बनाया है। यह ढांचा, पात्रता शर्तों, पूंजी का गठन, प्रकटन, संस्थागत निवेशकों को निधियों का आवंटन और विवेकाधीन आवंटन का निर्धारण करता है (बॉक्स 3.5)।

नकदी निधि और मुद्रा बाजार म्यूचुअल निधि योजनाएं का दबाव परीक्षण

3.41 नकदी/मुद्रा बाजार म्यूचुअल निधियां (एमएमएमएफ) के सामने विविध प्रकार के जोखिम होते हैं जैसे अल्पावधि ब्याज

बॉक्स 3.5: स्टार्ट-अप्स द्वारा निधि जुटाने के लिए सेबी का ढांचा

संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आईटीपी) उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, डेटा विश्लेषण, जीव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी का काफी गहन उपयोग करते हुए उत्पादों, सेवाओं या व्यापारिक प्लेटफार्म विशेष रूप से मूल्य योजित रूप में मुहैया कराती हैं और उनमें निर्गम-पूर्व पूंजी का कम से कम 25 प्रतिशत पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के पास हो या किसी अन्य ऐसी कंपनी द्वारा रखा गया हो जिसमें निर्गम-पूर्व पूंजी का कम से कम 50 प्रतिशत पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के पास हो।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की कंपनी में कोई भी व्यक्ति (व्यक्तिगत या एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों सामूहिक रूप से) निर्गम-पश्चात शेयर पूंजी का 25 प्रतिशत या उससे अधिक भाग अपने पास नहीं रख सकता है।

केवल दो श्रेणी के निवेशक अर्थात् (i) संस्थागत निवेशक (पारिवारिक न्यासों सहित क्यूआईबी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी और सेबी के पंजीकृत मध्यवर्ती संस्थाएं, इन सभी की निवल मालियत रु. 5 बिलियन से अधिक होनी चाहिए) और (ii) खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के अतिरिक्त गैर-संस्थागत निवेशक आईटीपी तक पहुंच सकते हैं।

कंपनियों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन में निर्गम के केवल व्यापक

उद्देश्य ही निहित होंगे और "सामान्य" कारपोरेट उद्देश्यों" के लिए जुटाई जानी वाली रकम पर कोई बंदिश नहीं होगी। निर्गमकर्ता निर्गम मूल्य के आधार पर जैसा कि उचित हो, प्रकटन के मानदंड निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि मूल्य-आय अनुपात (पी/ई) और प्रति शेयर कमाई (ईपीएस) जैसे मूल्यांकन के मानक पैमाने इस प्रकार की कई कंपनियों के संबंध में संगत नहीं हैं। सरकारी पेशकश करने के मामले में, संस्थागत निवेशकों को विवेकाधिकार के आधार पर आवंटन किया जा सकता है जबकि एनआईआई को इसे समानुपातिक आधार पर करना होगा। इन दोनों श्रेणियों के बीच आवंटन का अनुपात क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत होगा। संस्थागत निवेशकों को विवेकाधीन आवंटन करने के मामले में किसी भी संस्थागत निवेशक को निर्गम के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक का आवंटन नहीं किया जाएगा। विवेकाधार पर आवंटित सभी शेयरों को बंधन में रखा जाएगा, जोकि एंकर निवेशकों द्वारा बंधन के लागू अपेक्षाओं के अनुरूप होगा अर्थात् वर्तमान में 30 दिन। इस प्रकार के निर्गमों के मामलों में आवेदन का न्यूनतम आकार और न्यूनतम ट्रेडिंग लॉट रु. 1 मिलियन होगा। सरकारी पेशकश के मामले में आवंटियों की संख्या अनिवार्यतः 200 से अधिक होगी। कंपनी के पास यह विकल्प दिया गया है कि वे मुख्य बोर्ड की ओर प्रवास कर लें बर्शते कि वे स्टॉक एक्सचेंज की पात्रता अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

²⁰ सेबी (2015सी), क्षेत्रीय कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज के लिए जोखिम प्रबंधन', परिपत्र, अक्टूबर http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1445422330733.pdf पर उपलब्ध

दर जोखिम, चलनिधि जोखिम और क्रेडिट जोखिम। 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, नकदी/एमएमएमएफ की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) ₹1,785 बिलियन थीं जो कि कुल एयूएम का लगभग 15 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ), ने मुद्रा बाजार निधियों के लिए नीतिगत सिफारिशों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में 15 मुख्य सिफारिशों की हैं जो आठ क्षेत्रों में सुधार से संबंधित हैं। प्रभावी रूप से चलनिधि के प्रबंधन के लिए विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर एमएमएमएफ योजनाओं के पोर्टफोलियो का आवधिक दबाव परीक्षण करने की सिफारिश की गई है।

3.42 वैश्विक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सेबी ने अप्रैल 2015 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें एएमसी (आस्ति प्रबंधन कंपनियों) से यह अपेक्षा की गई थी कि वे दबाव परीक्षण नीति की व्यवस्था करें जो इस बात को अनिवार्य बनाती है कि एएमसी द्वारा आवश्यक समझे गए जोखिम मानदंडों, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम और चलनिधि/ मोचन जोखिम सहित, के संदर्भ में सभी नकदी निधियों और एमएमएमएफ योजनाओं के संबंध में दबाव परीक्षण किया जाए ताकि योजना पर एवं उसकी निवल आस्ति कीमत (एनएवी) पड़ने वाले उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार का दबाव परीक्षण आंतरिक रूप से कम से कम मासिक आधार पर किया जाना चाहिए और यदि बाजार की अपेक्षा है तो एएमसी को और त्वरित रूप से दबाव परीक्षण करना चाहिए।

3.43 दबाव- परीक्षण यदि किसी प्रकार की कमजोरियों या पूर्व सूचना की ओर इंगित करता है तो एएमसी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वो इसे "न्यासियों" की निगाह में लाएं और यथावश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करें ताकि उनकी सुदृढ़ता को पुनः संस्थापित किया जा सके। प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभावी रूप से समाना करने के लिए प्रत्येक एएमसी के पास लिखित दिशानिर्देश होने ही चाहिए। बदलती हुई बाजार परिस्थितियों को देखते हुए दबाव-परीक्षण नीति की समीक्षा कम-से-कम वार्षिक आधार पर एएमसी के बोर्ड और "न्यासियों" द्वारा होनी चाहिए और न्यासियों के लिए यह अपेक्षित है कि समाना की गई प्रतिकूल परिस्थितियों, यदि कोई हों, और उस दिशा में उठाए गए कदमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सेबी को न्यासी की अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। इस व्यवस्था से निधि प्रबंधक मौजूदा और संभावनाओं पर आधारित बाजार स्थितियों के आधार पर अपने पोर्टफोलियो पर लगातार नजर रख सकेंगे और उसमें सुधार ला सकेंगे एवं वे अपने पोर्टफोलियो का निर्माण इस प्रकार सकेंगे कि वे तीव्र दबाव को भी सह सकें और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

3.44 म्यूचुअल फंड्स की एक दबाव-परीक्षण नीति होती है और वे अपनी चल/एमएमएमएफ योजनाओं के संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप माह में कम से कम एक बार दबाव परीक्षण करते हैं। अधिकतर म्यूचुअल फंडों के मामले में म्यूचुअल फंडों द्वारा पूर्व में किए गए दबाव परीक्षण ने केवल एक म्यूचुअल फंड को छोड़कर, किसी भी फंड ने किसी प्रकार की कोई कमजोरी उजागर नहीं की; जबकि विशिष्ट प्रकार के दबाव परीक्षण द्वारा कमजोरियां उजागर करने के परिदृश्य में संबंधित म्यूचुअल फंडों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाइयां की गईं।

बीमा क्षेत्र

वित्तीय स्थिरता के स्रोत के रूप में बीमा कंपनियों की भूमिका

3.45 बीमा के व्यापारिक मॉडल में बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता दोनों आते हैं और इसके कुछ विशेषताएं हैं जो इसे बैंकिंग प्रणाली से भिन्न तथा वित्तीय प्रणाली में स्थिरता का स्रोत बनाती हैं। बीमा का वित्तपोषण अग्रिम में दिए गए प्रीमियम से किया जाता है, जो बीमाकर्ताओं को सुदृढ़ परिचालन नकदी प्रवाह प्रदान करता है। दूसरी ओर, बीमा पॉलिसियां विशेष रूप से जीवन बीमा पॉलिसियां सामान्य रूप से दीर्घावधि लिखतें होती हैं जिनमें बहिर्वाह नियंत्रित होता है। इस प्रकार, "उत्पादन के उल्टे चक्र" के साथ और प्रीमियम अंतर्वाह के जरिए स्वतः निधीयन होने से यह क्षेत्र पूंजी के एक दीर्घावधिकस्रोत के रूप में कार्य करता है और सकारात्मक चलनिधि चक्र में अपना योगदान देता है। बीमाकर्ताओं का यह उद्देश्य होता है कि वे आस्तियों और देयताओं की अवधियों को एक समान रखें और इसके परिणामस्वरूप वे दीर्घावधि देयताओं के प्रति दीर्घावधि आस्तियों को अपने पास रखते हैं और साथ ही वे अल्पावधि देयताओं द्वारा अपनी आस्तियों के आधार पर लीवरेज नहीं लेते हैं (कृपया पैरा 3.23 देखें)।

3.46 बीमा कंपनियों और बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों में मूलभूत अंतर है। बीमा संबंधी जोखिम विशिष्ट प्रकृति का है और इसका अधिकतर भाग, आर्थिक चक्र से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त, बड़े बीमाकर्ता औसतन भली प्रकार से भौगोलिक रूप से एवं व्यापारिक दृष्टिकोण दोनों दृष्टियों से विविधतापूर्ण हैं। इसके विपरीत, बैंक विशिष्ट जोखिम आर्थिक चक्र से अत्यधिकसंबंधित हैं। बीमा कंपनियों का मुख्य दायित्व आस्ति-देयता प्रबंधन होता है। बीमाकर्ताओं के पास भारी मात्रा में आस्तियां होती हैं जिन्हें वे अपनी देयताओं के प्रति संतुलित करते हैं। अतः बीमा कर्ताओं की निवेश क्रिया तृतीय पक्ष आस्ति प्रबंधन से अलग होती है जो

कि बाजार के बेंचमार्क के प्रति प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं के अत्यधिक विनियमित तुलन-पत्र भी जोखिम में आने वाली आस्तियों के अनुपात को सीमित कर देते हैं।

पूंजी बाजार निवेश के प्रति बीमा क्षेत्र का दृष्टिकोण

3.47 वित्तीय संकट के समय बीमा क्षेत्र की मुख्य भूमिका पूंजी बाजार में समग्ररूप से स्थिरता लाना रहा था, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में (चार्ट 3.13)। बीमा कंपनियां बड़ी निवेशक होती हैं और उनका (मुख्यतः जीवन बीमाकर्ताओं का) विशिष्ट रूप से दीर्घावधि निवेश क्षितिज होता है। उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं होता है कि टूटते हुए बाजार में उन्हें बिक्री करनी ही पड़ेगी और बल्कि गिरते हुए पूंजी बाजार में वे इसके विपरीत भी कर सकती हैं जो उन्हें लंबी स्थितियां बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

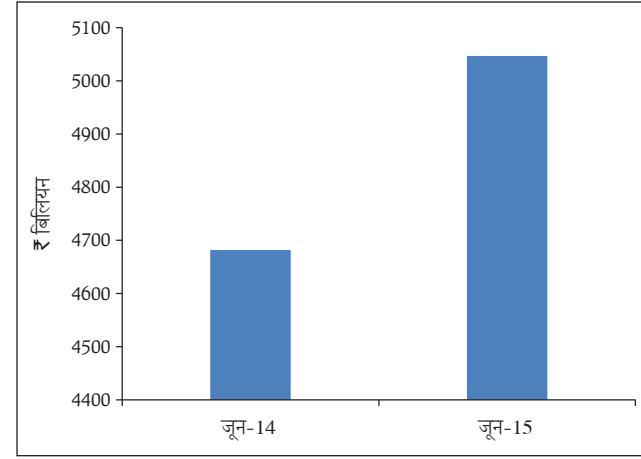
बीमाक्षेत्र के लिए निवेश जोखिम और विनियमन

3.48 बीमा कंपनियों के मामले में निवेश करने की पद्धतियां उनके विनियमनों में निर्धारित होती हैं, जो क्षेत्र आधार, समूह आधार और निकाय आधार पर जोखिम सीमाएं प्रदान करता है। अचल संपत्ति में किया जाने वाला एक्सपोजर निवेश योग्य कुल आस्तियों/ कुल निधि मूल्यों का 5 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त निवेशों के मूल्यांकन मानदंड लेखा विनियमों में निर्धारित होते हैं जो मुख्यतः परिशोधित लागत पर आस्तियों, ईक्विटी के मामले को छोड़कर जहां बीमाकर्ताओं को इन्हें सही कीमत पर मूल्यांकित करने की अनुमति होती है, के मूल्यांकन का प्रावधान करते हैं। तथापि, शोधन-क्षमता/ बोनस की घोषणा की गणना के लिए उचित कीमत और खरीद कीमत के बीच का अंतर उपलब्ध नहीं होता है।

विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों-जोखिम न्यूनीकरण

3.49 हाल ही में लाया गया बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 किसी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को भारत में अपनी शाखा स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है ताकि वह पुनर्बीमा संबंधी व्यवसाय कर सके। इन बीमाकर्ताओं का एक्सपोजर गैर-पारंपरिक और गैर-बीमा उत्पादों में हो सकता है, जिसमें प्रणालीगत जोखिम शामिल हो सकते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी किए विनियमनों²¹ का उद्देश्य पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है ताकि सभी संभावित प्रणालीगत जोखिमों का शमन किया जा सके।

चार्ट 3.13: पूंजी बाजारों में बीमा कंपनियों के निवेश की तुलनात्मक स्थिति



स्रोत: आईआरडीएआई

पेंशन क्षेत्र

बदलती हुई जनसांख्यिकी के साथ बढ़ती हुई महत्ता

3.50 पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इस समय सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2.2 प्रतिशत पेंशन भुगतानों पर खर्च कर रही है जो कि एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक जीडीपी के 4.1 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अतः पेंशन फंड विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निरंतर चलने वाली पेंशन प्रणाली के लाभ वर्तमान लक्षित समूहों के अलावा अन्य को भी मिल सकें और इसका सरकार के राजकोषीय अनुशासन पर भी कोई अनुचित प्रभाव न पड़े और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घावधि में निधियों की व्यवस्था की जा सके।

3.51 इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र में कार्यबल के पास वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के औपचारिक माध्यमों तक सीमित पहुंच है। अतः एक व्यवहार्य वृद्धावस्था सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना अनिवार्य बन गया है ताकि तेजी से बदलते हुए जनसांख्यिकीय लाभ का सामना किया जा सके। कमजोर श्रम बाजार संबद्धताओं, लगातार न होने वाली आय और सामाजिक सुरक्षा तक थोड़ी पहुंच, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके उत्पादनकारी वर्षों में आर्थिक आघातों के प्रति अत्यधिक कमजोर बना देती हैं और किसी भी प्रकार के सेवानिवृत्ति आय या लाभों तक पहुंच न होने के कारण इस बात की संभावना रहती है कि उन्हें वृद्धावस्था में निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है।

²¹ आईआरडीए (2015), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं का पंजीकरण और शाखा कार्यालयों का परिचालन) विनियमन, अधिसूचना https://www.irda.gov.in/ADMINCMS/cms/frnGeneral_Layout.aspx?page=PageNo2652&flag=1 पर उपलब्ध

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत प्रगति

3.52 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों की संख्या और प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में सतत वृद्धि देखी जा रही है (चार्ट 3.14)। जून 2015 में प्रारंभ की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य लचीलेपन और सरल परिचालनों सहित असंगठित क्षेत्र को एक निश्चित का स्तर और वहनीय सेवानिवृत्ति समाधान प्रदान करना है जो मौसमी रोजगार की चुनौती और वृद्धावस्था में ऋणग्रस्तता का भी सामना करने में सक्षम बना सकेगा। एपीवाई ने जून 2015 से 24 अक्टूबर 2015 तक की अवधि के दौरान 825,000 ग्राहकों के साथ रु. 1.43 बिलियन की राशि जोड़ी है। स्वालंबन योजना के तहत मौजूदा उपस्थिति स्थलों (पीओपी) और समूहकों (एग्रीगेटर) का उपयोग एनपीएस संरचना के जरिए ग्राहकों का पंजीयन कराने के लिए किया जा रहा है और एपीवाई के तहत एकत्र की गई राशि का प्रबंधन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश तरीके के अनुसार एपीवाई द्वारा नियुक्त पेंशन फंडों द्वारा किया जा रहा है।

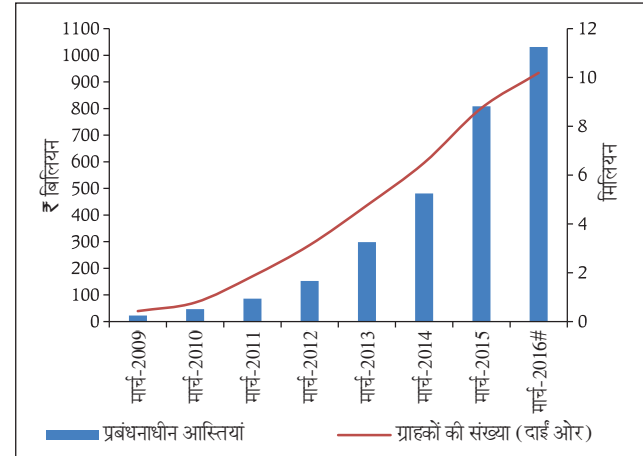
निवेश दिशानिर्देशों में संशोधन

3.53 एनपीएस योजनाओं के लिये लागू निवेश दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार किया जाता है और आवधिक रूप से उन्हें संशोधित किया जाता है ताकि ग्राहक को मिलने वाले प्रतिफल को अधिकतम किया जा सके और साथ ही वित्तीय प्रवाह एवं आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया जा सके। एनपीएस के तहत, दर्जाप्राप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण फंडों (आईडीएफ) और इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों को एनपीएस योजनाओं की सभी प्रकार की श्रेणियों के तहत निवेश के लिए पात्र माना जाता है बशर्ते कि उन लिखतों में निवेश किया जाए जिनके पास दर्जा प्रदान करने वाली कम-से-कम दो एजेंसियों से निवेश ग्रेड का दर्जा प्राप्त हो।

पेंशन फंडों के चुनाव का विकल्प और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए योजनाएं

3.54 पीएफआरडीए अधिनियम 2013²² यह कहता है कि ग्राहकों के लिए कई प्रकार के पेंशन फंडों और कई प्रकार की पेंशन योजनाओं को चुनने का विकल्प होगा। पीएफआरडीए अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों

चार्ट 3.14: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्राहकी और प्रबंधनाधीन आस्तियों में रुझान



टिप्पणी: इसमें एपीवाई शामिल है और आंकड़े 24 अक्टूबर 2015 तक
स्रोत: पीएफआरडीए

के लिए निवेश ढांचे का संरेखण किया जाए। पेंशन फंड का चुनाव करने और निवेश के तरीके को चुनने का विकल्प व्यक्तिगत कर्मचारी के पास होना चाहिए। इस बात की आवश्यकता है कि जोखिम को नियोजक से कर्मचारी की ओर अंतरित किया जाए जिसमें वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा के दायित्व का 'वित्तपोषण' उसके वैयक्तिक सेवानिवृत्ति खाते के जरिए करने की जिम्मेदारी नियोजक से अंतरित होकर वैयक्तिक कर्मचारी की ओर चली जाती है। सरकारी के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के ग्राहकों, दोनों के लिए निवेश के तरीकों में संगतता लाकर अन्य ग्राहकों के साथ एकरूपता यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी ग्राहक भी पेंशन फंड प्रबंधक को चुनने का और साथ ही तीन प्रकार की आस्ति श्रेणियों (ईक्विटी, कॉर्पोरेट ऋण और सरकारी प्रतिभूतियां) के बीच निधियों को आवंटित करने का अधिकार रखते हैं, जिसमें केवल एक ही सीमा लागू है कि निधियों का अधिकतम 50 प्रतिशत ही ईक्विटी के लिए आवंटित किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट बांडों में निवेश-पेंशन निधियों के लिए जोखिम

3.55 पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित किए गए मौजूदा निवेश दिशानिर्देश ग्राहक के अंशदान के 45 प्रतिशत को कॉर्पोरेट बांडों में निवेशित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पेंशन फंड्स द्वारा इस सीमा का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है ताकि बेहतर आस्तियां और प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें और इस समय एनपीएस पोर्टफोलियो का 33.95

²² पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20(2)।

प्रतिशत भाग कार्पोरेट बांड्स में निवेशित है। किसी ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए पीएफआरडीए ने विभिन्न लिखतों की उप-श्रेणियों के संबंध में संकेन्द्रण जोखिम और समूह तथा उद्यम में एक्सपोजर हेतु सीमाएं भी निर्धारित की हैं।

3.56 आर्थिक गिरावट के चक्र और कार्पोरेट आय में धीमी संवृद्धि ने हाल के वर्षों में भारत में कार्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित किया है। अतः, विनियामकीय नुस्खों के अतिरिक्त, पेंशन फंड्स में समुचित जोखिम प्रबंधन ढाँचे और सूचना प्रणालियों का होना आवश्यक है ताकि कार्पोरेट बांड्स की क्रेडिट गुणवत्ता में होने वाली अचानक और भारी खराबी से उत्पन्न होने वाले संक्रामक जोखिम से बचाव किया जा सके। भारत में कार्पोरेट बांड्स बाजार के परिपक्व होने और गहरे होने के साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों और कार्पोरेट बांडों के बीच आस्तियों के आवंटन में लचीलेपन और कुशलता आने से भी पेंशन फंड्स की प्रभावकारिता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

वार्षिकी(एन्युटी) बाजार का गहरापन

3.57 मौजूदा स्थिति में निवेश के समय ग्राहक की पेंशन संपत्ति के कम से कम 40 प्रतिशत को वार्षिकी में बदल जाना होता है और पेंशन संपत्ति के 60 प्रतिशत को एकमुश्त रूप में निकाला जा सकता है। यद्यपि वार्षिकी से ग्राहक को उसकी वृद्धावस्था में एक नियत आय होती रहती है, फिर भी प्रतिफलों के संदर्भ में यह ईष्टतम हो यह जरूरी नहीं है। अतः आस्थगित वार्षिकी और अन्य सेवानिवृत्ति जैसे उत्पादों को विकसित करना आवश्यक है जो ग्राहकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् ईष्टतम प्रतिफल प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, वार्षिकी बाजार में गहराई लाने और पेंशन क्षेत्र का विस्तार प्रदान करने वाले उपाय करना भी अपेक्षित है।

वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था: जमाराशि बीमा

जमाराशि बीमा के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली

3.58 अधिकतर जमाराशि बीमा प्रणालियां प्रारंभ में प्रत्याशित समान दर प्रीमियम प्रणाली अपनाती है क्योंकि उन्हें बनाना, क्रियान्वित करना और प्रशासित करना अपेक्षाकृत सरल होता है।

वैश्विक रूप से जमाराशि बीमाकर्ताओं के बीच इस आवश्यकता की पहचान की जा रही है कि बैंकों की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभेदक प्रीमियम प्रणाली (डीपीएस) लिया जाए, जिसे अक्सर जोखिम आधारित प्रीमियम(आरबीपी) भी कहा जाता है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (एफडीआईसी), यूएस ने 1993 में आरबीपी की शुरुआत की थी। तब से अंतरराष्ट्रीय जमाराशि बीमाकर्ता एसोसिएशन (आईएडीआई) के 79 सदस्यों में से 26 ने 31 दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार जोखिम-आधारित प्रीमियम की प्रणाली अपना ली है।

3.59 भारत में, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों ने पूर्व में बैंकों के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम आरंभ करने हेतु सिफारिशें की हैं। तथापि, विभिन्न कारणों से जोखिम-आधारित प्रीमियम को क्रियान्वित नहीं गया है। दूसरी ओर, हाल ही में हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर यह मांग की गई है कि जमाराशि बीमा कवर को मौजूदा रु. 0.1 मिलियन से बढ़ाया जाए। बीमित बैंकों की जोखिम-प्रोफाइल के अनुसार प्रीमियम दरों को युक्ति संगत बनाए बिना बीमा कवर में वृद्धि करने से नैतिक बाधाओं में वृद्धि हो सकती है।

भारत में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली के संबंध में समिति की रिपोर्ट

3.60 इस संबंध में, भारत में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली पर एक समिति²³ का गठन 31 मार्च 2015 में किया गया था ताकि वह भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम को लागू करने के लिए अपनी सिफारिशें दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 2015 को प्रस्तुत की जिसके साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक और डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए डाल दिया गया। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रीमियम दरें निर्धारित करने के लिए श्रेणियों की संख्या, सदस्य बैंकों के लिए मॉडल संबंधी सूचना, जो मुख्यतः लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आंकड़ों पर आधारित हो, को एकत्र करने हेतु डीआईसीजीसी के लिए सूचना प्रबंध तंत्र

²³ अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, भारिबैंक

(एमआईएस) स्थापित करना, सरकारी प्लेटफार्म पर रेटिंग नमूने की मुख्य विशेषताओं से संबंधित सूचना, रेटिंग प्रणाली और एकत्र किए जाने वाले प्रीमियम की आवधिक समीक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।

वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर

पूंजी बाजार में समाशोधन निगमों द्वारा दबाव परीक्षण

3.61 समाशोधन निगमों के लिए यह अपेक्षित है कि चिह्नित स्टॉक एक्सचेंज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए वे एक निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) बनाएं ताकि स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित क्षेत्र में संपादित किए गए व्यापारों के निपटान की गारंटी दे सकें। इस उद्देश्य के लिए, यह सुनिश्चित करने हेतु समाशोधन निगमों द्वारा बनाया गया एसजीएफ पर्याप्त है, उनसे यह अपेक्षित होता है कि वे क्रेडिट जोखिम के लिए प्रत्येक क्षेत्र, नामतः ईक्विटी, ईक्विटी डेरीवेटिव और करेंसी डेरीवेटिव, हेतु दबाव जांच के लिए मानकीकृत निर्धारित प्रक्रियाविधि का उपयोग करते हुए दैनिक आधार पर दबाव परीक्षण करें। दबाव परीक्षण परिदृश्यों के जरिए प्राप्त की गई निकृष्टतम मामले में हानि की संख्या का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए एसजीएफ हेतु न्यूनतम अपेक्षित निधियों (एमआरसी) की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

3.62 एसजीएफ, दबाव परीक्षण और मूल क्रमिक दिशानिर्देश (डिफाल्ट वाटरफॉल गाइडलाइन्स) दिसंबर 2014 में प्रभावी हुए। तीन समाशोधन निगमों - भारतीय समाशोधन निगम लि. (आईसीसीएल), राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल) और भारतीय मेट्रोपालिटन समाशोधन निगम लि. (एमसीसीआईएल)-से प्राप्त हुए आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2015 माह के लिए सभी क्षेत्रों के एसजीएफ के लिए कुल एमआरसी इस प्रकार रहा-आईसीसीएल: रु. 1.73 बिलियन; एनएससीसीएल: रु. 9.42 बिलियन और एमसीसीआईएल: रु. 0.42 बिलियन। दिसंबर 2014 की अवधि की तुलना में नवंबर 2015 में दबाव परीक्षण के परिणामस्वरूप एसजीएफ के लिए एमआरसी की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका निपटान निगमों और स्टॉक एक्सचेंजों ने उचित प्रकार से निधीयन किया है।

3.63 दबाव परीक्षण के अलावा, समाशोधन निगम चलनिधि दबाव परीक्षण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण भी करते हैं ताकि

समाशोधन निगमों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, समाशोधन निगम मार्जिन मॉडल के समुचित होने का पता लगाने के लिए पृष्ठभूमि में मार्जिन का भी परीक्षण करते हैं।

ईक्विटी बाजार के एफएमआई का सायबर सुरक्षा ढांचा

3.64 वैश्विक गतिविधियों के साथ कदम ताल करते हुए सेबी ने वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर सिद्धांतों (पीएफएमआई) को अपनाया है जिन्हें भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समिति (सीपीएमआई) तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईबोएससीओ) ने निर्धारित किया था और प्रतिभूति बाजार में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीएमएफआई का सिद्धांत 17 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं में 'परिचालन जोखिम' का प्रबंधन करने और उसे कम करने से संबंधित है। तदनुसार, सेबी ने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करते हुए, सायबर सुरक्षा और सायबर लचीलेपन के संबंध में एक ऐसा ढांचा निर्धारित किया जिसका अनुपालन, प्रतिभूति बाजार (जैसे स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम) में भाग लेने वाले एफएमआई के लिए करना अपेक्षित होगा। स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों और समाशोधन निगमों के लिए यह अनिवार्य है कि वे महत्वपूर्ण आईटी आस्तियों और इस प्रकार की आस्तियों से संबद्ध जोखिम को 'चिह्नित' करें; समुचित नियंत्रणों, उपकरणों और उपायों को लागू करते हुए आस्तियों की 'सुरक्षा' करें; समुचित निगरानी उपकरणों/ प्रक्रियाओं के जरिए घटनाओं, कमियों और आघातों की 'पहचान' करें; घटनाओं, कमियों और आघातों की पहचान करने के बाद उनका 'प्रत्युत्तर' देने के लिए तत्काल उपाय करें और घटना प्रबंधन, आपदा से बहाली और व्यापार निरंतरता ढांचे के जरिए घटना से 'वापसी' करें। यह ढांचा- अभिशासन, महत्वपूर्ण आस्तियों और सायबर जोखिमों (खतरे तथा कमजोरियों) की पहचान, पहुंच नियंत्रण, भौतिक सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा प्रबंध, आंकड़ों की सुरक्षा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मजबूती, एप्लीकेशन की सुरक्षा और जांच, पैच प्रबंधन, प्रणालियों और भंडारण उपकरणों का निपटान, कमजोरी का अनुमान एवं व्यापकता जांच (वीएपीटी), निगरानी और जांच, प्रत्युत्तर एवं बहाली, सूचना का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं आवधिक ऑडिट जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।

मुख्य वित्तीय बाजारों में केंद्रीय प्रतिपक्षी को सुदृढ़ बनाना

3.65 जैसा कि एफएसआर के पिछले अंकों में प्रस्तुत किया गया है, रिजर्व बैंक भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय कर रहा है। तदनुसार, यूएस डॉलर-भारतीय रूप के क्षेत्र में हरस्टैट जोखिम²⁴ को कम करने के लिए अप्रैल 2015 से भुगतान-बनाम-भुगतान (पीपी) निपटान व्यवस्था लागू कर दी गई है और आईआरएस व्यापार प्रणाली; जो कि एक नाम रहित प्रणाली है; हेतु अगस्त 2015 में रूप में ओटीसी व्यापार ब्याज दर डेरीवेटिव (एएसटीआरओआईडी) प्रारंभ कर दिया गया है। सीसीआईएल आइआरएस क्षेत्र में पोर्टफोलियो को संक्षिप्त बना रहा है। भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समिति (सीपीएमआई) और आईओएससीओ द्वारा प्रकाशित पीएफएमआई के प्रति सीसीआईएल जहां एक स्व-मूल्यांकन कर रहा है, वहीं रिजर्व बैंक ने भी सीसीआईएल का निरीक्षण किया है ताकि पीएफएमआई के प्रति इसके अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके। सीपीएमआई-आईओएससीओ द्वारा प्रकाशित प्रकटन ढांचे के अनुसार पीएमएफआई²⁵ के अनुपालन के लिए सीसीआईएल ने भी पीएफएमआई के 23वें सिद्धांत के अनुसार प्रकटन किया है। सीसीआईएल को सूचित किया गया है कि वे विनियामक (रिजर्व बैंक) के साथ चर्चा कर बहाली और संकल्प योजना तैयार करे।

भारत के लिए विधिक निकाय पहचानकर्ता (एलईआई)²⁶ प्रणाली

3.66 स्थानीय परिचालन एकक (एलओयू) एलईआई प्रणाली का स्थानीय स्तर पर परिचालन करते हैं और एलईआई के लिए पंजीकृत होने को इच्छुक निकायों के लिए प्राथमिक चेहरा होते हैं। भारत में सीसीआईएल को एलओयू के रूप में चिह्नित और नामित किया गया था। विनियामकीय पर्यवेक्षण समिति (आरओसी) द्वारा सीसीआईएल को प्री-एलओयू के रूप में भी पंजीकृत किया

गया है और इसने एलईआई निर्गम²⁷ करने की सेवा, स्वयं को और आईसीसीएल को एलईआई जारी करके कर दी है। अभी तक इसने विभिन्न निकायों को 13 एलईआई जारी किए हैं। सीसीआईएल की नई अनुषंगी भारतीय विधिक निकाय पहचानकर्ता लि. (एलईआईएल) को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा पंजीकृत किया गया है।

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की समुत्थानशक्ति का परीक्षण

3.67 रिजर्व बैंक भारत में बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे आवधिक रूप से व्यापार निरंतरता (बीसी)/ आपदा बहाली (डीआर) का अभ्यास करें ताकि कोर बैंकिंग प्रणालियों जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणालियों में उच्च स्तर की समुत्थानशीलता सुनिश्चित की जा सके। बैंक आवधिक रूप से बीसी/डीआर का अभ्यास कर रहे हैं जो विशेष रूप से उनकी कोर बैंकिंग प्रणाली और सामान्यतः आईटी प्रणालियों में उच्च स्तर की आघात समुत्थानशीलता दर्शाता है।

3.68 सायबर सुरक्षा के संबंध में सूचना प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग समुदाय के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं: जोखिम और खतरों के विश्लेषण के लिए भारतीय बैंकों का केंद्र (आईबी-सीएआरटी) तथा कंप्यूटर आकस्मिकता प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन)। बैंकिंग विकास और अनुसंधान संस्थान का आईबी-सीएआरटी एक केंद्रीय प्लेटफार्म है जो सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। सीईआरटी-आईएन को सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत गठित किया गया है जो बैंकिंग और फिशिंग जैसे सायबर सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी ताकत को मजबूत बनाता है। आईबी-सीएआरटी से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यहां 2,214 सुरक्षा संबंधी घटनाएं हुई हैं जिनमें से

²⁴ हर्स्टैट जोखिम जिसे विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन (क्रास-करंसी) में निपटान जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा जोखिम है जिसमें व्यापार में शामिल कोई एक पक्ष भुगतान करने में विफल हो जाता है यद्यपि कि प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान किया जा चुका होता है।

²⁵ सीसीआईएल (2015), वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सिद्धांतों के अनुपालन पर सीसीआईएल प्रकटन मानदंड', https://www.ccilindia.com/Documents/whats_new/PFMI%20Qualitative%20Disclosure%20March%202015.pdf पर उपलब्ध।

²⁶ एलईआई एक मानक संदर्भ कूट संख्या है जो निकायों को पहचानने का एक सार्वभौमिक तरीका है जिसमें वित्तीय और वित्तेतर दोनों प्रकार की कंपनियां शामिल होती हैं, जो कि ओटीसी डेरीवेटिव लेनदेनों या अन्य वित्तीय लेनदेनों में प्रतिपक्षी होती हैं या ऐसी कंपनियां होती हैं जो वित्तीय लेनदेनों की शर्त के तहत प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां जारी करती हैं।

²⁷ 18 नवंबर 2014 को

2,196 घटनाएं वास्तविक थीं जबकि शेष इस प्रकार के प्रयास थे जो सफल नहीं हो पाए (चार्ट 3.15)।

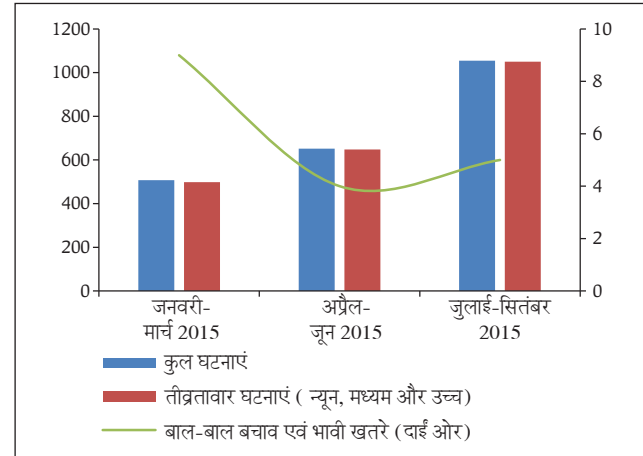
भुगतान प्रणालियां

3.69 रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और परिचालन कर रहा है। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), ई-कुबेर कोर बैंकिंग प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक सरकारी लेन-देन जैसे कि ई-रसीद और ई-भुगतान। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास होने के कारण भुगतान प्रणालियों की समग्र गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापार निरंतरता दस्तावेज (बीसीपी) तैयार किया जा रहा है जो आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन होगा। बीसीपी का मुख्य प्रौद्योगिकीय पहलू आपदा से बहाली करने की योजना है जो निर्धारित समयावधि के भीतर कंप्यूटिंग और नेटवर्क परिचालनों को तत्काल और अस्थायी रूप से बहाल कर देती है।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

3.70 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) और इसकी उप समिति प्रत्येक की 2015 के दौरान दो बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान विचार-विमर्श के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया जो इस प्रकार थे: बैंकिंग उद्योग में आस्ति-गुणवत्ता और कॉरपोरेट क्षेत्र में तुलन पत्र दबाव, कॉरपोरेट बांड बाजार का विकास, सामूहिक निवेश योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), केंद्रीय 'अपने ग्राहक को जानिए' रजिस्ट्री, बहु-प्रांतीय सहकारी समितियों द्वारा जमाराशि ग्रहण करना, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत रिपोर्टिंग हेतु अंतर-विनियामक समन्वय, भारत में पेंशन क्षेत्र की समुचित संवृद्धि, राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों (एसएलसीसी) की कार्यप्रणाली और वित्तीय आस्तियों के लिए खाता समूहन निर्माण हेतु मानक एवं प्रोटोकॉल।

चार्ट 3.15: 2015 के दौरान रिपोर्ट की गई 'घटनाओं' की संख्या में रुझान



स्रोत: आईबीसीएआरटी

अनुबंध-1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अक्टूबर 2015¹ में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का नौवां सर्वेक्षण है। परिणाम यह संकेत करते हैं कि वैश्विक जोखिम वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम के रूप में अभी भी उच्च जोखिम श्रेणी में विद्यमान हैं। समष्टिआर्थिक जोखिम में कमी हुई है और वे मध्यम जोखिम की श्रेणी में आ गए हैं। इस सर्वेक्षण में बाजार जोखिमों में कथित रूप से बढ़ोतरी हुई है और वे निम्न जोखिम श्रेणी से निकलकर उच्च जोखिम श्रेणी में चले गए हैं, जो सर्वेक्षण के वैकल्पिक चरण में उतार और चढ़ाव की चक्रीय स्थिति दर्शाता है। दूसरी ओर, संस्थागत जोखिम, मध्यम जोखिम श्रेणी में बना रहा। इस सर्वेक्षण में सामान्य जोखिमों में कमी आई है (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के तहत, मौजूदा सर्वेक्षण में वैश्विक मंदी का जोखिम और सरकारी जोखिम बढ़ गया है जबकि वैश्विक निधीयन और वैश्विक मुद्रास्फीति जोखिम में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। इस सर्वेक्षण में, समष्टिआर्थिक जोखिम की श्रेणी के अंतर्गत, घरेलू आर्थिक संभावना में कमी आने से संबंधित जोखिम घटकर मध्यम जोखिम की श्रेणी में आ गया है जबकि घरेलू मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा से संबंधित जोखिम में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पूंजी प्रवाह और कार्पोरेट क्षेत्र से संबंधित जोखिम उच्च जोखिम की श्रेणी में बने रहे। उत्तरदाताओं ने विदेशी मुद्रा जोखिम, ईक्विटी कीमत में अनिश्चितता और निधीयन जोखिम को वर्तमान सर्वेक्षण में बढ़ी हुई रेटिंग प्रदान की है। संस्थागत जोखिमों के बीच, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को अभी भी उच्च जोखिम घटक के रूप में देखा गया, ऋण की कम उठान के कारण होने वाले जोखिम में मामूली कमी आई है (चित्र-2)।

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षणों में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अक्टूबर 2015)

प्रमुख जोखिम समूह	अक्टू-15	परिवर्तन	अप्रैल-15	परिवर्तन	अक्टू 14	परिवर्तन	अप्रैल-14	परिवर्तन	अक्टू 13
ए. वैश्विक जोखिम		↑		↔		↑		↓	
बी. समष्टिआर्थिक जोखिम		↓		↓		↔		↑	
सी. बाजार जोखिम		↑		↓		↑		↓	
डी. संस्थागत जोखिम		↔		↑		↓		↔	
ई. सामान्य जोखिम		↓		↑		↓		↑	

टिप्पणी :

जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्ध वार्षिक आधार में) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित हो (बढ़/घट) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि, समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं संबंधी परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षणों के तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं. प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2015) (अर्द्ध वार्षिक)।

¹ ये सर्वेक्षण अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण अक्टूबर 2011 में किया गया था।

चित्र 2 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्टूबर 2015) में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम				
जोखिम समूह	जोखिम की मद	अक्टू 15	परिवर्तन	अप्रैल-15
ए. वैश्विक जोखिम	वैश्विक मंदी		↑	
	सरकारी जोखिम/संक्रमण		↑	
	निधीयन जोखिम (बाहरी उधार)		↓	
	वैश्विक मुद्रास्फीति/पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमत सहित)		↓	
	अन्य वैश्विक जोखिम		↔	
बी. समष्टिआर्थिक जोखिम	घरेलू आर्थिक संभावनाओं का कमजोर होना		↓	
	घरेलू मुद्रास्फीति		↓	
	चालू खाता घाटा		↓	
	पूंजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↔	
	सरकारी रेटिंग में गिरावट		↔	
	राजकोषीय जोखिम (उच्च राजकोषीय घाटा)		↔	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम (उच्च लिवरेज/निम्न लाभकारिता)		↔	
	आधारभूत संरचना के विकास की कमी/धीमी गति		↓	
	स्थायर संपदा के मूल्य		↓	
	पारिवारिक इकाइयों की बचत		↓	
	राजनीतिक जोखिम		↔	
	अन्य समष्टिआर्थिक जोखिम		↑	
	सी. बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↑
इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव			↑	
निधीयन जोखिम/चलनिधि जोखिम/ब्याज दर जोखिम			↑	
बाजार संबंधी अन्य जोखिम			↑	
डी. संस्थागत जोखिम	विनियमन जोखिम		↓	
	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↑	
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकता		↓	
	बैंकों की निधीयन संबंधी मुश्किलें		↓	
	ऋण का धीमा उठाव		↓	
	ऋण में बहुत अधिक वृद्धि		↔	
	परिचालनात्मक जोखिम		↑	
	संस्थागत अन्य जोखिम		↓	
ई. सामान्य जोखिम	आतंकवाद		↔	
	प्राकृतिक आपदा/प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां		↓	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती हुई असमानता)		↔	
	अन्य सामान्य जोखिम		↔	

टिप्पणी:
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्ध वार्षिक आधार में) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित हो (बढ़/घट) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि, समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं संबंधी परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षणों के तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015)।

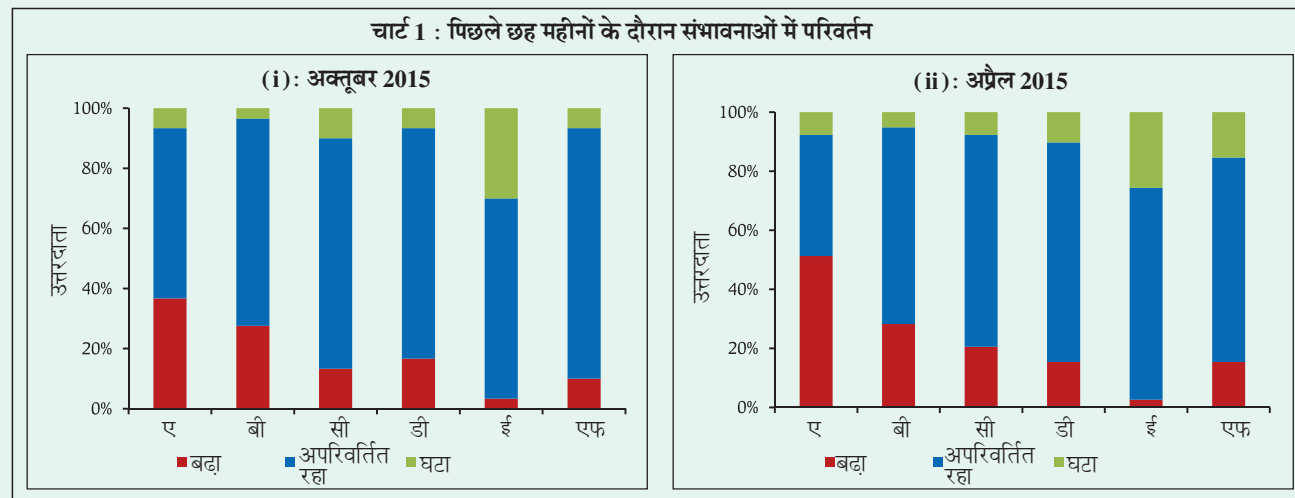
सर्वेक्षण के मौजूदा चरण में प्रतिभागियों ने यह महसूस किया है कि आगामी अवधि (अल्प से मध्यम अवधि) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने की संभावना अधिक है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विषय में उनका विश्वास कम रहा और अधिकतर प्रतिभागियों ने यह दर्शाया कि पिछले छह महीनों के दौरान उनके विश्वास में मामूली कमी आई है। तथापि, प्रतिभागियों के अनुसार, आगामी अवधि (अल्प से मध्यम अवधि) में भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने की 'मध्यम' दर्जे की संभावना है हालांकि उत्तरदाताओं ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में अपना विश्वास बनाए रखा है (चित्र-3 और चार्ट-1)।

चित्र-3: उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अक्टूबर 2015)		
प्रभाव	अक्टूबर 15	अप्रैल 15
ए. आगामी अवधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अल्प अवधि में: 1 वर्ष तक)		
बी. आगामी अवधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (मध्यम अवधि में: 1 से 3 वर्ष तक)		
सी. आगामी अवधि में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (अल्प अवधि में: 1 वर्ष तक)		
डी. आगामी अवधि में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना होने की संभावना (मध्यम अवधि में: 1 से 3 वर्ष तक)		
ई. समग्र रूप में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास		
एफ. भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में विश्वास		

टिप्पणी
जोखिम श्रेणी

Risk	बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
ए-डी					
ई-एफ	अति विश्वसनीय	विश्वसनीय	काफी विश्वसनीय	बहुत विश्वसनीय नहीं	विश्वसनीय नहीं

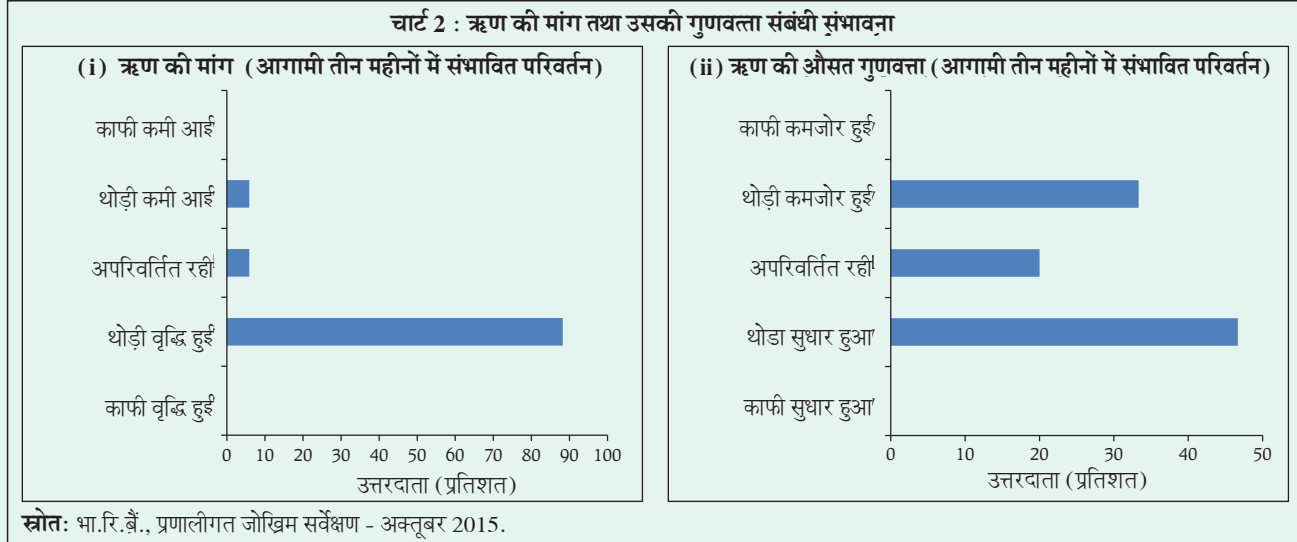
स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015)।



नोट : ए. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
 बी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
 सी. भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
 डी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
 ई. समग्र रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।
 एफ. समग्र रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015.

अगले तीन महीनों में ऋण के लिए मांग में होने वाली संभावित मांग के मुद्दे पर अधिकतर उत्तरदाताओं का यह विचार था कि इसमें मामूली बढ़त हो सकती है। अधिकतर उत्तरदाताओं ने यह दर्शाया कि क्रेडिट की औसत गुणवत्ता में अगले तीन महीनों में सुधार होगा। तथापि, उत्तरदाताओं के एक समूह का यह विचार था कि इसमें मामूली गिरावट आ सकती है (चार्ट-2)।



अनुबंध 2 कार्यप्रणालियां

कारपोरेट क्षेत्र

बैंक ऋण के संबंध में एनजीएनएफ कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमता में कमजोरी के प्रभाव का मूल्यांकन

1. सामान्य सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के कुल बैंक ऋण तथा निजी गैर-वित्तीय निगमों [अर्थात् गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां] को दिए गए बैंक ऋण से संबंधित आंकड़ों का पता चलता है। इस प्रयोजन से, कुल बैंक ऋण में एनजीएनएफ कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से का आकलन किया गया है।
2. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) डाटाबेस के नमूने का प्रयोग करते हुए नमूने में दी गई समस्त एनजीएनएफ कंपनियों की कुल बैंक उधारियों में 'कमजोर' एनजीएनएफ कंपनियों की बैंक उधारी के अनुपात की गणना की गई है। इसी प्रकार से नमूने में दी गई कुल बैंक उधारियों में 'लीवरेजयुक्त' एनजीएनएफ कंपनियों की बैंक उधारी के अनुपात की गणना की गई है।
3. 'कमजोर' और 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों के कारण बैंक ऋण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए उपर्युक्त पैरा 2 में निकाले गए अनुपात को बीएसआर ऋण डाटा (उक्त पैरा 1) पर लागू किया गया है। इस प्रकार कुल बैंक ऋण में प्रतिशत के रूप में 'कमजोर' कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से तथा कुल बैंक ऋण में प्रतिशत के रूप में 'लीवरेजयुक्त कमजोर' कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण के हिस्से का आकलन किया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करते हैं। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक में पांच संयुक्त सूचकांकों का प्रयोग किया गया है जिनके पांच आयाम हैं - मजबूती, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में जिन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सारणी-1 में दिया गया है:-.

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात				
आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों की तुलना में पुनःसंरचित- मानक- अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों की तुलना में ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों की तुलना में गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों की तुलना में 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट+ जमाराशि) #		कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय

नोट: # जोखिम से प्रतिलोम संबंध है।

प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपात द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता

है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नूमा अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है :

$$\frac{X_t - \min(X_t)}{\max(X_t) - \min(X_t)}$$

जिसमें X_t अनुपात के मूल्य को t समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

हानि का अनुमान: संभावित हानि, असंभावित हानि और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संभावित कमियां

इन हानियों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मानक परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है:

- संभावित हानि (ईएल) : ईएल वह औसत क्रेडिट हानि है जिसकी संभावना बैंकिंग प्रणाली के अपने क्रेडिट एक्सपोजर से उत्पन्न होती है।
- असंभावित हानि (यूएल) : $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर वह हानि होती है जो संभावित हानि को घटाकर हानि वितरण के α -क्वान्टाइल (α -quantile) पर हो सकती है।
- संभावित कमी (ईएस): जब हानि (Z) का वितरण निरंतर होता है, $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के विश्वास स्तर ($ES\alpha(Z)$) पर होने वाली संभावित कमी को, $ES\alpha(Z) = E[Z | Z \geq VaR_\alpha(Z)]$ से संभावित हानि को घटाकर Z के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः, होने वाली संभावित कमी, हानि की सशर्त संभावना है यदि VaR स्तर से संभावित हानि घटाने पर हानि अधिक हो जाती है।

इन हानियों का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है:

- जहां, ईएडी = चूक की स्थिति में एक्सपोजर है, जो बैंकिंग प्रणाली का कुल अग्रिम होता है। ईएडी में केवल तुलन पत्र से संबंधित मदें शामिल होती हैं क्योंकि चूक की संभावना (पीडी) केवल तुलन-पत्र पर मौजूद एक्सपोजर के लिए ही निकाला जा सकता है।
- एलजीडी = चूक के कारण हुई हानि है। आधारभूत परिदृश्य के तहत, 'पूंजी पर्याप्तता-क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने के लिए दि आईआरबी एप्रोच' पर भरिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार औसत एलजीडी को 60 प्रतिशत के रूप में माना जाता है। मध्यम और गंभीर मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्यों के तहत एलजीडी को क्रमशः 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत माना गया।
- पीडी = पीडी को कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन अग्रिमों के रूप में परिभाषित किया गया है। चूककर्ता खातों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण पीडी का पता लगाने के लिए चूककर्ता खातों (अर्थात् सकल गैर-निष्पादन आस्ति संबंधी राशि) के आकार को उपयोग में लाया गया है।

ईएल, यूएल और ईएस हानियों को एक कृत्रिम पीडी वितरण प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया। पहले कदम के रूप में केरनल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए पीडी के अनुभवजन्य वितरण का अनुमान लगाया गया; उसके बाद अनुभवजन्य संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए मान्ते कार्लो कृत्रिमता पर आधारित 20,000 यादृच्छिक संख्याएं निकाली गईं और अंत में ईएल, यूएल और ईएस की गणना की गई जिसमें पीडी को, पीडी के 99.9 प्रतिशत वीएआर तक औसत के रूप में लिया गया गया और 99.9 प्रतिशत वीएआर से अधिक के औसत पीडी को क्रमशः हानि माना गया।

मैक्रो-दबाव परीक्षण

मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रति बैंकों की समुत्थानशक्ति सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो दबाव परीक्षण किया गया। मैक्रोइकोनॉमिक चरों के कार्य के रूप में एक क्रेडिट जोखिम संकेतक का निर्माण किया गया जिसमें विविध अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया जो चुनिंदा बैंकिंग प्रणाली को समग्रतः मैक्रोइकोनॉमिक चरों से संयुक्त करता है। जिन समय-श्रृंखला अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया वे इस प्रकार हैं: (i) बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ¹, (ii) वेक्टर स्वरीग्रेशन (वीएआर) को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iv) बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, और (vi) क्षेत्रगत सकल एनपीए के लिए बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन। समग्र बैंकिंग प्रणाली में विपथन अनुपात के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि मैक्रोइकोनॉमिक चरों में आधार कीमत पर जीवीपी संवृद्धि, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलएआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात ($\frac{EX}{GDP}$), जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष ($\frac{CAB}{GDP}$), और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल

¹ किसी अवधि के दौरान एनपीए में होने वाली नयी अनुवृद्धि विपथन है। विपथन अनुपात = नये एनपीए/अवधि की शुरुआत में मानक अग्रिम

राजकोषीय घाटा ($\frac{GFD}{GDP}$) शामिल होते हैं।

जहां बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली के सकल एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा मैक्रोइकोनॉमिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वहीं वीएआर नमूना, बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है और यह फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, विपथन अनुपात के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रीग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है।

नमूना ढांचा

जीएनपीए अनुपात और/अथवा स्लिपेज अनुपात (एसआर) पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी नमूने अपनाए गए:

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया: बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन, वीएआर (जो मैक्रो चरों और सहसंबद्धता प्रभावों के संबंध में क्रेडिट गुणवत्ता के प्रभावों के विषय में प्राप्त फीडबैक को भी संज्ञान में लेता है) और क्वान्टाइल रीग्रेशन (जो क्षुद्र जोखिमों के साथ निपट सकता है और मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के विषम-रेखीय प्रभावों को भी संज्ञान में लेता है)। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया है।

- **बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन**

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर विपथन अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$.

- **वेक्टर स्वतः रीग्रेशन (वीएआर) मॉडल**

अंकन रूप में, मध्यमान-समायोजित वीएआर के क्रम order p (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t ; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां, $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})'$ समय t पर चर का एक वेक्टर ($K \times 1$) A_i ($i=1,2,\dots,p$) निर्धारित ($K \times K$) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})'$ एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

अनुमान लगाने के लिए वीएआर मॉडल, विपथन अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के समुचित क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (VAR(2)) का अनुमान लगाया गया और एआर की बहुपदीय अभिलाक्षणिक मूल के आधार पर नमूने की स्थिरता की जांच की गई। चूंकि सभी मूल इकाई की परिधि के भीतर पाई गई अतः इस चुने गए नमूने को स्थिरता की शर्त पूरी करने वाला पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- **क्वान्टाइल रीग्रेशन**

विपथन अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन का प्रयोग किया गया:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-3} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

बैंक समूह स्तरीय पद्धति

बैंक समूह-वार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग करते हुए लगाया गया: बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन और वीएआर। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया।

• बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन

विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन का उपयोग किया गया:

सरकारी क्षेत्र के बैंक

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP} \right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

निजी क्षेत्र बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1}$$

विदेशी बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-5} + \beta_5 \text{Dummy}$$

• वेक्टर स्वतः रीग्रेशन मॉडल

विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो चरों पर आधारित थे:

सरकारी क्षेत्र के बैंक : आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

निजी क्षेत्र के बैंक : आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और क्रम 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात।

विदेशी बैंक : सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

क्षेत्रगत मॉडल्स

क्षेत्रगत बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन

विभिन्न क्षेत्रों पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बहुभिन्नरूपी रीग्रेशन नमूने का उपयोग किया गया जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से समग्र जीएनपीए अनुपात का उपयोग किया गया। आश्रित चरों में पिछले जीएनपीए, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि (समग्र या क्षेत्र-वार), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात शामिल था।

स्लिपेज से जीएनपीए का अनुमान

स्लिपेज अनुपातों से निकाले गए जीएनपीए जिनका अनुमान पूर्व में उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: 11 प्रतिशत की क्रेडिट संवृद्धि, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 11.7 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की दर से रिकवरी होना, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 4.48 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की दर से बड़े खाते डालना।

कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

बैंकों के पैट के कई घटक होते हैं, जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इन घटकों का विभिन्न समय श्रृंखलाओं पर आधारित अर्थमितीय नमूनों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया जाता है।

$$\text{पैट} = \text{एनआईआई} + \text{ओओआई} - \text{ओई} - \text{प्रावधान} - \text{आयकर}$$

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर निकाला जाता है:

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीवीएब्सए सार्केतिक जीवीए का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवीजीआर अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रेड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाए गए औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओओआई को निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

एलओओआई, ओओआई का लॉग है

परिचालनगत खर्च (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतःपरावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधान: अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान निम्नलिखित रीग्रेशन कर उपयोग कर दिया गया:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times RGVA_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

पी एडीवी, कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। आरजीवी जीआर वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्तियां हैं। डमी, कल्पित समयावधि है।

आयकर: लागू आयकर को कर पूर्व आय का 35 प्रतिशत माना गया है, जो कर पूर्व लाभ की तुलना में आयकर के पिछले रुझानों पर आधारित है।

पूंजी पर्याप्तता पर जीएनपीए का प्रभाव

निष्कर्षतः, सीआरएआर पर पड़ने वाला प्रभाव का अनुमान, पूर्व भाग में उल्लिखित अनुमानित पैट के आधार पर लगाया गया। आरडब्ल्यूए संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर 10 प्रतिशत, मध्यम जोखिम के तहत 12 प्रतिशत और गंभीर जोखिम वाली स्थिति में 14 प्रतिशत अनुमानित की गई। ऐसा माना गया कि विनियामकीय पूंजी में संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी क्योंकि इसके लिए यह माना गया कि लाभ का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित खातों में अंतरित किया गया और हितधारकों द्वारा किसी प्रकार के पूंजी लगाने को विचार में नहीं लेता है। 'तुलनपत्र पद्धतिट को अपनाते हुए, सकल गैर-निष्पादन आस्तियों के अनुपात के अनुमानित मूल्य को पूंजी अनुपातों के रूप में निरूपित किया गया, जिसके कारण तुलन पत्र में मौजूद पूंजी पर प्रावधानों और निवल लाभों के जरिए प्रभाव पड़ा।

एकल घटक संवेदनशीलता घटक-दबाव परीक्षण

तिमाही निगरानी करने के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए जाते हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की समुत्थानशीलता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की समुत्थानशीलता का परीक्षण करने के लिए सभी प्रकार के पोर्टफोलियो और कुछेक चुनिंदा सेक्टरों में जीएनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके आघात दिया जाता है। क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए मुख्य व्यक्तिगत उधारकर्ता(कर्ताओं) और उधारकर्ता(कर्ताओं) के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में मान लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि को मानक से कम, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। तथापि, क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम के लिए संभावित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए पर विचार किया गया ताकि उसे केवल अवमानक श्रेणी में रखा जा सके। विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के आधार पर इन दबाव जांचों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। अवमानक, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना में लिए गए अतिरिक्त

जीएनपीए पर इन मानदंडों को ही लागू किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय की हानि को एक तिमाही के लिए प्रावधानीकरण की अतिरिक्त आवश्यकताओं के अलावा कुल हानियों में भी शामिल किया गया। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण माने गए आघात के तहत, पोर्टफोलियो की कीमत में होने वाली कमी या आय में होने वाली गिरावट के कारण होने वाली हानियों को संज्ञान में लिया गया। बैंकों की पूंजी में से इन अनुमानित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया ताकि, कीमत के प्रभाव (पोर्टफोलियो हानियों) की गणना की जा सके। दिए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक कालावधि के लिए इन निवेशों पर पोर्टफोलियो हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआरपर निकालने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलियो में ब्याज दर आघात प्रभाव देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, मुद्दत पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियो पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियो दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्कड-टु-मार्केट) है।

बैंकिंग बही पर ब्याज दर जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन ध्याय पद्धति-के जरिए किया गया। एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो को छोड़कर दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजर अंतर के आधार पर आघातों के प्रभाव का आकलन आय हानियों के अनुमान द्वारा प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु किया गया। यह वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव को दर्शाता है।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव परीक्षण का उद्देश्य यह है कि चलनिधि के अप्रत्याशितरूप से बाहर चले जाने पर, बाहर से चलनिधि की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की संभावनाएं (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) सामने लाती हैं और साथ ही स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीशुदा क्रेडिट (कार्यशील पूंजी की स्वीकृत अप्रयुक्त सीमा, प्रतिबद्ध क्रेडिट और क्रेडिट पत्रों तथा गारंटियों की अप्रयुक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए) सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के लिए मांग उत्पन्न होती है। दबाव परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्रेडिट के लिए अतिरिक्त और अप्रत्याशित मांग को बैंकों की केवल चलनिधि युक्त आस्तियों की सहायता से पूरा करने की उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। दबाव परीक्षण ऋण की अतिरिक्त एवं अचानक उठने वाली मांग को सिर्फ अपनी चलनिधियुक्त आस्तियों की मदद से पूरा कर पाने की बैंक की क्षमता का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए।

चलनिधि दबाव परीक्षण की मान्यताएं इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधियुक्त आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेगा।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के कमीशन पर कर ली जाएगी।
- दबाव परीक्षण स्थैतिक मोड के अंतर्गत किया गया।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण करना

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण को शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श समूह के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में केंद्रित किया गया और इसके लिए व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की अनुमानित कीमत ली गई। प्रतिदर्श में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का अनुमान लगाएं।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया। व्युत्पन्नी व्यापार के लिए जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव परीक्षण से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया की दर और घरेलू ब्याज दरें मानकों के रूप में ली गईं।

सारणी 2 : संवेदनशीलता विश्लेषण के संबंध में आघात

		घरेलू ब्याज दरें
आघात 1	एक दिवसीय	+2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशत अंक

		घरेलू ब्याज दरें
आघात 2	एक दिवसीय	-2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशत अंक

		विनिमय दरें
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत

		विनिमय दरें
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण करना

क्रेडिट जोखिम

सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उनके आस्ति पोर्टफोलियो को उपयोग में लाते हुए क्रेडिट जोखिम के बारे में दबाव परीक्षण किया गया। यह जांच एक घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। ऐतिहासिक मानक विचलन (एसडी) का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया था :

अनुमानित परिदृश्य निम्नलिखित थे :

- परिदृश्य I: जीएनपीए पर 0.5 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य II: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य III: जीएनपीए पर 0.5 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य IV: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि में नकदी के प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें बहिर्वाह के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी बहिर्वाह की तुलना में नकदी प्रवाह का कम होना)] होने की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिदृश्य I : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 50 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)
- परिदृश्य II : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 100 प्रतिशत तक होना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण करना

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली -दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया, इसमें सितंबर 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार मौजूद उनके आस्ति पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया। ये परीक्षण एकल घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थीं। ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर तीन विभिन्न परिस्थितियों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।
- परिदृश्य II: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।
- परिदृश्य III: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में जीएनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित कर दिया गया। दबाव परीक्षण व्यक्तिगत एनबीएफसी स्तर के साथ ही साथ समग्र स्तर भी किया गया।

अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क का विश्लेषण करने में मूल विषय मैट्रिक्स अल्जेब्रा होता है, जो वित्तीय क्षेत्र में निकायों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजरों का उपयोग करता है। प्रणाली में एक संस्था की दूसरी संस्था को दी गई उधारियों अथवा ली गई उधारियों को वर्गाकार मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क मानचित्र में चिह्नित किया जाता है। प्रणाली में अंतर-संबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :

संबद्धता : यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव शृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच शृंखलाओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में $K = \sum_{i=1}^N k_i$ के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपसे में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। k_i , निकटवर्ती प्रत्येक बैंक हेतु उनके बीच सभी प्रकार के संभावित जुड़ावों की कुल संख्या $k_i(k_i-1)$ है। मान लेते हैं कि E_i एजेंट, i बैंक के k_i निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को प्रदर्शित करता है अर्थात् जो i के k_i निकटवर्ती हैं वो आपस में भी निकटवर्ती हैं। i बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस सर्वसमिका द्वारा व्यक्त गया है:-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी C_i का औसत निम्नलिखित है

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i}{N}$$

निकटतम मार्गस्थ दूरी : यह नेटवर्क के किसी एक नोड और अन्य नोडों में प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी शृंखलाओं की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

इन-बिटवीननेस सेंट्रलिटी: यह सांख्यिकी यह बताती है कि निकटतम मार्गस्थ दूरी किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के जरिए गुजरती है।

केंद्रीयता की आईजेनवेक्टर माप: किसी नेटवर्क में किसी नोड (बैंक) का क्या महत्व है इसे आईजेनवेक्टर केंद्रीयता के जरिए मापा जाता है। यह बताता है कि किसी नोड का पड़ोसी कितना संबद्ध हैं और यह उनकी बाहरी डिग्री या एक नोड के प्रत्यक्ष रूप से कितने 'पड़ोसी' हैं, उससे कहीं कुछ अधिक बताने का प्रयास करता है। यह अल्गोरिथम नेटवर्क के सभी नोड्स को एक संबद्ध केंद्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी नोड का केंद्रीयता अंक, आपस में संबद्ध सभी नोड्स को दिए गए केंद्रीय अंक के जोड़ के समानुपातिक होता है। किसी $N \times N$ मैट्रिक्स के लिए इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे, जिनके लिए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में उसका महत्व दर्शाता है। नेटवर्क विश्लेषण में इस उपाय का उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है।

कतारबद्ध नेटवर्क संरचना: विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में कतारबद्ध संरचना का उपयोग देखा जाता है। कतारबद्ध संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक (केंद्रीयता के आईजेनवेक्टर माप के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्र में होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य-केंद्र, बाहरी केंद्र और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित चक्रों में) उनकी संगत संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है और बाह्य अंश को सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत पर आते हैं वे भीतरी केंद्र का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशत के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशत वाले बैंकों की एक तीसरी सतह होती है। 40 प्रतिशत से कम प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण का विश्लेषण

संक्रमण का विश्लेषण एक प्रकार का दबाव परीक्षण होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम राउंड बाई राउंड या अनुक्रमिक (सीक्वेंशियल) अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूपता संक्रामकता, जिसे अब फरफाइन (2003) से बेहतर जाना जाता है, का पता लगाया जा सके। यदि i बैंक से प्रारंभ करें जो 0 समय पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उन्हें $Dq, q = 1, 2, \dots$ के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रमण विश्लेषण

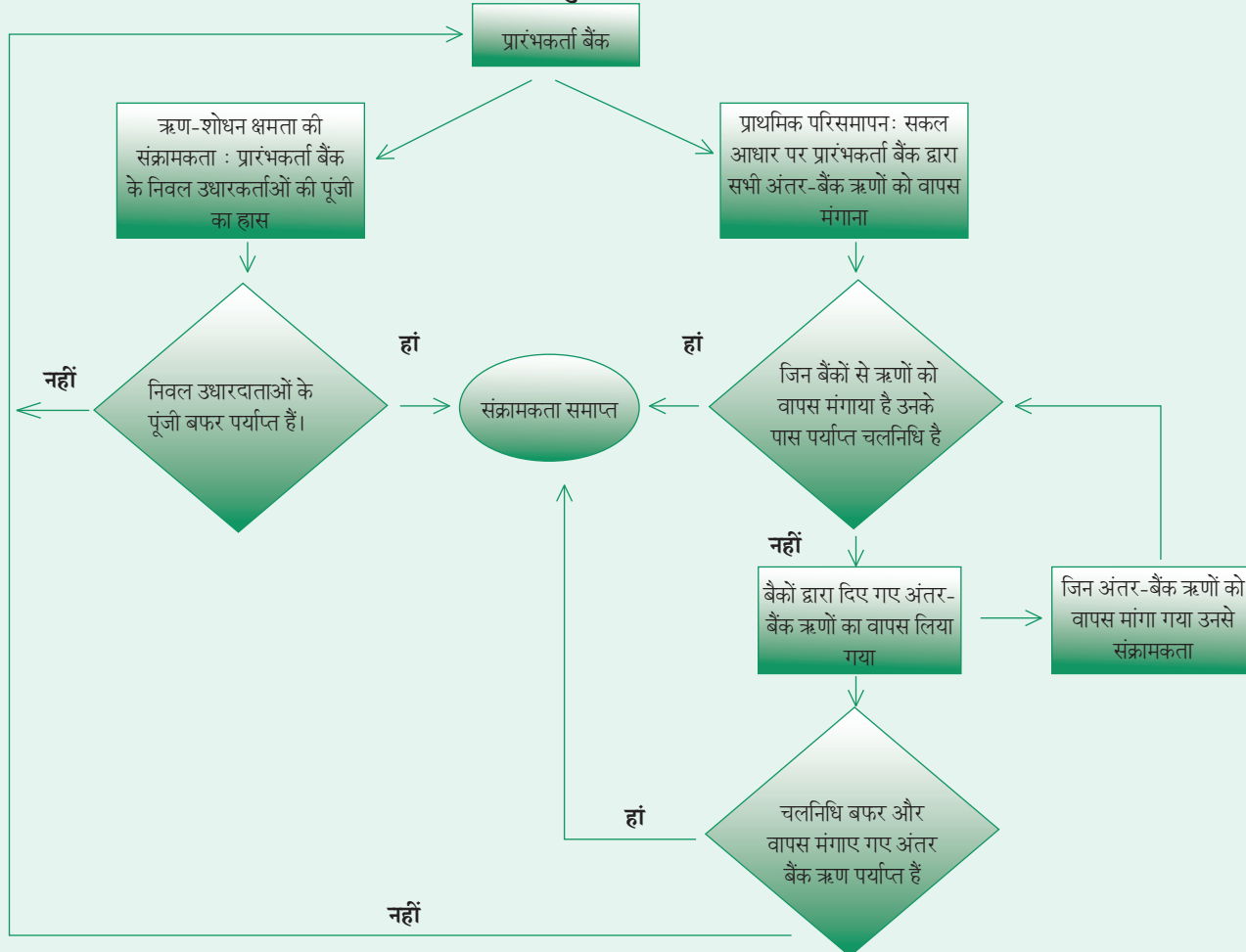
जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रमण विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रमण विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान व्यक्त करता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोजर के संबंध में किया जाता है। एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल होते हैं। इस विश्लेषण का मूलभूत आकलन यह होता है कि किसी बड़े उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए किसी बैंक के चलनिधियुक्त रिजर्व या बफर में पहले तो गिरावट आएगी। चलनिधियुक्त रिजर्व के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं : (क) सीआरएआर का अधिशेष अतिरेक; (ख) एसएलआर का अधिशेष अतिरेक; (ग) उपलब्ध मार्जिनल स्थायी सुविधा और (घ) उपलब्ध निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आगे कोई और संक्रमण नहीं होता है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो तब बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण होता है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य कहा जा सकता है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बच गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रमण हो सकता है जिससे अन्य बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा आकलन यह किया गया है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान के अनुसार, प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा)।

संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता का विश्लेषण

औसतन किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल ऋण प्रदान करने की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधार की स्थितियां -दोनों ही होती हैं। इस प्रकार किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया है:

किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना गया कि प्रारंभकर्ता बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात् यह निश्चित रूप से दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। उसी समय, यह अपनी आस्तियों को भी बेचना प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो यह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन प्रक्रिया एक चलनिधि संकट उत्पन्न करती है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मंगाना प्रारंभ कर देता है।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूंजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर जाते हैं और वे अपने से बाहर दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नया संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार के उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त होती है वे भी आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेते हैं। परंतु कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मंगाते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस मांगने की प्रक्रिया से वे पुनः एक नया संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं।

ऋणशोधन और चलनिधि दोनों ही ओर से संक्रामकता तभी रुक पाएगी/स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली हानि/आघातों को पूर्णतः अवशोषित कर सके और भविष्य में कोई विफलताएं न हों।